राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २३वां दिवस [संख्या १

शुक्रवार, दिनांक १४ मार्च, १९६४

(विधान सभा की बैठक म.पू. ८ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ (वापिस लेना)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा क्यों करने की आवश्यकता पड़ी यह भी माननीय मंत्री बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक १९६३ में प्रस्तुत किया था और उस समय यह पारित नहीं किया जा सका। उसके बाद राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आगई और जिन मुद्दों को इस बिल में इनकारपोरेट किया जाना था, उस संबन्ध में रेवेन्यू लॉज कमीशन की राय मिल गई। साथ ही साथ कुछ और भी मुद्दे थे, जिनको जल्दी ही पारित करने की जरूरत थी इस वजह से इन मुद्दों को रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर और दूसरे आवश्यक मुद्दों को इनकोरपोरेट करते हुए एक बिल अलग से तैयार किया है जो सदन में परसों इन्ट्रोड्यूस किया जायगा। जो प्रावधान उन रिकमन्डेशन्स में हैं उनको उसमें इन्ट्रोड्यूस कर लिया गया है उनकी सम्मति के आधार पर। इसलिये इस बिल की आवश्यकता नहीं रहती है। वह बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी संशोधन विधेयक, १९६३ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

कार्य-विवरण से शब्द निकालने संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं सूचित कर दूं कि मुझे एक प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसे माननीय सदस्य

Page No. 2

(श्री अध्यक्ष)
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत करने की आज्ञा चाही है। प्रस्ताव इस प्रकार है :

"दिनांक २ मार्च, १९६४ को श्री मानसिंह महार, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने भाषण में प्रयुक्त जो शब्द "डाक्टरों के तबादले आप करते हैं राजस्थान में वे आप पैसा लेकर करते हैं" तथा इस प्रकार के शब्द कार्यवाही में प्रयुक्त हुए हैं वे तथा इसी प्रकार ६ मार्च, १९६३ के भाषण में भी प्रयुक्त हुए हैं वे सब सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जावें।"

मैं औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखने के स्थान पर माननीय सदस्यों की एक सामान्य धारणा जो इस पर हो, वह जानना चाहूंगा और इसके बाद किस तरह से इसको निरस्त करने की कार्यवाही की जाय, इस बारे में निर्णय किया जावेगा। क्या माननीय सदस्यों की यह राय है कि ये शब्द सदन की कार्यवाही में से निरस्त कर दिये जावें ?

कुछ माननीय सदस्य: निकाल दिये जावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो मोशन या जो क्वेश्चन आफ प्रिविलेज उठाने के सम्बन्ध में मोशन मैंने दिया था उसके सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई थी और इसके बाद यह सवाल आया कि इसमें अमेन्डमेन्ट किये जा सकते हैं इस वजह से आज इसको रखा। अमेन्डमेन्ट अब नहीं आकर के एक नया ही प्रस्ताव माननीय य ने सदन के सम्मुख रक्खा है और उसके सम्बन्ध में चर्चा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मेरी ओर से रखा गया था या जो क्वेश्चन आफ प्रिविलेज मेरी ओर से उठाया गया था वह बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन उससे कन्ट्राडिक्टरी है और साथ ही साथ जब कि एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है और जिन माननीय सदस्य के सम्बन्ध में यह सारी बात कही गई थी वे उस को हर्ट करती हैं और वे समझते हैं कि यह मेरे साथ अच्छी बात नहीं है, और मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है, उसे मैं समझता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो उसको हाउस के सामने उठाना और उसके सम्बन्ध में निर्णय लेना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी आधार पर वह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही गई थी इसलिये जो आपने यह प्रस्ताव शब्दों को विलोपित करने का रखा है उससे मेरे प्रस्ताव की मंशा पूरी नहीं होती है इसलिये मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव यह रखा है वह मुझे मान्य नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने अभी रखा है उस सम्बन्ध में जहां तक मैं समझता हूं वह काफी सोच समझ कर रखा गया है और उचित है। माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रिविलेज का मोशन कल रखा था उस सम्बन्ध में आगे जाकर क्या परिस्थितियां होंगी किस तरह से वह आगे बढ पायेगा,

(श्री मुरलीधर व्यास)
इस तरह के मतभेद सबके दिमागों में हैं। और वे परिस्थितियां आगे किस तरह से कार्यान्वित हो सकती हैं, उनसे क्या नई चीजें कायम होंगी, यह भी सोचने की बात है। किस कन्टेक्ट्स में कोई यहां किसी व्यक्ति के लिये क्या बात कहता है उसके पीछे क्या क्या बातें हैं वे अगर निर्णय करने के वक्त पूरी-पूरी सामने नहीं आतीं तो फिर उसका मतलब भी किसी भी हालत में न्याय के दरवाजे तक नहीं आ सकता। तो इसलिये हमने जब इस पर सोचा कि मंत्री महोदय जब कि सिर्फ उतनी ही पंक्तियां रखना चाहते हैं और उसकी पृष्ठ भूमि और गहराई में जाना नहीं चाहते तो उसका नतीजा ठीक ढंग से नहीं निकल सकता। तो इसलिये बीच का मार्ग हमें निकालना चाहिये कि दोनों के ही आत्म-सम्मान को ठेस न लगे और मामला सही तरीके से हल हो जाय।

तो इसलिये जैसा कहा गया कि इस पर अमेन्डमेन्ट आता और उस पर विचार होता तो अच्छा होता। हम भी मानते हैं इसे। परन्तु इसके भी लाने में बहुत विचारों का यहां मतभेद रहता और उससे भी ठीक नतीजा नहीं निकल सकता था।

मै चाहता हूं कि इस मामले को व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं बनाया जाय, हमें तो इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि इसका आगे का नतीजा किस तरह से कहां तक कैसा होगा। और उसको देखकर यह सोचें कि कोई ऐसा बीच का रास्ता भी निकल सकता है या नहीं कि जिसके जरिये सम्बन्धित व्यक्तियों को भी किसी जरिये से किसी भी प्रकार यह भी भान न हो कि मेरे आत्मसम्मान को धक्का लगा है। तो इसको देखते हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और इस सही दिशा में प्रयत्न किया हैं वह सराहनीय है।

आखिर हम एक ही सदन में बैठने वाले सदस्य हैं। हो सकता है कि भाषा के दृष्टिकोण से किसी को कोई चीज बुरी लग जाती है। कई भाषण इस तरह के यहां होते है, परन्तु कभी किसी को बहुत सीरियसली ले लिया जाता है और कभी नहीं लिया जाता है। तो जहां तक किसी की इन्टीग्रिटी पर शक करने का सवाल है वह इसमें नहीं होता। पर किस कन्टैक्ट्स में कौनसी बात कही गई यह देखा जाय तो अच्छी बात होती है।

तो इस मामले में जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखना चाहा हैं उसमें एक इस प्रकार की बात है कि जिसमें किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगेगी और सही दिशा में यह कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे शब्द कार्यवाही में से निकाल दें। तो वस्तुस्थिति हमारे दृष्टिकोण से ऐसी है। इस पर आप विचार करके निर्णय दें तो अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में माननीय उप-मन्त्री जी ने जो यहां सदन में अभी अपने विचार रक्खे, उसके द्वारा तो उनके प्रस्ताव की मंशा बिल्कुल बेकार हो जाती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। यह सही है कि मैंने उनके प्रस्ताव में संशोधन के रूप में इसे नहीं रक्खा है।

वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम २९८ के तहत स्वयं आसन को इस प्रकार के अधिकार हैं कि वह सदन में कोई शब्द जो इस प्रकार का कहा गया हो व किसी प्रकार से ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया हो जो अनपार्लियामेंटरी, डेरोगेटरी या डेकोरम के खिलाफ हो, सदन की कार्यवाही में से निकाल दें। ऐसे शब्द और भाषा के प्रयोग निकाले गये हैं भूतकाल में चाहे उन पर खेद प्रकट किया गया हो या नहीं, शब्दों को या उस भाषा के प्रयोग को वापिस लिया गया हो या नहीं। अभी कुछ दिनों पूर्व श्री मोहनलाल सारस्वत बोल रहे थे और वे कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोल गये जिनको वे वापिस लेने को तैयार नहीं हुये, तो आसन ने स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन शब्दों को कार्यवाही में से निकाल दिया था। तो यह अधिकार तो स्वयं आसन को प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग आसन उस समय भी कर सकता था और आज भी कर सकता है। यह आसन का एब्सोल्युट डिस्क्रीशन है जिसका उपयोग मैं समझता हूं, वे कर सकते हैं और आज्ञा इस प्रकार की दे सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यह मामला सदन के सामने अब आ गया हैं और कार्यवाही के सारांश के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया और सदन में वह प्रश्न विचाराधीन है, इसलिए मैंने स्वयं ने यद्यपि आसन से कल भी प्रार्थना की थी, इन सारे ऐसे शब्दों को निकाल दिया जाये जो आपत्तिजनक हों इस कार्यवाही में से। पर फिर भी चूंकि एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत हो चुका था इसलिए मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह उचित समझा कि इस सम्बन्ध में सबस्टेन्टिव मोशन के रूप में एक चीज पेश करदी जावे और सदन में वह चीज आ जावे। इन सारी परिस्थितियों पर विचार करके बिना ज्यादा इस बहस में गये, बिना सदन का अधिक समय खराब किये, यह मोशन ब्रीच आफ प्रिविलेज का बनता है या नहीं उस सारे मसले की बहस में गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया है इन सारे शब्दों को कार्यवाही के सारांश में से निकाल दिया जाय जो कि आपत्तिजनक है उससे मैं सहमत हूं। जो भी कार्यवाही में चीज आई है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यवाही के सारांश में से शब्दों को निकाल देना भी काफी बडी चीज होती है। हर चीजें कार्यवाही में से नहीं निकाली जातीं इसलिए यह कोई चीज छोटी हो ऐसी बात नहीं हैं। कई मेम्बर सदन में इस प्रकार के शब्द बोले हैं और उनको निकाला गया है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई मेम्बर सदन में बोले और कई बार वैसी ही भाषा का प्रयोग करे और दसियों बार उनके शब्दों को हाउस की प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय, तो पढ़ने वाले लोगों पर उसका एक असर पड सकता है। वह भी एक प्रकार का पनिशमेंट है, वह भी एक तरह का सेंसर हैं कि यह शब्द बार-बार बोले जाते हैं इसलिए यह एक प्रकार का सेंसर है, it amounts to a censure of the member इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी चीज का कोई न कोई वाया-मीडिया निकालना चाहिए और यदि कोई वाया-मीडिया नहीं निकलता है तो फिर इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बहस होगी इसलिए हम उस मसले पर न जाएं। नहीं तो कल बातें यहां पर माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसाद जी ने भी सदन के एक सदस्य के लिये कहीं और उन्होंने भी और आरोप लगाया।

अब चाहे स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने उसको रिव्युट किया या नहीं, वह सही हो या गलत हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह बात झूठी होती है अगर वह माननीय सदस्य इसके ऊपर प्रिविलेज का मोशन लेकर आयेंगे तो उसको भी रेफर किया जायेगा। इसके अलावा कई प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं और प्रिविलेज कमेटी का कोई डिसिजन ऐसा है कि अगर झूठा भी उत्तर दिया जाये यह सही है कि झूठा उनको उत्तर नहीं देना चाहिए, अगर झूठा उत्तर दिया जायेगा तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन नहीं बनता। वैसे यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। अगर सदन में माननीय सदस्य अपने विचारों का दुरुपयोग करते हैं। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो सदन के अन्दर इस प्रकार की रेप्युटेशन पैदा होती है कि यह सदस्य गलत बातें कहने के आदी हैं। जैसी कि कई सदस्यों के बारे में और माननीय मंत्रियों के बारे में बातें आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के लिए अगर इस प्रकार की भावना सदन में पैदा हो जाती है और सदन के बाहर पैदा हो जाती है तो स्वयं में यह उस माननीय सदस्य के कन्डक्ट पर एक प्रकार का सैन्सर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रिविलेज मोशन पर आगे बहस करें उस बहस में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं उस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उप-मंत्री जी चाहें कि इस सारे मसले पर शांतिपूर्वक बैठ कर विचार लिया जाये तो मुझे आपत्ति नहीं है। हम इसको आगे कभी ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में जल्दी न करें क्योंकि यह मसला बड़ा अहम मसला है अगर एक बार हमने कोई परम्परा डाल दी और आरोप लगाने पर कोई चैलेन्ज कर दे, तो हर झूठा कहने वाला मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जाये यह परम्परा ठीक नहीं है। अगर इस संबंध में कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है और शांतिपूर्वक यह मामला हल हो जाता है तो उसके बारे में भी बैठकर विचार किया जा सकता है।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे बीच का रास्ता इस प्रकार निकल सकता है, उसको स्वीकार करें और माननीय सदस्य ने जो शब्द उस रोज कहे, उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये। अगर फिर भी सद्भावना की अपील के बाद भी उनके कॉन्शस को अपील नहीं किया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो वाद विवाद उठा है उस पर फिर कुछ बैठ कर विचार कर लें। कल जल्दी में सारी की सारी चीज हो गई इसलिए इसको फिर ले सकते हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में अपने कुछ विचार रखे और उस पर कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने दूसरा प्रस्ताव

(श्री फूलचन्द जैन)

उसके ऊपर रखा है कि जो शब्द आपत्तिजनक थे वे प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिये जायें। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ऐसे आपत्तिजनक शब्द जो किसी माननीय सदस्य या मंत्री के चरित्र पर सीधे प्रहार करते हैं और उसके बारे में वे शब्द बारबार माननीय सदस्य जिन्होंने कहे थे वह फिर सदन के अन्दर कहें और इस बात पर जोर दें कि मैं यह कहता हूं कि अगर मुझे मौका दिया जाये तो और भी कई चीजों को साबित करने की कोशिश करूंगा, यानी कई और राज खोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जो शब्द कहे गये हैं उनको सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये, इतना ही काफी नहीं होगा क्योंकि इससे हमारे यहां पर न सिर्फ प्रोसिडिंग्स में ही ये सारी चीजें आई हैं बल्कि उसके साथ ही साथ अखबारों के जरिये और दूसरे जरिये से इस प्रकार का प्रचार हो गया है कि जिससे कोई भी स्वाभिमानी सदस्य या मंत्री इस स्थिति को बरदाश्त नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष, इस सारी स्थिति को जब हम देखते हैं और दूसरी तरफ से अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमको अच्छी और स्वस्थ परम्पराओं को ढालना चाहिये मैं इस विवाद को नही बढ़ाना चाहता हूं। तो इस संबंध में मेरा यह भी निवेदन है कि फिर हमको भी अपनी भाषा पर संयम और संन्तुलन रखना चाहिये। अगर हम अपनी भाषा पर संयम और सन्तुलन नहीं रख सकते और स्वयं इस बात का पालन हीं क रते कि जो कुछ कहा गया है वह स्वस्थ परम्परा के लिए अच्छा नहीं हो सकता उसके लिए मैं अच्छा समझता हूं कि सबसे अधिक सही तरीका यह है जिन माननीय सदस्य ने यह विचार रखे थे वही अपने विचारों को वापिस लेलें। अगर उन शब्दों को वापिस नहीं लेते हैं। अगर वे जोर देते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की स्वस्थ परम्परा के लिए ही यह जरूरी है कि फिर इस प्रकार की स्थिति के अन्दर जो प्रिविलेज का मोशन रखा गया है उसके कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो मुनासिब निर्णय हो वह आप दें। अगर वह प्रिविलेज की संज्ञा में आता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर इसलिए भी जोर देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से बातें कहीं जायें और कह कर के उनका प्रचार किया जाये और फिर जैसी स्थिति बनाना चाहें राजनैतिक या दूसरी तरीके की वह स्थिति बनाई जाकर फिर उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी जाये कि वह शब्द प्रोसिडिंग्स से निकाले जायं तो यह कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति बर्दास्त नहीं कर सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो और कई अवसरों पर यह कहा है कि सदन में जो कुछ बातें कही जायें उनके बारे में पूरी स्थिति, पूरे तथ्य और पूरी प्रमाणिकता के साथ में, पूरी बातें कही जानी चाहिये। लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष के हैं, वे आवेश में आकर कई बार ऐसी बातें कह देते हैं, जो कि स्वाभिमान पर चोट पहुंचाती हैं। परन्तु उसके बावजूद भी कभी-कभी ऐसी स्थिति के अन्दर कि वह प्रिविलेज की संज्ञा में नहीं आ सकता है, इस बात पर कोई रोकथाम

(श्री फूलचन्द जैन)
करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। आज जब हम यह देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति और उग्र रूप धारण करती जा रही है और सीधे आक्षेप लगाये जा रहे हैं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर इसको सख्ती के साथ या प्रिविलेज मोशन ला कर इसको नहीं रोका गया तो यह स्थिति और आगे दूसरे रूप में काफी आ सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जब माननीय सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा है मैं उसे प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं और जिन मंत्री महोदय के विरुद्ध ये बातें कहीं गई हैं उसके लिए चीफ व्हिप जो प्रस्ताव लाये हैं इसके अन्दर कोनसी आपत्ति रह जाती है कि जब खास तौर से इस प्रकार के आरोप है कि जिसमें रिश्वत लेने की बात है, पैसे लेने की बात हैं और वह भी ट्रान्सफर्स आदि के मामलों में ऐसी बातें कहीं जायें जिनसे सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका असर पड़ता है तो उस स्थिति में यही निवेदन करूंगा कि या तो माननीय सदस्य जिन्होने यह बात कही है वह स्वयं जो उन्होने शब्द रखे थे उनको वापिस लें अगर उन शब्दों को वापिस नही लेते हैं तो उस सूरत में जो प्रस्ताव माननीय सतीशचन्द्र जी ने रखा है वह मैं समझता हूं कि इस सारी स्थिति के लिए संतोषजनक नहीं हो सकता और उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाकर और जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के उप-मंत्री ने रखा है जो वाजिब है और किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप किये जाने पर लाया जाना चाहिए और आवश्यक हो जाता है उसके ऊपर आपका निर्णय हो कर आगे कार्यवाही चालू रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है और उस पर उन्होंने यह कहा कि चेयरमैन को २६८ के अन्दर यह अधिकार है कि उन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जा सकता है। परन्तु माननीय अध्यक्षजी, यह परिस्थिति तो कल यानी उसके पूर्व भी जब यह शब्द कहे गये मौजूद थी। चेयर ने यह वाजिब नहीं समझा कि इन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जाय और उसके बारे में ऐसा एक मौका पिछले साल भी आगया था और इतने ही शब्दों में कहा गया था तो चेयर ने रूलिंग दी थी कि ज्यादा मात्रा में शब्द कहे जायं तो एक्सपन्ज करने की आवश्यकता प्रतीत होती ही नहीं। यह माननीय सदस्यों के देखने की चीज है कि किस मौके पर किस तरह के शब्द कहें, उनको ही संयम रखने की आवश्यकता है, और ऐसे शब्द आने वाले लोग पढ़ कर देखेंगे कि माननीय सदस्य ऐसे बोला करते थे। वह भी व्यवस्था आपकी तरफ से दी जा चुकी है।

इसके विपरीत यह चीफ व्हिप ने हमारी तरफ से जो प्रिविलेज मोशन पेश किया है उसके लिए, माननीय अध्यक्षजी, जो भी इसके ऊपर वजूहात हैं और यह Breach of Privilege की तारीफ में आता है कि नहीं आता है उस संज्ञा में और उस पर वाद-विवाद हो और वह प्रिविलेज मोशन की तारीफ में आता है यह देखने की चीज है। उसके रिलेशन में दूसरा यह जो मोशन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बिल्कुल ही कन्ट्राडिक्टरी है और इससे कोई ताल्लुक इसका नहीं है, क्योंकि, माननीय अध्यक्षजी, चेयर की तरफ से साफ तौर से वाद-विवाद होने से पहले माननीय सदस्य से कहा गया था कि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या वे उपयुक्त समझते हैं कि उन शब्दों को वापिस लेना पसन्द करेंगे। परन्तु उसके बावजूद भी उन्होंने फिर साफ शब्दों में कहा था कि यह मेरी आत्मा के खिलाफ चीज है उसको मैं पसन्द नहीं करता और अभी भी इन्सिस्ट करता हूं कि वह बिल्कुल सत्य है और यह मैं कहता हूं कि तीसरी बार रिपीट किया है। यह उनकी स्वयं की धारणा है कि मेरी कॉन्शस को किल नहीं कर सकता। और दूसरे माननीय मंत्री जी का भी यह आग्रह है कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और मेरा जो विशेषाधिकार है उसका हनन है, और जो एक हाई आथोरिटी है, एक मिनिस्टर हैं उनकी भी रेस्पेक्ट है। वह यह समझते हैं कि वह बिल्कुल असत्य है। इसलिए प्रश्न यह आपके सामने नहीं आता है कि इसको एक्सपन्ज किया जाय। ऐसी समस्या नहीं है कि हीट ऑफ पैशन में इन्नोसेन्टली ऐसे शब्द कहे गये हों। उस हालत में इनको एक्सपन्ज किया जा सकता है। वह स्थिति और हो सकती है। यहां दोनों मिनिस्टर और माननीय सदस्य बिल्कुल क्लीयर हैं। इन हालात के अन्दर यह चीज सामने नहीं आ सकती। माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं अगर उनके विचारों में परिवर्तन हुआ हो और वे ऐसा महसूस करें कि इस चीज को साबित नहीं कर सकते हैं और किसी आवेश में आकर उन्होंने यह शब्द कह दिये हों। किन्तु यह परिस्थिति आज भी नहीं है। वे इस बात को इन्सिस्ट करते हैं। दूसरे माननीय सदस्य इसकी वकालत करके कहें तो यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि दोनों तरफ से इसका आग्रह है। इस हालत को देखते हुए इस मुद्दे पर चेयर से दोनों तरफ से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन पर मनन किया जाकर ही रूलिंग दिया जाना मेरे विचार में उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि कई माननीय सदस्य इस बहस में—(श्री ज्वाला-प्रसाद शर्मा के खड़े होने पर) आप अपना स्थान ग्रहण करें। भाग लेना चाहते हैं और जो आज को कार्यवाही रखी है उसमें से काफी समय देना पड़ेगा अगर इसका निराकरण आज ही करना है तो। तो मैं यह उचित समझता हूं कि इस पर विचार करने के लिए कोई और तिथि निर्धारित कर दी जायगी, और आज की जो कार्यवाही निश्चित है उस पर कार्यवाही होगी।

श्री केदारनाथ

(८.३७.म.पू.)

आय-व्ययक (१९६४-६५) पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री केदारनाथ (गंगानगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारी प्लान की जो फिलासफी है उस पर मेरा विश्वास है, प्लान की प्रायोरिटी पर मेरे दिमाग में रिजर्वेशन नहीं है, मगर प्रायोरिटीज को इस तरीके से आर्डर किया है उनके बारे में मतभेद है और साथ ही साथ जो इन्फ्रेन्सेज निकाले गये, जो नतीजे निकाले गये, प्लान के इम्पेक्ट के और उसको यह कह कर कि इसमें शार्टफाल बहुत मार्जिनल है, इसके बारे में मेरा मतभेद है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कामोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी का, आबादी की बढ़ोतरी का असर देखना चाहते हैं, कि आम, कॉमन मैन पर क्या असर पड़ा है, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। कोई भी मजदूर जो राजस्थान केनाल में काम करता है, कोई भी किसान जो खेत में फावड़े से काम

(श्री केदारनाथ)

करता है, कोई भी मजदूर चाहे माइन्स में, चाहे टेक्सटाइल में, चाहे शुगर फैक्ट्री में काम करता है, तो उसमें वह काम करने की शक्ति नहीं है। उससे फावड़ा चलता नहीं है, मजदूर से काम होता नहीं है, क्योंकि पिछले तीन महीनों में कई रातें उसको बिना रोटी के निकालनी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रॉडक्शन कम हुआ तो सरकार को दोषी नहीं ठहराते, अगर बारिश नहीं होने के कारण कम हुआ है हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते–अगर कॉमोडिटीज की कीमतें इसलिये बढी हों। मगर, अध्यक्षजी कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि सरकार चौकस नहीं रही। उसको कीमतों के बढ़ने का मालूम पड़ गया था १९६३ के अप्रेल में, और उसके बाद किसानों की ६० फीसदी फसल मार्केट मे आगई, और उसके बाद यहां सैशन होता है, और माननीय सदस्य हमारी सरकार के ध्यान में यह चीज लाये कि कीमतें बढ़ रही है मगर सरकार के पक्ष की तरफ से जवाब मिलता है कि कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं आई है। हम चौकस हैं। उसके बाद भी अगर कीमतें बढ़ती है और हम एसेन्शियल कॉमोडिटीज् एक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, ईमर्जेन्सी पॉवर्स के तहत आर्डिनेन्स इस्तेमाल नहीं करें, स्टॉकिस्ट्स पर जैसा कि पंजाब सरकार ने किया है, एक्शन न लें, तो मैं सोचता हूं कि इसका नतीजा क्या हुआ कि करोड़ों रुपये उनके पास आगये जिनकी आबादी दो पर्सेन्ट भी नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने हमारी इकनॉमी को ठप्प कर दिया है और इतना पैसा कमा लिया है कि आने वाली तीन डिकेड्स तक उनके पैसे का असर हमारी सियासी चीज पर रहेगा। हमारी सोशियल लाइफ को ठप्प करेंगे, हमारी इकानॉमिक लाइफ को गाइड करेंगे। हम कितनी ही कोशिश करेंगे, कितने ही कानून बनायेंगे, कितनी ही विजीलेन्स रखेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगले तीन डिकेड्स तक उनके पैसे के असर को दूर नहीं कर सकेंगे। दो पर्सेन्ट जो कम्युनिटी है, सारी पोपुलेशन की दो पर्सेन्ट है वह ३० साल तक, चाहे हम कितना ही प्लान डवलपमेंट करें उसके पास इतना काफी पैसा है कि आज भी हमारे समाज और सरकार पर हावी है। मैं सोचता हूं कि इसका सही अन्दाजा लगा कर आने वाले प्लान को हमारी प्रायोरिटी को रिआर्डर करने के लिए हमारे टैक्सेज का इन्सीडेन्स उन लोगों पर पड़े, उनकी प्रॉपर्टी पर पड़े, वैल्थ और इन्कम पर पड़े और मैं सोचता हूं जिन लोगों को उसमें निग्लैक्ट किया है उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाय–कैसे उनका स्टैण्डर्ड आफ लिविंग बढ़े, कैसे उनके साथ इन्साफ करें, ताकि वह डिस्पैरिटी कम हो। इस प्लान को हम यह नही कह सकते हैं कि यह प्लान रिओरियेन्टेड है। अगर किसान तकावी की किश्त नही भर सका, लैण्ड रेवेन्यू नहीं भर सका तो उसका अटैचमेंट हुआ, उसकी क्रॉप का, फसल का, लेकिन एक इन्डस्ट्रियलिस्ट जब बिजली और पानी का पैसा, लोन और एडवान्सेज का पैसा स्टेट फन्ड्स में नहीं देता है तो उसके साथ में रियायत दी जाती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक कल्टीवेटर, एक किसान, अध्यक्ष महोदय, यह मांग करता है कि वह पैसा खर्च करने को तैयार है उसको ट्यूब-वैल की इजाजत और बिजली दी जाय तो उसको बिजली नहीं मिलती है। प्लान में यह शर्त है कि एक गांव की ५ हजार की आबादी हो तो पांच हजार की आबादी तो दूसरी शताब्दी तक नहीं होने की

(श्री केदारनाथ)

है, लेकिन ३ मील की दूरी पर मेन लाइन बिजली की उस गांव से पड़ती है तो बिजली क्यों नहीं मिलती है ?

दूसरी तरफ हम राजस्थान का हाल देखें तो यहां चार बड़े बड़े इन्डस्ट्रियल प्लान्स हैं और उनको बिजलो कितनी दी ? अगर कॉस्ट आफ प्रॉडक्शन एक यूनिट का भी लेते हैं और उनको देते हैं तो हमको गुरेज नहीं होता, लेकिन आपने उनको कॉस्ट आफ प्रॉडक्शन से कम पर दी। उनको दो नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी और २३ लाख रुपया रिबेट का उनको जाता है। मैं उस बात का जिक्र नहीं करता हूं कि इन्डस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर आपने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है और जिनका रिटर्न्स आधा पर्सेन्ट मिला है। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करता कि जिन २ बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टों को आपने पैसा दिया अगर उनके रिटर्न को देखा जाय, समाज की इकानॉमी में उनके कन्ट्रीब्यूशन को देखा जाय, तो वह आधा पर्सेन्ट ही है। मैं कहूंगा कि किसान जिसको आबादी ७२ पर्सेन्ट है, गावों की आबादी ७८ पर्सेन्ट है, लेकिन जिनका किसानी से वास्ता है उनकी आबादी ७२ पर्सेन्ट ही है और जिनका स्टेट की इकानॉमी में कन्ट्रीब्यूशन ४६ पर्सेन्ट है उनको निग्लेक्ट किया है प्लान में, उनको रुइन किया है सरकार ने। उनके लिए कोई भी दृष्टिकोण इस चीज में नहीं है।

आपने सीलिंग फिक्स किया है। मैं सीलिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको फिक्स करते हुए जिस दृष्टिकोण का आपने इंडीकेशन दिया है कि सबसे बड़ा जो किसान है उसकी आमदनी ३००) रुपये आपने रखी है।

३६००) की लिमिट बांधी है आपने शहरों की आबादी पर ३६०० रु० से ऊपर की इन्कम पर इन्कम टैक्स शुरू होता है। ३६०० की लिमिट है १८०० रु० का खर्चा है एक परिवार के लिये १५०) रु० पर-मंथ पड़े। यदि किसी का लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, या इंजिनियरिंग कॉलेज में जोधपुर में पढ़ता है तो उस पर उसको १००) १५०) से कम नहीं खर्च करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कैसे आप लोगों की हालत को ऊंचा उठा सकते हैं। प्लॉन की स्ट्रेजी को लेकर फोर्थ प्लान में आप आशा करते हैं कि हर एक परिवार की आमदनी नेशनल आधार पर कर पायेंगे यानि हर एक की इन्कम १००) माहवार कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप प्लान को प्रून करें। प्लान को कट करने से आप कभी नेशनल इन्कम को नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको प्रून मत करिये, स्केल डाउन मत करिये। २०८ करोड़ से २०३ करोड़ कर रहे हैं। आपके द्वारा प्लान को स्केल डाउन करने से ५ करोड़ का फर्क पड़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान सरकार में लीडरशिप है तो जो हमारे क्लेम्स पेन्डिंग हैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में और पानी व बिजली का झगड़ा पंजाब सरकार से है यदि राजस्थान सरकार की लीडरशिप मजबूत है उसको सेटल कराने में तो मैं नहीं समझता कि प्लान को स्केल-डाउन करने की जरूरत पड़ेगी।

मैं आपके सामने कुछ कोट करना चाहता हूं बारबारा वार्ड जो हमारे बहुत ही वेल-विशर हैं उन्होंने किताब लिखी है "Warning to the waste" article का शीर्षक है और किताब का नाम है "India and the West" उसमें उन्होंने लिखा है:

(श्री केदारनाथ)

Behind the Indian figures and statistics lie the realities of children without bread men without work, women without hope. If these do not lead us to action. the outer form of society may survive. but the inner will have to wither away. Then like the myriad proud civilisations upon which the sentence of the Watchers has already gone forth, we shall be carted off the great stage of world into the dust and debris of history, then to join the melonchaly line of past societies which at the crucial test could not change and advance in time."

ये चीजें वार्निंग के रूप में है। आज तक प्लान का इम्पेक्ट, प्लान के दूसरे फायदे, हमारे डवलपमेंट के फायदे कौनसे सेक्शन्स पर पड़े। हम अपने आपको सुधारें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यदि हमारे राजस्थान की लीडरशिप मजबूत है, तो हमें प्लान को स्केल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसमें कोई शक नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत इण्टेलिजेन्ट हैं, हरएक सब्जेक्ट पर उनका ग्रास्प है। हरएक चीज के प्रोस एण्ड कोन्स को तोलते हुए किसी पोइन्ट को प्रेस करने में वे माहिर हैं सारी बातों के लिये उनका दिमाग बहुत साफ है। लेकिन इम्पलीमेन्टेशन के लिये जिस तरह का ड्राइव चीफ मिनिस्टर में होना चाहिये उस तरह का नहीं है। इसका भी कारण है। वह स्टेट जो १०० साल से बेकवर्ड है वह इनको विरासत में मिली है। उसके वे चीफ मिनिस्टर हैं। वे टैस्ट जिसकी मशीनरी जो राजाओं की गुलाम थी और जिनका दिमाग इस कारण से ठीक नहीं है और उसको वे ठीक ढंग पर लाना चाहें तो जल्दी ला नहीं सकते— स स्टेट के वे चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन मेरा यह दावा है कि आप मजबूती से काम करिये। हमारे क्लेम्स पेन्डिग हैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने उनको तय कराइये। इनमें से दो तीन क्लेम्स बहुत अहमियत के हैं। हमारा पहला क्लेम है कि राजस्थान केनाल को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बना सके। इसके लिये भी आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। केबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया। आप उसको लेकर ऊपर भी गये, कोशिश भी की. पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बारे मे मेरा निवेदन है कि प्लान का जो सीलिंग है, यह खर्चा उसमें दर्ज न हो, सीलिंग के बाहर दर्ज हो। पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है, दर्ज हमारे खाते में होता है। लेकिन आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि सारा खर्चा राजस्थान केनाल का सीलिंग में न दर्ज किया जाय। उससे क्या फायदा होगा? उसका फायदा यह होगा कि हमारे बहुत से डवलपमेंट के कार्य जो प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं आ सकते थे वे आ सकेंगे, प्लान में इन्क्लूड हो जायेंगे। मैं समझता हूं, डिबेट के जवाब में आप इस पर रोशनी डालेंगे।

दूसरी बात पौंग डेम, पॉवर स्टेशन और व्यास प्रोजेक्ट की बात है और पानी का हिस्सा आपने तय कराया, लेकिन बिजली का तय होना है वहां पर ६ लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है जो हमारे गांधीसागर डेम पर के पॉवर स्टेशन से ६ गुना ज्यादा है। यदि पंजाब सरकार २० पर्सेंट से ज्यादा हिस्सा देने को तैयार नहीं है तो हमें ईल्ड नहीं करना चाहिये। आने वाली जन-

(श्री केदारनाथ)

रेशन यह नहीं कहेगी कि आपने कुछ नहीं किया। स्टेट की इकॉनोमी आपके पीछे थी, जनमत आपके पीछे था, राजस्थान की विधान सभा आपके पीछे थी और जनता आपके पीछे है, जो मांग करते हैं कि आप अपने क्लेम को मजबूती के साथ प्रेस करिये और कभी ईल्ड मत करिये।

तीसरी बात घग्घर की है। अखबारों में चर्चा है, १ मार्च को कृषि मंत्री गये थे और पंजाब के मुख्य मंत्री और उनके बीच बातचीत हुई थी इसके बारे में इन्डियन एक्सप्रेस ने अपने व्यूज दिये हैं। मेरे दिमाग में इल्युजन है कि कहीं इग्नोरेन्स के कारण पंजाब सरकार के साथ यह फैसला कर बैठे कि इस ड्रेन को हम जब्त कर सकेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पानी को हम अपने यहां हरगिज जज्ब नहीं कर सकेंगे। पंजाब सरकार हार्ड नट टू क्रेक है। यदि पंजाब में कम्युनिस्ट सरकार होती तो आप कह सकते थे कि हमारी बात नहीं मानते लेकिन पंजाब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सेन्टर में कांग्रेस की गवर्नमेन्ट है और हमारे यहां कांग्रेस की गवर्नमेन्ट है और सभी एक ही प्लान पॉलिसी को मानने वाले हैं, एक ही हाई कमान्ड के बीच में हैं फिर भी आपके क्लेम सैटल नहीं होते इसलिये कि आप कमजोरी दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी कभी ईल्ड नहीं करेंगे राजस्थान की जनता को देखते हुए, हमारी इकानॉमी को देखते हुए और अपने फर्ज को देखते हुए।

तीसरी बात हमारे गंग केनाल की बात है। इसमें शक नहीं कि सन् ५६ में जब एग्रीमेन्ट हुआ था इन्डो पाक वाटर ट्रीटी के नाम से, उस समय हमारी सरकार सोती रही। उन्होंने सोचा होगा कि इसका असर गंग केनाल पर क्या होगा हमारे दूसरी तरफ तो हरियाली रहेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका सर्वनाश हो जायगा, Petal by petal it is going to wither away. आज वहां की हालत क्या है और दो साल पहले वहां की हालत क्या थी, दोनों की हालत में बहुत फर्क है। ईल्ड पर-एकड़ कम हो रही है, टोटल प्रॉडक्शन कम हो रहा है। स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हुआ है। हमारी साइकोलोजी पर, दिमाग पर इसका बुरा असर हुआ है। आज वहां पर डिमोन्स-ट्रेशन्स होते हैं, मीटिंग्ज होती हैं, लोग इसके बारे में सोचते हैं डेपुटेशन्स आते हैं, हमारे माननीय सदस्य जो वहां से चुन कर आये हैं, वे कहते हैं कि आप इसके बारे में कदम उठाइये और अगर नहीं उठायेंगे, तो वहां के किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आपने ईल्ड कर लिया तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इसके अलावा हमारा सूरतगढ़ फार्म है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी मौका मिला है इसे देखने का और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं कि कितनी बड़ी जमीन का हिस्सा है। एशिया का यह सबसे बड़ा फार्म है और वह सेन्टर के हाथ में है। पिछले साल इस फार्म में ३४ लाख रु० का घाटा हुआ था। आज आप वहां की फसल देखिये और आस पास की देखिये, वहां पर पानी की सहूलियत को देखिये, अच्छे से अच्छे खाद और बीज का वहां उपयोग होता है उसको देखिये, अच्छे से अच्छे टेक्निशियन्स वहां पर हैं, अच्छी से अच्छी मशीनरी वहां पर हैं। इन सब के बाद भी वहां का प्रॉडक्शन गिरता है और नुकसान होता है, तो इस सब के पीछे क्या कारण है, यह देखने और गौर करने की बात है। राजस्थान की जमीन जिस ढंग से मांगते हैं

(श्री केदार नाथ)

और उसके बाद उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाय, कुछ लोग वहां आवें हाई सर्कल वाले अपने रिश्तेदारों को वहां पर भेजें–ये सब चीजें हैं जिनके कारण नुकसान होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से इसे अपने हाथ में लेना चाहिये। हमारे हाथ में इसका मैनेजमेन्ट आने पर हम इसकी उन्नति करने के लिये जिम्मेदार होंगे। आप इसको ईल्ड करने जा रहे हैं। ५० हजार एकड़ जमीन देंगे तो यह ठीक नहीं होगा। यह ठीक है कि अमेरिकन पेटर्न पर यह बना है लेकिन इसका इन्तजाम और इसका मुनाफा हमारी राजस्थान सरकार के हाथ में होना चाहिये, चाहे हम छोटे किसानों को बेदखल करें उनको अपनी दूसरी जमीन दें लेकिन हमारी जमीन हमारे पास रहनी चाहिये। हम सेन्टर से रिक्वेस्ट करें कि हमारी इकोनोमी को डवलप करने का सवाल है इसलिये यह हमें दे दिया जाय। हमारी इकोनोमी को डवलपमेन्ट करने का सवाल है, इसलिये लाजिम है कि आपको यह फार्म हाथ में लेना पड़ेगा।

इसी तरह से आपने दो तीन डील और किये हैं और उनमें कमजोरी दिखाई है। जिप्सम की रोयल्टी का सवाल था। मुझे मालूम है कि आज से दो साल पहले एक टन १.०२ नये पैसे मिलते थे पर न मालूम किस कारण से सेन्ट्रल एवार्ड के कारण इस पर रोयल्टी १२ आ० पर-टन कर दी गई। यह आपकी कमजोरी का सवाल है। हमारे यहां के जिप्सम की तरह ही आसाम के ऑइल की रोयल्टी का सवाल था, पर आसाम गवर्नमेन्ट ईल्ड नहीं हुई। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को ईल्ड करना पड़ा। इसी ढंग से और चीजें हैं।

बोर्डर की बात है, मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं कि बोर्डर पर कोई टेन्शन नामक चीज है। मैं यह नहीं कहता कि आप चौकस नहीं हैं और आपके बेटर इक्विपमेन्ट्स वहां के सिपाहियों के पास नहीं हैं। आपने उनको बेटर इक्विपमेन्ट्स दिये हैं। आप चौकस हैं; आप दिनों दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने रोड्स बनाई हैं, और बना भी रहे हैं और दूसरे तरीके भी वहां तरक्की के काम में ला रहे हैं। आपने वहां पर आर. ए. सी. बटेलियन भेज दी है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या हमारी ही जिम्मेदारी है बोर्डर की, क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ? मैं समझता हूं कि बोर्डर की सारी समस्या और खर्च व इन्तजाम की जिम्मेदारी हमारी स्टेट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए और इस बात को मानते हुये कि वहां बोर्डर पर कोई टेन्सन नाम की चीज नहीं होते हुए भी, मेरी यह सलाह काम की है। वहां पर जो लोग रहते हैं वे मार्शियल कौम के हैं। उनकी हालत वहां पर अच्छी नहीं है मगर फिर भी वे देश प्रेम के कारण वहां पर बसे हुए हैं और देश की सेवा करते हैं। वहां पर जमीन से उनको ज्यादा आमदनी नहीं होती क्योंकि वहां पर टीले हैं और इस कारण चम्बल से भी पानी वहां पर नहीं पहुंचता। उनकी आमदनी कम होती है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उनके पास चाहे जो भी जमीन हो उसमें उन लोगों को कम्पेनसेट किया

(श्री केदार नाथ)

जाना चाहिए और रियायतें मिलनी चाहिए। वहां पर वे लोग एक तरह से सोल्जर्स के नाम से काम करेंगे। प्रहरी के नाम से काम करेंगे। बोर्डर पर रहने वाले लोगों को राहत देंगे तो उसका साइक्लोजिकल इफेक्ट बहुत अच्छा होगा और इस बैक ग्राउन्ड को ध्यान में रखते हुए उनको सहायता देना ठीक होगा।

इसके अलावा हमारे यहां पर रिफाइनरीज और डिस्टीलरीज हैं। शराब बनाने में चार साल से यू. पी. से झगड़ा चल रहा है। आज भी वह झगड़ा चल रहा है और आपस में पत्र व्यवहार चल रहा है। अभी तक उसका हल नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि ऐसे और भी कई मसले हैं जिनका हल नहीं हुआ है। इसलिए इनका हल जल्दी होना चाहिए। यह नहीं कि यह मामला चलता रहे। इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि हमारी इन्डस्ट्रीज आपके हाथ में हों।

इसके अलावा हर एक पॉलिटिकल एक्टीविटीज हमारे पर लाद दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जब आप शासन करते हैं तो हमें उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए मगर यह भी नहीं हो कि यदि किसी को राज्य सभा के लिए कैन्डीडेट भेजना हो तो वह यहां का न हो और कोई बाहर का हो। आपको राज्य सभा में कैन्डीडेट भेजने की स्वतन्त्रता है मगर इसके लिये ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका रिफ्लेक्शन उसकी पॉलिटिकल लाइफ पर पड़ता हो। क्या राजस्थान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने Liberation Struggle में फाइट किया हो, या जीनियस न हो या अच्छा सोशल वर्कर न हो जिसके कारण आपने यहां से राज्य सभा के लिए सेन्टर के होम मिनिस्टर के पी. ए. को राज्य सभा के लिए खड़ा किया है जो यहां राजस्थान में अपना कोई वकत नहीं रखता है। अगर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति होता, किसी पार्टी का व्यक्ति होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं था। आप कहते हैं कि यह तो पार्टी का प्रश्न है। मगर यह पार्टी का प्रश्न नहीं है यह सिद्धान्त का प्रश्न है। अगर कोई हरिजन को आप चुन लेते या किसी जागीरदार को भी चुन लिया होता तो भी उसका कोई दुःख नहीं होता। मगर स्टेट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने हमारे राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है उसका हमारे यहां डेमोक्रेसी में लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो और आगे बढ़े तो आप दूसरे लोगों से पूछे बिना अपनी मर्जी से इस प्रकार के मामलों में फैसला नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं सोचता कि यह आपके लिये कोई शोभा की बात है। यह बात मैंने आपके सामने रखी है, अध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन बातों को रखने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आती है। I will take only five minutes more.

(विराम)

अब मैं बजट प्रपोजल पर आता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि राजाओं के समय में जिस समय बजट बनता था उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा राजा-रानियों के पीछे लगा हुआ रहता था उसका इसमें अभाव है। जो आज तक निगलेक्टेड सेक्शन्स थे उनकी तरफ आपने ध्यान दिया और उनको रिलीफ दिया और टैक्स लगाते वक्त ध्यान रखा इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

Page No. 15

(श्री केदार नाथ)

It is never too late to be wise. मैं यह सोचता हूं कि कांग्रेस ने यह जो फैसला किया है उसको अगर आयन्दा नहीं बदला गया और मजबूती से आपने अपने फैसलों को नहीं बदला, प्राइसेज को स्टेबिलाइज नहीं किया, तो मैं यह कहूंगा कि आप जिन्दा रहें। आपको कोई चेलेंज नहीं करता। आज की हालत में पाकिस्तान और चाइना की इकोनोमी, ऐसी है कि यहां रूल कर लेंगे।

आपने कर्मचारियों को जो ५ रु० माहवार का रिलीफ दिया है उसमें कोई मोरल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई बेसिस नहीं है पर फिर भी आपने उनको यह जो रिलीफ दिया है वह हेपी डिपार्चर है। दूसरी तरफ आपने जो टेक्सों के मामले में अपना यह डाइरेक्शन बदला है यह न्यू आउट लुक और न्यू डिपार्चर है। मैं समझता हूं कि कभी भी आप Evaluation Commission मुकर्रर करें। तो राजस्थान में कौन से लोग निगलेक्टेड रहे हैं और किन को आयन्दा रिलीफ मिले, हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, सेक्शन वाइज स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग के जिनको आपके सामने पेश करता। मैं आपके सामने एक प्लानिंग की रिपोर्ट जो उपलब्ध है, छपी है, पेश करता हूं, उसमें वे लिखते हैं।

30% of the population have 10% of the national wealth.

10% of the population have 36% of the national wealth, higher than that of America and U.K.

60% of people live below the minimum subsistence level.

30% of people live on Rs. 15 per month.

20% of people live on an income of Rs. 12 per month."

उसमें लास्ट लफ्ज ये हैं : "Upto 1991, 30 per cent of the population will live below subsistence level."

अगर आपके प्लान की यही साइज रही, यही स्टेटस रहा तो मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक्सटेन-सिव ग्रुप काम कर रहे थे, हमारे यहां राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ पोपूलेशन हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से ज्यादा रफ्तार से हैं। हमारे यहां पर राइज एन्ड ग्रोथ की पर्सेन्टेज २६.१ है और इण्डिया में २१.०० पर्सेन्ट है इसलिये कौन से सेक्शन की प्रोग्रेस पर यह टेक्स करेगी, कौनसे सेक्शन की इन्कम को और कौनसे सेक्शन को यह रिलीफ देगी ? इसके लिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को दो जोन बनाने चाहिए। एक तो वह जहां रूरल इकोनोमी

(श्री केदारनाथ)

में परमानेन्टली इरिगेशन होता है वहां का मोड ऑफ डवलपमेंट अलग है, वहां के रेवेन्यू लॉज और लेजिसलेशन अलग हैं, कल्चर अलग है, मोड ऑफ लिविंग अलग होगा। और एक वह जोन जहां पर परमानेन्ट इरिगेशन नहीं होता। इनका अलग जोन बना कर मोड़ दें।

तीसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं वह यह कि ऐसे इलाकों की बाबत ऐसा नहीं हो कि फरटीलाइजर इन्डस्ट्रीज को खोलने का आश्वासन दें और

(६.०० म० पू०)

यह कन्सेशन्स कागज में दे दें और कागज में गायब हो जांय। कहीं ऐसा न हो कि यहां से उठाकर बीकानेर ले जाय। यह खुशी की बात है, लेकिन राजस्थान के तमाम हिस्सों में रीजनल इम्बेलेन्स की बात आप करते हैं। आप नहीं चाहते, हर इलाके में मिनिमम पाइन्ट ऑफ डवलपमेंट हो। मैं सोचता हूं, आज तक जो आपने किया उसका जस्टीफिकेशन हो सकता है, पर आयन्दा आप करें उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आखिरी लफ्ज कहता हूं, जो फरदर डिपार्चर किया, जो नया मोड़ है उसका मैं स्वागत करता हूं एक विश्वास और कन्डीशन के ऊपर कि २५ हजार का सरचार्ज है किसानों के ऊपर, उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है....

कुछ माननीय सदस्य: २५ लाख !

श्री केदारनाथ: २५ लाख का सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर बहुत बड़ा इन्सीडेंस है और साइकलोजिकल इफेक्ट रूरल लाइफ पर बहुत बड़ा है। आप सबसे पहले इसे बन्द कर सकते हैं।

तो जो बातें मैंने रखी हैं वे सेन्टर के सामने रख कर, अपने क्लेम मनवा कर आपको बहुत पैसा मिलेगा। मैं सोचता हूं, आज की हालत में जो ढांचा लाये हैं, इसमें यह न्याय का तकाजा है, न्याय यह मांग करता है कि क्योंकि किसान ने प्रॉडक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, स्टेट इकोनोमी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, वे आपके साथ रहे हैं और आपके लिए उन्होंने फूड का प्रॉडक्शन किया है– इन सारी बातों को देखते हुए, पॉलिटिकल, सोशल और इकानामिकल आसपेक्ट्स का विचार करते हुए इस सरचार्ज को हटा दें, यह मेरी मांग है।

दूसरी बात, आपने पांच रुपये का रिलीफ दिया है, इसमें खुशी है। लेकिन जो मजदूर फैक्ट्री में, कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए जैसा मुख्य मंत्री ने कहा था, मजदूरों के द्वारा प्रॉडक्शन न हो तो कोई फैक्ट्री कामयाब नहीं हो सकती। यह स्लोगन है, यह हमारे लिए फर्ज के रूप में बदल जाय तो क्या हिम्मत है इन्टरप्रेन्योर, इन्डस्ट्रियलिस्ट की कि वे आपका कहना न मानें। उनको आज मालूम है कि जो आज बात कही गई है आहिस्ता आहिस्ता वह ठंडी पड़ जायगी। It will catch cold; इस बात को मानते हैं। उनके दिमाग में एप्रीहेन्शन हो भय हो, कि मुख्य मंत्री की स्पीच के बाद, ऐलान के बाद नहीं माना तो लाजिमी एक्शन होगा वह यह कि कन्सेशन बन्द हो जायगा। तो मैं नहीं समझता कि पांच सात रुपये का रिलीफ इस डीयरनेस अलाउन्स के

(श्री केदारनाथ)

रूप में न दें ।

आखिरी बात यह कहते हुए मैं मेरी बात आपके सामने निवेदन कर देता हूं:—

"This brings an automatic bounty of goodwill. But much sustained work and firmness of purpos will be needed to weed out the pockets of privilege and fraud in the key sectors of the political and economic life."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बहस में हिस्सा ले चुके हैं और बहुत सैद्धान्तिक भाषण इस बजट पर हो चुके हैं। कल भी स्वतंत्र पार्टी की तरफ से दो भाषण और दो भाषण कांग्रेस की तरफ से प्लान के विवेचन और बजट के सिद्धान्तों पर हुए। आज भी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से बजट का विश्लेषण किया। वित्त मंत्री ने इस बजट को पैडेस्ट्रियन बजट कहा है। मैं किसी भी विश्लेषण के आधार पर इस बजट को पैडेस्ट्रियन बजट नहीं मान सकता। मैं समझता हूं कि पैडेस्ट्रियन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शायद पीपुल्स बजट शब्द इस्तेमाल करने से भय लगने के कारण उसके स्थान पर पैडेस्ट्रियन शब्द को इस्तेमाल किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पीपुल्स बजट या पैडेस्ट्रियन बजट नाम की कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ टैक्सेज का बोझ न डालना, टैक्सेज का बढ़ाना, नये टैक्स जनता पर न लगाना पैडेस्ट्रियन बजट के लिए काफी नहीं हैं। जो पुराने टैक्स लगे हुए हैं, आपकी जनता पर वह उन पर बहुत बड़ा बोझ है। उनको भी आप राजस्थान की परिस्थियों को देखते हुए कम नहीं कर सके तो आप यह नहीं कह सकते कि यह पीपुल्स बजट है या पैडेस्ट्रियन बजट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो भी नये टैक्सेज लगाये हैं उनका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान का प्रिविलेज सैक्टर है उसक एक अंश, उसका एक फीसदी भी इन टैक्स प्रपोजल्स से नहीं छुआ है और इन टैक्सेज से राजस्थान की प्रिविलेज क्लासेज पर असर नहीं होता है, इसलिए बजट का जो मूल सिद्धान्त है उससे मेरा मतभेद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की छाया और राइजिंग प्राइसेज की छाया में जो बजट लाये हैं, इस सारी पृष्ठभूमि में जो चेंजेज इस बजट के द्वारा होनी चाहिए थी, जिन नीतियों की घोषणा होनी चाहिए थी, उन नीतियों की घोषणा बजट से नहीं हुई। राजस्थान में प्राइसेज बढ़ रही हैं, सारे देश में प्राइसेज बढ़ रही हैं, बहुत लम्बी चौड़ी बहस इस बात पर हुई। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि प्राइस-राइज के सम्बन्ध में जो स्टेप्स लिये गये हैं, उनसे इस सदन को आगाह किया गया है जो मौके पर यह सदन समझ जायगा। इस बजट स्पीच के पहले किस दिन आगाह किया गया है कि क्या कदम उठाये हैं? गवर्नर ने जरूर कहा कि हमने प्राइसेज को बढ़ने से रोकने के लिए बारह सौ दुकानें राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सस्ते अनाज की खोल दी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बारह सौ दुकानें राजस्थान में खोलने से प्राइस राइज नहीं रोक सकते। आपके पड़ौसी प्रान्त पंजाब में छः हजार दुकानें खोली हैं, जिसकी लम्बाई चौड़ाई राजस्थान से कम है। उस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्टेट में अन्न की चीप ग्रेन शॉप्स ६ हजार खोली हैं, और आपने १२०० खोली – इसके बावजूद आपका दावा है कि आपने सक्षम कदम उठाये हैं। कल की बहस में हमने प्रश्न उठाया था कि क्या राजस्थान में प्रोफिटियरिंग को रोकने के लिए कानून बनाया ? आपके पास फूड ग्रेन्स के लाइसेन्स देने का कानूनी प्रावधान है उसका कोई उपयोग नहीं किया। आपने होल सेल और रटेल सेल में प्रोफिट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया। डी. आई. आर. के तहत जो कानूनी प्रावधान है उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। और प्राइस राइज को एक स्पैक्टेटर की तरह देखते रहे हैं, कि किस तरह होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, इस सदन में ६ सितम्बर को डिबेट हुई कि अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने एक दृष्टि से यह कहा कि हम उसको रोकेंगे, हमने विजिलेन्स कमेटी जिले जिले में बना दी हैं, सरकार जागरूक है, सरकार सक्षम कदम इस सम्बन्ध में उठायेगी। आप विश्वास रखिये, प्राइसेज नहीं बढ़ने देंगे। विरोधी दल आगाह नहीं करता तो भी आप कह सकते थे। लेकिन आधा घंटा की बहस के बाद. मन्त्री महोदय के जवाब के बाद भी सक्षम कदम नहीं उठाये गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी बजट स्पीच में यह घोषणा नहीं है कि राजस्थान में भविष्य में प्राइस राइज नहीं होंगी, जो प्राइस एबनार्मल ढंग से बढ़ गई हैं उनको नीचे लाने का यत्न किया जायगा। और इस सम्बन्ध में लिए जाने वाले कदमों का कोई लेशमात्र जिक्र नहीं है, इस समस्या का आपके बजट में कोई समाधान नहीं है।

आपके बजट में जितनी अलग अलग मदे दी गई हैं, उनमें कहा गया है कि इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। आप पर आरोप लगाया गया प्लान की प्रायोरिटी के सम्बन्ध में। आपने कौनसी खुलासा बात की, आप कौनसी बात मंजूर करते हैं प्लान प्रायोरिटी के सम्बन्ध में ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लान प्रायोरिटी को स्वतन्त्र पार्टी चैलेंज करे या न करे, प्लान में भरोसा हो या नहीं हो लेकिन इस सदन के बहुमत का प्लान में, इकानामिक प्लान में भरोसा है। लेकिन राजस्थान के प्लान में जनता की अत्यधिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्रायोरिटी देने के अलावा आप निगलेक्ट करते जा रहे हैं, उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। मैं एक छोटे से प्रश्न को लेता हूं, राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर की प्रोबलम को लेता हूं, उसके लिए आपने कितना प्रावधान किया है ? उसके लिए बीस लाख का प्रावधान किया है। आप कहते हैं कि बीस गावों में स्वच्छ पीने के पानी की समस्या को हल कर दिया जायगा और पांच वर्षों में सौ गांवों में इस समस्या को हल कर दिया जायगा। इस रेट से चलते हैं तो राजस्थान में हजारों गांव हैं, न जाने कितने वर्ष में, कितने प्लान के द्वारा इस स्वच्छ पीने के पानी की समस्या को हल करेंगे ? दो करोड़ रुपया आपने रखा है प्लान के अन्दर, २३६ करोड़ के प्लान मे केवल २ करोड़ रुपया

(श्री मानकचन्द सुराणा)

रखा है लेकिन जो ट्रेन्ड है उससे ६० लाख रुपया खर्च कर पायेंगे और आने वाले साल में बीस लाख रुपये की स्पीड से खर्च करदें तो एक करोड़ रुपया खर्च करेंगे। बारह करोड़ तेरह करोड़ की मांग को ६२ के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर साहब ने सैन्टर को भेजा था कि १३ करोड़ से ग्रामों में पीने के पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी एक दिन एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री ने कहा कि इस वाटर सप्लाई स्कीम के अन्दर सैन्टर का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसको प्लान सीलिंग में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद प्लान में पैसा मिल जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पार्लियामेंट में माननीय सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर के जवाब में हिन्दुस्तान सरकार की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुशीला नायर ने साफ तौर से कहा कि हमने राजस्थान सरकार को कहा कि आप १ करोड़ रुपया राजस्थान के रूरल एरिया को वाटर सप्लाई करने के लिए रखिये पर उन्होंने डिस्कशन में ५० लाख कर दिया और फिर बाद में उसे काट कर २० लाख कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ५ साल के अर्से में पीने के स्वच्छ पानी की समस्या का हल नहीं कर सके तो गावों में रहने वाले लोग महसूस नहीं कर सकते कि इस देश में आजादी आई है। किसी तरह का हमारे देश में प्लान्ड डवलपमेंट हो रहा है, या प्लान्ड-वे में हमारे देश का अर्थ-तन्त्र चलाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि प्लान की किसी भी प्रीयोरिटी को कट कर दीजिये, किसी भी मेजर प्रोजेक्ट को कट कर दीजिये पर पीने के पानी की समस्या को बिदिन थ्री ईयर्स आपको हल करना चाहिये। एक करोड़ खर्च करने के लिए भारत सरकार कहती है तो आप २ करोड़ खर्च कीजिये। भारत सरकार से आपको इसके लिए ५० प्रतिशत एड मिलती है वह कोई लोन नहीं है। ५० प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, एड मिलती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्लान में ड्रिंकिंग वाटर की प्रोबलम पर जिस तरह का रवैया राजस्थान सरकार द्वारा अख्तियार किया गया है, उसी तरह का रवैया राजस्थान की और प्रोबलम्स पर राजस्थान सरकार द्वारा अख्तियार किया गया है।

इन्डस्ट्रियल टेम्पो हमारे राजस्थान में बढ़ रहा है–इस प्रकार के मुख्य मंत्रीजी के भाषण आते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थर्ड प्लान में इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट का कोई टैम्पो राजस्थान में नहीं बना है। पूंजीपतियों को जितने लाईसेन्स दिये हैं उनमें २५, ३० प्रतिशत ऐसे लाइसेंसेज होंगे जिनका कोई काम शुरू नही किया गया है। स्वतन्त्र पार्टी कहती है कि प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा दिया जाय। इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर से किया जाय या पब्लिक सेक्टर से इस बात की कोई बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि राजस्थान के इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाय? न तो कोई राजस्थान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट करने पर कोई रोक लगाई है जिससे कि स्वतन्त्र पार्टी को यह मांग करनी पड़े कि प्राइवेट सेक्टर को मारा जा रहा है। सारे राजस्थान में आज प्राइवेट सेक्टर का इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन में कुल कन्ट्रीब्यूशन कितना है? आपने

(श्री मानिकचन्द सुराण.)

आंकड़े दिये हैं। १.४८ प्रतिशत हमारा टोटल प्रोडक्शन है। उसमें प्राइवेट इन्डस्ट्रीज का कन्ट्रीब्यूशन डेढ़ प्रतिशत है। सारे हिन्दुस्तान का इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन ८ प्रतिशत है। राजस्थान में डेढ़ प्रतिशत है। पिछले साल के आंकड़ों को देखा जाय तो वह डेढ़ प्रतिशत से घट कर सवा प्रतिशत पर आ गया है और राजस्थान के पिछले तीन वर्षों का सब मिला कर एवरेज निकाला जाय तो वह एक प्रतिशत भी नहीं आता, ०.१ आता है। तो फिर कहां राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट का टेम्पो बन रहा है ? यह सब देखने से साफ जाहिर होता है कि इन्डस्ट्रीज के विकास का कोई टेम्पो राजस्थान में नहीं बन रहा है। कोर ऑफ दी प्लान पर आपने २९२ लाख रुपया रखा है, ३ करोड़ रखा होगा पर इससे राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल रिवोल्यूशन शुरू हो जायगा इस तरह की धारणा बिल्कुल गलत है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान प्रोविजन रखा है, जो रोजी पिक्चर हमारी सरकार पेश करना चाहती है, उससे हम उस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। १२०० इन्डस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, उनमें ४४ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि थर्ड प्लान में जितना इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट हम करना चाहते थे, नहीं कर सके, जितना एम्फेसिस इन्डस्ट्रीज पर देना चाहिये था वह नहीं दे सके। बहुत विश्लेषण के बाद हिन्दुस्तान सरकार ने स्वीकार किया है कि इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में सरप्लस प्रॉडक्शन नहीं हो पाया है। मुख्य मंत्रीजी भी इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं अतः एग्रीकल्चर सैक्टर में एम्फेसिस किया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर का क्या हाल है ? इस सम्बन्ध में बड़ी बहस होती है सदन में कि हमारे यहां राजस्थान में पर-एकड़ ईल्ड गिर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय की स्पीच में पढ़िये, चाहे वित्त मंत्री की स्पीच में पढ़िये साढ़े पांच लाख टन का प्रोडक्शन पोटेन्शियल, ६४ तक मंजूर कर लिया है, ६६–६५ में प्रॉडक्शन पोटेन्शियल ४ लाख टन करेंगे। दोनों को मिलाने से साढ़े नौ लाख टन और थर्ड प्लान के बाकी बचे अर्से में ६ लाख टन प्रॉडक्शन पोटेन्शियल करेंगे, तो सैकिण्ड प्लान की समाप्ति के बाद में ६४-६५ में ५४ लाख टन प्रॉडक्शन के लक्ष्य को अचीव कराना चाहते थे। जो लक्ष्य अचीव करना चाहते थे, एग्रीकल्चर सैक्टर में ५० प्रतिशत प्रॉडक्शन आपने किया है और इस तरह आप अपने लक्ष्य को अचीव करने में फेल हो गये हैं।

इसी तरह आइल सीड के प्रॉडक्शन का जो आपका लक्ष्य था उसमें आप ७५ पर्सेंट ही अचीव कर पाये हैं, तो इसमें भी आप अपने लक्ष्य को अचीव करने में फेल हुए हैं। आप इसके लिए बहुत से कारण दे सकते हैं, कि वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान्ड इकोनोमी का मतलब ही यह है कि प्रकृति पर मानव विजय प्राप्त करे, अपने प्लान्स के अनुसार प्रॉडक्शन को बढ़ाये, अपने टार्जेट्स को अचीव करें, पर हम यह सब कुछ करने में फेल रहे हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पिछले बजट को देखने पर मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री ने, जो ढाई करोड़ रुपया एक्सीलरेटेड असिस्टेन्स का भारत सरकार से हमें प्राप्त हुआ था, वह भी पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दिया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार के पुराने कर्जे को चुकाने में दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह जब स्पेसिफिकेली एग्रीकल्चर के लिये यह रुपया मिला उस रुपये को कुछ एग्रीकल्चर में खर्च कर, कुछ ऋण पेटे चुका दें, इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रॉडयूक्शन नहीं बढ़ सकता। चम्बल बना तो-२१ करोड़ रुपया खर्च कर दिया पर राजस्थान सरकार का वाटर लौगिंग के प्रति कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड है। वाटर लौगिंग के लिए जनसंघ के लोग चिल्लाते हैं और और लोग चिल्लाते हैं पर आप कहते है, वह महत्वपूर्ण चीज नहीं, महत्वपूर्ण चीज तो २१ करोड़ रुपया खर्च करना है। चम्बल में मेरा यह दावा है कि जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, न लैंड का और न वाटर का। २५ पर्सेंट लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। राजस्थान केनाल की तो बात ही निराली है। आप इस पर ३२ करोड़ रुपया खर्च करना चाहते थे परन्तु पिछले तीन साल में १६ करोड़ रुपया खर्च कर सके हैं, ६ करोड़ इस साल का रखा है, प्लान के चार साल में आप २५ करोड़ ही खर्च कर सकेंगे। जो आपका टार्जेट ३८ करोड़ रुपया खर्च करने का है वह क्या आप पूरा कर पायेंगे ? नहीं कर पायेंगे। १३ करोड़ रुपया अब और, आपकी बजट प्लान प्रोविजन को देखते हुए आप कभी खर्च नहीं कर सकते। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान केनाल के नीचे २८ लाख एकड़ भूमि मे किस तरह हुआ, स्टेज वन और स्टेज टू में डिवाइड कर रखा है। राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार दोनो मिलकर रिवाइज नहीं करते है तो राजस्थान केनाल से राजस्थान को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जब तक इसे नेशनल प्रोजेक्ट नही बना लेते तब तक राजस्थान को इससे कोई फायदा नही हो सकता। मिश्र ने आस्वान डैम ३ साल में बना लिया। जो मुल्क सही मायने मे तरक्की करना चाहते हैं, वहां बहुत थोड़े अर्से में नेशनल डैम, नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाये जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिये, इनका फोर्थ प्लान में फल मिलेगा। मैं कहता हूं फोर्थ प्लान के शुरू में, फोर्थ प्लान के मिडिल में, हमें राजस्थान केनाल के फ्रूट्स मिलें इस बात को हमें भारत सरकार से कहना चाहिये। यदि यह संभव नहीं है, भारत सरकार हमारी इस बात को स्वीकार नहीं करे, कि इसका नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय तो भारत सरकार से कहा जाय कि हमारी फोर्थ प्लान में हमें १०० करोड़ और एडीशनल एड दीजिये, ताकि हम अपने प्लान प्रोविजन्स में खर्च कर दें। यह महत्व का विषय है कि वह प्रोजेक्ट ४ साल में पूरा होना चाहिये। भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरा कर दे। हम १०० करोड़ देना चाहते हैं तो वह १०० करोड़ एडीशनल हमको दें। २०० करोड़ की प्लान जो स्वतंत्र पार्टी वाले कहते हैं कि ओवर-एम्बीशस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है उसके लिए मै कहना चाहता हूं कि राजस्थान क्या कोई भी सरकार, जो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है, के लिए ५५० करोड़ भी ज्यादा नहीं।

जो कुछ सिफारिश डाक्टर लोकनाथन ने की है कि राजस्थान का भला नहीं हो सकता, राजस्थान में जो सरप्लस इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लगी हुई वह प्राप्त नही हो सकती, न पर-केपीटा इन्कम उससे बढ़ सकती है इसलिए प्लान की प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर पर एम्फेसिस दिया जाये। अभी तक जिस तरह से प्लान चल रहा है उससे हमें यह नहीं लगता कि हम राजस्थान की समस्याओं के लिए बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल को जिस तरह से हम १६ साल में पूरा करना चाहते हैं, उसको ४ साल में कम्पलीट किया जाय, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी, अनाज बिकेगा, सरकार को सेल्स टैक्स मिलेगा। २८ लाख की नई-नई मंडियां बनेंगी, उनके जो प्लाट्स कटेंगे उन पर नए मकान बनेंगे उनसे करोड़ों रुपये प्राप्त होंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जितनी इम्पार्टेन्स मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है।

श्री अध्यक्षः समय बहुत थोड़ा है ध्यान रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणाः मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। जो हमारे टार्जेट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा हम एग्रीकल्चर में फेल हुए, एजूकेशन में तीसरी प्लान में जैसे भारत सरकार कहती है, हमको ७५ पर्सेंट की जगह ८० प्रतिशत देना पड़ा, ६ से ११ वर्ष के बच्चों की पढ़ाई में हम सिर्फ अभी तक ४४ प्रतिशत तक पहुँच पाए हैं। मतलब यह है कि जो थर्ड प्लान के अन्त तक हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हम नहीं कर पाएंगे बल्कि दूसरी स्टेट्स ने जो दूसरी फाइव ईयर प्लान से प्राप्त कर लिया सिर्फ उस हद तक हम एजूकेशन के मसले पर पहुँच जायेंगे।

हमारी सरकार कोग्रॉपरेटिव्ज को बढ़ावा देना चाहती है। वह कहती है कि ४० प्रतिशत परिवार कोग्रॉपरेटिव सेक्टर में हमने ले लिए। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यह बात बहुत बार गवर्नर की स्पीचेज में और वित्त मंत्रियों के भाषणों में पढ़ने को मिली है। लेकिन कैसे आ गए? जो १० रुपये का शेयर लेता है और कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी का मैम्बर बन गया आपने उनकी भी गिनती करली? और वह कोग्रॉपरेटिव सेक्टर में आगया?

आज राजस्थान के किसान और साधारण जनता को इस तरह की कोग्रॉपरेशन के प्रति वह भावना नहीं है। इसलिए यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़ेबाजी है। गलत तरीके से कोग्रॉपरेटिव्ज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह मुख्य मंत्री भी जानते हैं और वित्त मंत्री भी जानते हैं, कि कोग्रॉपरेटिव सैक्टर उस ढंग से नहीं फंक्शन करता है, जैसे फंक्शन करना चाहिए। आज उसमें जो लोन्स की गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है कोग्रॉपरेटिव्ज डिपार्टमेन्ट उन सारी बातों को रोकने में नाकामयाब हुआ है। यदि कोग्रॉपरेटिव्ज को हम अपना वे आफ लाइफ बनाना चाहते हैं तो उसको हमें उस मॉडल पर मॉडल करना पड़ेगा।

(श्री मनिकचन्द सुराणा)

जिससे जन साधारण को उसके प्रति आदर हो। लेकिन वह विश्वास और आदर नहीं हो पाया है। इसलिए एजूकेशन को लें, एग्रीकल्चर को लें, चाहे इंडस्ट्रीज को लें, चाहे कोआॅपरेटिव्ज को लें, किसी भी मसले को लें, हमें अभी तक सफलता जिस पर गर्व कर सकें, वह नहीं प्राप्त हुई है। उधर आप समाजवाद की दुहाई देते हैं कि हम पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा, कि सोडियम सल्फेट की फैक्टरी शुरू हो गई एक्सपैरीमेंटल प्रोडक्शन शुरू हो गया, और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इसी पर दो पेज कह डालें। मैं यह नहीं कहता हूं कि दो पेज बहुत ज्यादा हैं लेकिन जिस दिन वह भाषण दे रहे थे उस दिन वहां सोडियम सल्फेट का प्रोडक्शन बंद था। वहां एक्सपैरीमेन्टल प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था। शुरू होकर बंद हो गया, उस दिन बन्द पड़ा था और आप कह रहे थे कि शुरू हो गया है। १०० टन सोडियम सल्फेट भी अभी बहुत दूर की चीज है। अपने भाषण में लिखा है कि १०० टन एक साल में पैदा करेंगे। फैक्टरी अभी भी जिस तरह से लगनी चाहिए नहीं लग पाई। पलाना लिग्नाइट के प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक करोड़ का प्रावधान किया था, थर्ड फाइव ईयर प्लान में, उस पलाना लिग्ना-इट फेक्टरी में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हमारे जो भूतपूर्व मन्त्री थे स्टेट इंडस्ट्रीज के श्री नाथूरामजी मिर्धा उन्होंने कहा था कि हमने चीफ इंजीनियर से कह दिया है कि वह आॅर्डर्स प्लेस कर दें और मशीनरी मंगाएं। चीफ इंजीनियर ने कहा कि हमारे पास कोई फाइनेन्शियल सैंक्शन नहीं है। जो नए मंत्री हैं श्री मथुरादास माथुर, उनसे भी हमने कहा तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन के सामने यह सवाल रखा था तो उन्होंने पूछा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां है?

तो उन्होंने कहा कि वह तैयार नहीं है। वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। जापान के एक्सपर्ट्स ने भी मांगी है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर सबमिट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पलाना लिग्नाइट का दूसरी प्लान में प्रोवीजन था, तीसरी प्लान में भी जिसके दो साल बाकी हैं। फर्स्ट प्लान में भी जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, प्रोवी-जन किया गया था। आपने इस तरह से १२ १३ साल गंवा दिए। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को इस तीसरी प्लान के अन्त होने से पहले एग्जीक्यूट करवा दें और इसमें यदि किसी भी तरह की कोई ढील रहती है तो न सिर्फ योजना मंत्री जिम्मे-दार हैं, न सिर्फ स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। राज-स्थान के इम्बेलेंसेज को समाप्त करना चाहिए इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कराना चाहिए और इस तरह जो इंडस्ट्रीज अलग अलग डिवी-जन्स में हैं उनको पूर्णतया सफल बनाया जाय।

इस तरह से जो लोन्स और एडवान्सेज आपने दे रखे हैं उनको दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन पर पूरा रिटर्न नहीं मिलता है। यदि हम पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, सोशलिज्म में हमारा कोई विश्वास है, सोशलिज्म का मतलब जिस तरह से आप समझते हैं, वह नहीं, सोशलिज्म, वह जिसमें पब्लिक सैक्टर का

Page No. 24

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इतना एक्सपेन्शन हो जाये कि प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे समाप्त हो जाय, प्राइवेट सेक्टर पर विजय पा सकें। आप मिक्सड इकोनोमी की बात करते हैं। हम अभी तक पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड नहीं कर पाए हैं। पब्लिक सेक्टर में जब तक हम अच्छे रिटर्नस् नहीं देंगे तब तक हमको ये स्वतंत्र पार्टी वाले क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हमें पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट एन्टरप्राइजेज़ मॉडल पर लाना है। हमारी रिलेशनशिप लेबर से क्या है? वहां भी मजदूरों की मांग यही है कि हमारी तनख्वाह बढ़े। हड़ताल करते हैं तब तनख्वाह मिलती है। कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। एक समाजवादी सरकार में पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐसे होने चाहिए जिनके आधार पर सरकार यह कह सके कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी इसी मॉडल पर बनाना चाहिए नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन आपने मॉडल किया है एन्टरप्राइजेज़ को। आप प्राइवेट एन्टरप्राइजर्स को मॉडल करें। इसलिए इन्डस्ट्रियल रिलेशनशिप में फन्डामेन्टल चेन्ज किया जाय। जब तक रिटर्न आफ पर्सेन्ट होगा तब तक राजस्थान में और देश में पब्लिक सेक्टर कभी भी नहीं पनप सकता। यदि पब्लिक सेक्टर को देश में और राजस्थान में पनपाना है तो कम से कम रिटर्न छः पर्सेन्ट होना चाहिये। जो सेक्टर छः पर्सेन्ट का रिटर्न नहीं दे सकता, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें पैसा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और हम को अधिक रिटर्न लाना है। इसलिए पब्लिक सेक्टर में जितना पैसा हमारा लगे, मैं यह मांग करूंगा कि कम से कम ऐसे एफर्ट किये जायं कि कम से कम ६ पर्सेन्ट रिटर्न तो हमको आ जाय। जो रुपया आपने प्राइवेट सेक्टर में लगा रखा है, अगर प्राइवेट सेक्टर आपको उन रुपयों का छः पर्सेन्ट रिर्टन नहीं दे सकता है तो आपको उन शेयर्स को वहां से विथड्रा कर लेना चाहिये और उनको ओपन मार्केट में बेच दिया जाना चाहिये जिससे उस पैसे का अच्छा उपयोग किया जा सके।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अभी जो रिटर्न ठीक प्रकार से नहीं आता है, उसके क्या कारण मानते हैं?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका कारण मैनेजमेंट की अव्यवस्था, सरकार का इनएक्सपीरियेन्स्ड होना और पब्लिक सेक्टर में सरकार का फेथ कम होना ये मूल कारण हैं, जिनके कारण रिटर्न ठीक नहीं मिल सकता।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं ठीक तरह से नहीं समझा।

श्री मानिकचंद सुराणा : पब्लिक सेक्टर में फेथ की कमी, निष्ठा की कमी। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। फर्टीलाइजर की फेक्टरी का क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में लगाना है। आपकी स्पीच के आधार पर कहना चाहता हूं कि जहां प्राइवेट एन्टरप्राइजर्स ने नहीं लगाया वहां स्टेट आगे होकर लगायेगी। हनुमानगढ़ में पब्लिक सेक्टर में फर्टीलाइजर फेक्टरी को कायम करें। बीकानेर में वूल मील को कायम करें पब्लिक सेक्टर में।

श्री बालकृष्ण कौल : निष्ठा की कमी नहीं हुई।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं कॉजेज़ में जा रहा हूं कि किन कारणों से उसमें फुल

(श्री मानिकचंद सुराणा)

रिटर्न नहीं हुआ। हो सकता है आपका उसमें मेरे से मतभेद हो। जहां तक मैं समझता हूं यही मूल कारण है।

अध्यक्ष महोदय, यदि पब्लिक सेक्टर को एक्सपेन्ड करना चाहते हैं राजस्थान की इकोनोमी को देखते हुए यदि एग्रीकल्चर को एम्फेसिस देना है तो फर्टीलाइजर फैक्टरी कायम करें। एनीमल हस्बैन्डरी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे ११ पर्सेन्ट स्टेट को इन्कम प्राप्त होती है। इसके साथ साथ वुलन मिल कायम की जाय, सोफ्ट वाटर बनाया जाय। आज विज्ञान का युग है। यदि बीकानेर में हार्ड वाटर है, तो वह सौफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जहां नाली आती है घग्घर की, वहां पर प्रोजेक्ट बना कर जो ४॥ करोड़ की स्कीम है उसको और एक्सटेण्ड करके इमिजियेटली तीन वर्षों में बीकानेर तक और चूरू तक उसका पानी पहुँचाया जा सकता है। इन प्रोजेक्ट्स को आपको एम्फेसिस देने की आवश्यकता है ताकि विकास का बेस बन सके।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आखिर में फेमिन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में १५ लाख आदमी फेमिन से अफेक्टेड हैं। आपने जो प्रावधान रखे हैं उनके आधार पर चार रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। आपने १ करोड़ ८७ लाख का प्रावधान किया है। एवरेज चार रुपया प्रति व्यक्ति का आता है। चार महीने अकाल के हमारे सामने हैं। मैं नहीं समझता कि एक महीने में एक रुपया प्रति व्यक्ति के लिए रख कर, यह देखते हुए कि ऐसा २५ वर्ष में भी अकाल नहीं पड़ा है, चार महीने निकाल सकें। यह ठीक है, आपने यह कहा कि इसके प्रोविजन को बढ़ाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने कमजोरियां दिखाते हैं। बिजली और पानी का झगड़ा हमारा पंजाब के साथ तय नहीं हो सका। १ करोड़ से ऊपर ५० पर्सेन्ट मिलता है और स्टेट की इकोनोमी यह गवारा नहीं कर सकती है कि ५० पर्सेन्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे तो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से ७५ पर्सेन्ट रकम देने का प्रयत्न करना चाहिये। आज भी राजस्थान के बहुत से गावों में यह शिकायतें हैं कि उनके यहां फेमिन डिक्लेयर होना चाहिये वह नहीं हुआ। नागौर की ऐसी शिकायत है। करीब १०० गांव ऐसे हैं जहां फेमिन डिक्लेयर होना चाहिये था लेकिन फेमिन डिक्लेयर नहीं किया गया। चूरू के हैं, सूरतगढ़ के गांव हैं, जहां फेमिन डिक्लेयर हो जाना चाहिये था नहीं हुआ।

जहां फेमिन चल रहा है, वहां आपकी डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटीज, तहसील रिलीफ कमेटीज फन्क्शन नहीं करती और लोग मांग करते हैं काम की जरूरत, नाडी खुदवाई जाय, तालाब खुदवाये जायं तो क्लेक्टर महोदय कह देते हैं, कि आवश्यकता नहीं है। पानी कब भरेगा ? चार वर्ष में डेजर्ट में पानी नहीं होता है। यह पूछना कि नाड़ी भरेगी या नहीं यह एक टालने की बात है और उचित नहीं है। लोगों को तो धन्धा देना है—चाहे आप उनको सड़क पर दें या तालाब को खुदवाने में दें। बीकानेर में दिखाया गया कि सबसे ज्यादा एक्स्पेन्डीचर हुआ है। जहां तालाबों की जरूरत है, खारे पानी के गांवों में वाटर स्टोरेज के लिए तालाब बना देने चाहिये। वह काम नहीं हो रहा है। अक्टूबर में मुख्य

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

मंत्री जी आये थे। सड़कें नवम्बर में मंजूर कर दीं। वे आज तक छुई नहीं हैं। कलेक्टर महोदय को कहते हैं। रोज उनके पास डेलीगेशन आते है, और कहते हैं कि मंजूरी हो गई है फिर सड़कों का काम क्यों नहीं शुरू होता है? कलेक्टर कहते हैं कि ओवरसीयर नहीं है, असिस्टेन्ट इन्जीनियर नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : फेमिन में लगे हुए हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने सेंक्शन कर दी, उसके बावजूद भी एक्जीक्यूशन नही है। फाइनेन्शियल सेंक्शन से क्या हुआ? एक्चुअल वहां काम हो उससे मतलब है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसके लिए शुक्रिया।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपकी तारीफ के लिये धन्यवाद।

मिनिस्टर साहब ने ये बातें रखी थीं। १.८७ लाख का प्रोविजन रखा है इससे काम नहीं चलने वाला है। यह मांग की गई थी कि राजस्थान को कम से कम फेमिन रिलीफ के लिए ८ करोड़ रुपया खर्च करना चाहिये जब कि पिछले वर्ष और इस वर्ष चार सवा चार करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। इस प्रोविजन को बढ़ाया जाय और लोग मांग करते हैं कि तलाइयों के काम को शुरू किया जाय। और सड़कों के काम जहां सेंक्शन कर दिये हैं उनको शुरू किया जाय। एक रोजी पिक्चर कागजों में पेन्ट कर देने से काम नहीं चलता। जहां पर वर्क्स चलते हैं वहां पर अनाज की उपलब्धि नहीं है, शोप्स नहीं हैं, झोंपड़ी नहीं हैं। दो हजार लेबर के कैम्प पर ही चले जाइये, सन्ध्या को रहने का मौका मिले, शेल्टर नहीं है, लोगों की क्या कठिनाइयां हैं यह आपको मालूम हो जायगी। मेडीकल फेसिलिटीज नहीं है। पांच हफ्ते तक वेजेज का पेमेंट नहीं होता है। टेलीग्राम आपको करेंगे बावजूद इसके नहीं आता।

श्री बालकृष्ण कौल : हमारे पास इत्तिला नहीं।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपके पास नहीं फेमिन मिनिस्टर साहब और मुख्य मंत्री जी के पास भेजते हैं।

इसलिए फेमिन वर्क्स में जो तेजी राजस्थान में आनी चाहिये वह नहीं आई है और जो लिबरल एटीट्यूड हमारा होना चाहिये, उसको कायम करने की जरूरत हैं।

उसके साथ ही फेमिन वर्क्स में फोडर का इन्तजाम है। ग्रेटेशियस का भी प्रावधान किया है लूले-लंगडों के लिए। मई, १९६३ में ७४ आदमियों की, बीकानेर जिले के आदमियों की लिस्ट बनी है। ७४ आदमी लूले-लंगड़े, अंधे आदमी थे उनको एक महीने तक सहायता दी गई। उनको सात महिने तक बाद में मुतवातिर सहायता नहीं दी। मुख्य मंत्री जी आये। कलेक्टर को आदेश दिया। उसका क्या हुआ? कलेक्टर को तीन दफा याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगले महीने शुरू करेंगे। दिसम्बर तक उन लूले-लंगडों को नहीं मिला। हमने प्रोविजन किया। कहेंगे कि लेप्स हो गया। फाइनेन्स मिनिस्टर कहेंगे कि अच्छा हुआ सेविंग हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

एक प्रोब्लम उठती है कि, कलेक्टर नहीं मानता है तो क्या किया जाय ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह जब हुकूमत में आवेंगे तब बतावेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह जब गवर्नमेन्ट में आवेंगे तब बतावेंगे, उनके पास अलादीन का चिराग तब आयगा । लेकिन मैं तो अभी बता दूंगा ।

इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो ढिलाई है कि कलेक्टर नहीं मानता तो आप तीन आदमियों की एमर्जेन्सी कमेटियां हर जिला और तहसील हैडक्वार्टर पर बना दीजिये । जिसमें दो नोन ऑफिशियल मेम्बर्स हों और कलेक्टर भी उसका मेम्बर हो । फिर देखा जाय कि उसका इम्प्लीमेन्टेशन होता है या नहीं । नौन ऑफिसियल मेम्बर्स चाहे आप ही की पार्टी के क्यों न रखे जाय, हमें कोई एतराज नहीं होगा । सिर्फ बजट सेक्शन और फाइनेन्सियल सेक्शन से यह समस्या हल होने वाली नहीं हैं एक्चुअल इसका इम्पलीमेन्टेशन किया जाना चाहिए ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स प्रपोजल्स प्रस्तावित किये गये हैं, उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । टैक्स प्रपोजल्स में, जो दस हजार से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनमें जो इस प्रकार के प्लाट्स खाली हैं, उन पर टैक्स प्रपोज किया गया है मैं इसका विरोध नहीं करता । मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस टैक्स को नहीं लेकर भी, जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार सरकार कार्यवाही करती तो आपको इससे बीस गुना ज्यादा आमदनी मिल सकती थी । आप बीस गुना अधिक रेवेन्यू नहीं लेना चाहते । मैं आपके सामने जयपुर का ही उदाहरण दूं ऐसे ४५० प्लॉट्स जिन पर दो साल के बाद भी मकान नहीं बनाये गये जयपुर में हैं, जिनकी लिस्ट भी बनी थी । इस प्रकार जिन्होंने मकान नहीं बनाये उनको उनकी लागत का एक चौथाई पैसा लौटा कर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट उस पर कब्जा कर सकता था लेकिन वह कार्यवाही नहीं की गई । अगर उन प्लाट्स पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती तो ट्रस्ट को इन्हीं प्लॉट्स से करीब ४० लाख की आमदनी हो सकती थी । लेकिन हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने क्या किया कि इन प्लाट्स को केन्सिल नहीं किया और वह मामला अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को रेफर कर दिया । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उन प्लॉट्स में ऐसे प्लॉट्स थे जिन लोगों ने दस दस प्लॉट्स खरीद रखे थे और वे ऊंचे भावों में बेचने के लिए ही खरीदे गये थे । इस तरह से बड़े बड़े लोग ही इस प्रकार अपने पैसे का इन्वेस्टमेन्ट कर सकते हैं, साधारण आदमी के तो बलबूते की बात नहीं हो सकती । बड़े लोगों के प्लॉट्स थे इसलिए केन्सिल नहीं किये गये । अभी भी मेरा दावा है जितने प्लाट्स जयपुर में खाली पड़े हैं, अगर उनको उप मंत्री महोदय केन्सिल करें, अगर उनमें हिम्मत हो तो वे केन्सिल करें, उससे ही तीस लाख की आमदनी ट्रस्ट को हो सकती है । आपने जो

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

इसके लिए आना सैंकड़ा लगाने का विचार किया है उससे आपको पांच हजार रुपये भी नहीं मिलने वाले हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर हम सोचना बन्द कर दें इस प्रकार नये नये टैक्स लगाने के बारे में तो………

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेरा सुझाव था कि इसको आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बना दें ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : अगर आप इसको बीस साल पहिले से भी लागू कर दें तो भी बीस गुना आमदनी नहीं आने वाली है । इस टैक्स के इम्पोजिशन का मैं विरोध तो नहीं करता लेकिन मुझे इसके लागू करने में खुशी भी नहीं हैं । यह कोई समाजवादी टैक्स नहीं है । यह तो केपीटलिस्ट मनोवृत्ति का परिचायक है । ज्यों ज्यों लैन्ड की कीमत बढ़ती जाती है उस पर रेवेन्यू के रूप में इन्कम प्राप्त करने की सोचना यह पूंजीवादी प्रवृति का परिचायक है । अमेरिका ब्रिटेन आदि देशों में यह टैक्स है । आप इस आधार पर कि हमने शहरों में जो इस प्रकार प्लॉट्स पड़े हैं, उन पर टैक्स लगा दिया हैं, इसलिए हमें समाजवाद का सर्टिफिकेट मिल जायगा कम से कम मेरे लिये यह आपको देना संभव नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बजाय आपके जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, उन पर आप जोर दीजिये, अगर कोई नहीं बनाता है तो उसके प्लाट्स को केन्सिल कीजिये, उससे आपको ज्यादा आमदनी मिलेगी ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो हमारा फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स है वह सेल्स टैक्स इस बजट में कम हो जाता है। सरकार कहती है कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेज बढ गये हैं । गेहूं का भाव जो १८ रुपया मन था वह आज २८ रुपया मन हो गया है। अगर इस हिसाब से भी १ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स डाला जाय तो स्टेट के रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ती हुई कीमतों पर भी यदि सेल्स टैक्स आपको दो पर्सेन्ट मिलता है तो आप इस बढी हुई कीमत के कारण अपने सेल्स टैक्स में वृद्धि करना चाहते हैं । इस तरह से फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स की कमी नहीं हुई है। आपने खुद ने यह माना है कि अनाज की कीमतों में बहुत बडी वृद्धि हुई है ।

श्री **ललितमोहन** (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिला । अतः मेरा नम्र निवेदन हैं हमें भी समय मिलना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : इस बारे में आप अपने पार्टी लीडर से बात करिये, एक ही रास्ता है। उनको चाहिये कि वे आपका नाम उसमें दें ।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, समय का कुछ बटवारा जरूर होना चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष**: समय का बटवारा बराबर होता है और उसी के अनुसार चल रहे हैं। हर पार्टी को समय मिला है । उसी हिसाब से बहस का क्रम चल रहा है।

श्री मानसिंह महार: माननीय सदस्य को बोलते हुये ४५ मिनट से ज्यादा समय हो गया है....

श्री अध्यक्ष : जहां तक समय का सवाल है किस किस पार्टी को कितना दिया जाय वह समय बंटा हुआ है। सामान्य तौर पर सभी पार्टियों को समय दिया गया है अभी भी समय शेष है। जो नहीं बोल सके हैं उनको समय दिया जा सकता है....

श्री ललित मोहन: शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो एम० एल० एज़ हैं चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, उनको बोलने का समय नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अगर इस बारे में पार्टी के नेता लोग ध्यान रखते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये मेरा निवेदन है फूड-ग्रेन्स पर जो दो पर्सेन्ट टैक्स हैं उसको एक पर्सेन्ट कर देना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय ने इस बारे में आर्डि-नैन्स नहीं निकाला है और न सेल्स टैक्स के जो प्रोविजन्स है उनमें हमारे सामने इस प्रकार का कोई प्रावधान आया है। बढ़ती हुई कीमतों में व्यापारी मुनाफाखोरी करें और उस मुनाफाखोरी से सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाये– क्या इसको सोशियलिस्ट हुकूमत कहा जा सकता है ? कदापि नहीं कह सकते। विशेष रूप से मेरा यह कहना है कि फूड ग्रेन्स में जो सेल्स टैक्स आपका है वह कतई अनुचित हैं इसलिये फूड ग्रेन्स पर जो सेल्स टैक्स दो प्रतिशत है उसको एक प्रतिशत कर दिया जाय। इसके साथ साथ हम यह नहीं चाहते कि जो प्राइसेज हैं वे निर्विवाद रूप से बढते जाय और उस हिसाब से पांच रुपया सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ा दिया जाय। मेरा यह निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों का डीअरनेस अलाउन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग के इन्डेक्स से जोड़ दें। इससे जो अनाप शनाप बर्डन स्टेट एक्स-चेकर पर पड़ेगा तो मैं यह मानता हूं कि प्राइसेज को बढने न देने की भावना आप में जागृत होगी, उसका हल ढूंढने के लिये भावना आयेगी। प्राइसेज जब बढ़ते हैं उसका असर जन साधारण पर पड़ता है और जब उस हिसाब से सरकार को भी महंगाई देनी पड़ेगी तो सरकार उसको रोकने का उपाय निकालेगी। प्राइसेज़ को रोकने के लिये एम-र्जेन्सी भावना आयेगी। अभी आपमें भावना नहीं है। अभी तो आप एक स्पेक्टेटर की भांति इसको देखते रहते हैं।

कल ही मुख्य मंत्री महोदय ने चैम्बर के भाषण में और कृषी मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि व्यापारी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने इसके लिये कोई उपाय सोचा है ? मैं आपका ध्यान अशोक मेहता के चेयरमैन-शिप में जो कमेटी स्टेबिलाइजेशन ऑफ प्राइसेज़ के बारे में बैठी थी उसकी रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। उन्होंने इस बारे में अपने सुझाव दिये थे जो आज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हो गये हैं। चाहे आप दूसरों के, किसी के सुझाव मानें या न मानें उन्होंने प्राइ-सेज स्टेबिलाइजेशन बोर्ड कायम करने की सिफारिश की है उसको तो आप लागू करिये। इसमें आप पहल करिये। इस प्रकार से जो प्रॉफिट व्यापारी लोग कमा रहे हैं, होल-सेल व्यापारी और रिटेल व्यापारी उनके मुनाफे को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सीमित कर दीजिये और जो उससे अधिक आमदनी हो वह स्टेट एक्सचेकर में शामिल कीजिये। इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई जाय। मैं इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू इसलिये कहता हूं कि वह टैक्स नहीं है और न हम उससे मुनाफा लेते हैं। हम तो उसे स्टेट एक्सचेकर में जमा कर लेते हैं।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राजस्थान में प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड कायम किया जावे।

आपने जो पेंशन दी है बुड्ढों के लिये, मैं उसके ऊपर आपको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। आपका यह कदम वेलफेयर स्टेट कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आपकी मिड-टर्म प्लान के अनुसार कोई तीन लाख नौजवान बेकार हैं उनको सरकार काम नहीं दे सकती। यह सरकार मानती है। बूढ़ों को आप राहत देना चाहते हैं, यह सही है। पर नौजवानों को अगर आप अनएम्प्लायमेन्ट का कम्पेन्सेशन भी नहीं देंगे तो यह निश्चित बात है कि उनके खाली दिमागों में खुराफातें आ सकती हैं और वे आपके खिलाफ बगावत के भाव पैदा कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। तो या तो आप उनको कोई न कोई धन्धा दे दीजिये नहीं तो उनकी खुराफातों को स्वीकार करिये। इसके अलावा दूसरा कोई आल्टरनेटिव इसका नहीं है।

अब अनएम्पलॉयमेन्ट के खिलाफ आदमी को राज्य में सिक्योरिटी न हो यह समाजवादी सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसलिये जो आज बेकार हैं उनके लिये आपके एक्सचेकर पर फिर कुछ भी भार पड़े, प्रत्येक को कम से कम बीस रुपया माहवार कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान अपने बजट में रखकर आप चलें और इसकी तैयारी करें। सही सोशियलिस्टिक स्टेट की दिशा में यह अगला कदम होगा।

अन्त में यह मांग करते हुए कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यू का सरचार्ज फौरन समाप्त किया जाय, मैं अपना कथन समाप्त करूंगा। राजस्थान में यह लैंड रेवेन्यू उड़ीसा, यू. पी. और मध्यप्रदेश के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सेल्स-टैक्स का इन्सीडेन्स पर–व्यक्ति पड़ता है। तो जब सेल्स-टैक्स का इन्सीडेन्स सबसे ज्यादा है और जमीन का उत्पादन जहां उन स्टेटों में १२८ प्रति एकड़ का है हमारा प्रति एकड़ का उत्पादन सिर्फ ६२) का है। तो मैं समझता हूं यह सरचार्ज लैंड रेवेन्यू उचित नहीं है, और राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों में इसे फौरन समाप्त किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **नाथूराम** (वागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का बजट जो यहां पेश हुआ है उस को देखते हुए मैं सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वैसे तो राजस्थान ने आजादी के बाद में काफी तरक्की की है। पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि भी आज सब जगह जा रहे हैं। यहां भी आये हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मानसिंह महार मेरे से अखबार मांग रहे हैं। एक प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ पहले ही चल रहा है।

श्री **मानसिंह महार** : सदन में, अध्यक्ष, महोदय, लाना ही गलत है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : लाना गलत नहीं है, पढ़ना गलत है।

श्री **नाथूराम** : राजस्थान सरकार ने यहां पंचायती राज कायम किया। उसमें पिछड़े वर्ग

(श्री नाथूराम)

के प्रतिनिधि भी आये। यहां और सैन्टर में भी इस बारे में बड़े महत्वपूर्ण कानून बने। राजस्थान में भूमि सुधार के कानून भी बने लेकिन सरकार की तरफ से इन कानूनों का पालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। यह खामी है। इसे ठीक किया जाय यह मेरा निवेदन है।

भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से आदिवासियों के हित के लिये उनकी तरक्की के लिये काफी काम हो रहे हैं। लेकिन इस बजट को देखते हुए वित्त मंत्री महोदय ने आदिवासियों के बारे में एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

सरकार ने पिछड़े वर्ग के एवं आदिवासियों के लिये आदिवासी क्षेत्रों में न छात्रावास खोले हैं न हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले हैं। इसके लिये इस बजट में प्रावधान भी नहीं रखा है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर–बांसवाड़ा के आदिवासी एरिया में राहत के कार्य भी होते हैं और पंचायतों में निर्माण के काम और सिंचाई के काम भी होते हैं, सिंचाई के कामों में ३३ पर्सेन्ट श्रमदान भी आदिवासियों से लिया जाता है, पी० डब्लू० डी० से और सिंचाई विभाग से नहीं लिया जाता है। पंचायतों में लोग श्रमदान भी बहुत करते हैं फिर भी उनको जैसी मदद मिलनी चाहिये नहीं मिलती है। उनको भूखों मरने का प्रश्न है। उदाहरण के लिये मैं बताऊं; सरकार ने कृषि के लिये छोटे छोटे तालाब बंधाये हैं। पर न उधर नहरों की व्यवस्था है, न और कोई जरिया है। आदिवासियों के लिए कुऐं बनाने के लिये सरकार ने पैसा दिया है, पर इसमें भी भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिये। बांसवाड़ा में हजारों कुऐं इनकम्पलीट पड़े हैं। (५००) सब्सिडी दी जाती है पर इसमें से बी० डी० ओ० ही आधा पैसा खा जाते हैं। लगभग चार हजार कुऐ इनकम्पलीट पड़े हैं।

तालाबों में भी यही हालत है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जहां हमारे लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार काफी रकम खर्च करती है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। जहां भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ हमने कागज भी उच्चाधिकारियों के पास पहुँचाये हैं। गबन के और भ्रष्टाचार के कागज पहुँचाये पर सरकार की ओर से टाल दिया जाता है। सही जांच नहीं होती है।

हम आदिवासी चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, उत्पादन बढ़ावें, पर सरकार की ओर से पैसे का वास्तविक उपयोग नहीं होता है। सरकार भी खर्च करती है, इसमें शक नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इधर और उधर बैठने वाले भी भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं। लेकिन मामले सही हाउस में लाने चाहिए। जब तक भ्रष्टाचारी अफसरों और कर्मचारियों को ठीक तरह से सजायें नहीं मिलेंगी, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। सरकार की ओर से लाखों रुपया हमारी भलाई के लिए खर्च किया जाता है पर गरीब लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वह इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण नहीं मिल रही है।

शिड्यूल्ड एरिया में टैक्निकल शिक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिए। कई स्थानों पर केवल किताबों की शिक्षा मिलती है, उद्योगों की नहीं।

भूखिया पंचायत समिति निकट के क्षेत्र में चालीस हजार की जन संख्या में ९९ प्रतिशत आदिवासी हैं। पर वहां एक भी हायर

(श्री नाथूराम)

सैकेन्डरी स्कूल नहीं है। कुदरत ने पहाड़ों से एक अनास नदी निकलने के कारण इस क्षेत्र को तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से अलग कर रखा है। उस एरिया में बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं। वे अपने लड़कों को आठवीं तक या प्राइमरी तक ही पढ़ा सकते हैं। उनको हाई स्कूल में जाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। तहसील में कृषक काम के लिये जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर जाते हैं तो नदी में तैरकर उसे पार करके जाते हैं। इस तरह क्षेत्र में रहने वाले गरीब लड़के आगे की शिक्षा पाने के लिऐ कैसे बाहर जा सकते हैं। इसलिए उस एरियां में कम से कम पंचायत समिति के हेड क्वार्टर पर जो मिडिल स्कूल है। हायर सैकेन्डरी स्कूल इस वर्ष शुरू हो जाने चाहिए।

(१०.०० म. पू.)

अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट विभाग के लिए मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि फोरेस्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। फोरेस्ट में अन्दर जब तक कोई पॉलिसी सरकार निर्धारित नहीं करेगी, तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। आज फोरेस्ट की जो सम्पदा है, जो उसकी उपज है, उसके लिए गवर्नमेन्ट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे आदिवासियों फोरेस्ट सोसाइटीज बनाइए-इसके लिए मैं यह नहीं कहता कि फोरेस्ट सोसाइटीज में आप सारे आदिवासियों की ही रखें लेकिन उनमें अधिक तर आदिवासी लोग हों। वहां पर सोसाइटी बनाकर गवर्नमेंट के अन्दर में ये सोसाइटीज काम करें और टेक्निकल आदमियों के द्वारा उनकी व्यवस्था होनी चाहिए और जो छोटे-मोटे ठेके हों वे उन फोरेस्ट सोसाइटीज को देने चाहिए ताकि गरीब लोगों को कुछ विशेष फायदा पहुंचे और मैं आपको सही स्थिति निवेदन करूं कि आज जंगलों की रक्षा वे आदिवासी लोग करते हैं। जहां रिजर्व फोरेस्ट्स हैं गवर्नमेन्ट हजारों रुपया उन पर खर्च करती है लेकिन रिजर्व फोरेस्ट के लिए ठीक रक्षा व्यवस्था नहीं ही बांसवाडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जंगल थे कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं गिरती थी लेकिन आजादी के बाद बड़े बड़े जंगल कट गए और बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिए गये। इसलिए वहां क्या होता है कि हर साल हतसाली होती है। कभी पानी ज्यादा भी बरसता है लेकिन हतसाली ज्यादा होती है और सरकार को हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जंगलों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जहां पुराने वृक्षों को काट कर नये आबाद करने की जरूरत है वहां होनी चाहिए। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह देखा कि पहले गवर्नमेन्ट ने छोटी छोटी चोकियां जंगलों में बनाने का सोचा था लेकिन राजस्थान सरकार ने संकट-कालीन स्थिति के कारण छोटी सी रकम के लिए वहां पर चोकियां बन्द कर दी। इससे जंगलों की रक्षा ठोक तरह नहीं हो सकती। जंगलों की रक्षा के लिए आज आदिवासियों को भर्ती करना चाहिए। जंगलों में जो गार्ड्स रखे जाते हैं उनके लिए आदिवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा छोटे मोटे उद्योग भी फोरेस्ट के अन्दर होने चाहिए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए हमारी राजस्थान सरकार काफी कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी कृषि की उपज गिरती

(श्री नाथूराम)

जा रही है। उसके लिए मैं बांसवाड़ा का उदाहरण पेश करता हूं। वहां बाढीगोरा और बांसवाड़ा तहसील में अधिक कपास पैदा होती है और लगभग २ करोड़ का कपास वहां पर हर साल पैदा होता है। लेकिन जब कपास को बीमारी लगती है तो एग्रीकल्चर विभाग उसमें असफल रहता है। फसलों में जब बीमारी लगती है और हम दवाइयों की मांग करते हैं और कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं लेकिन जब पर एग्रीकल्चर विभाग के जो कर्मचारी हैं वे समय पर न दवाइयां दे सकते हैं और न उनको इसका ज्ञान ही है। कॉलेज से नये लड़के निकले हुए एक्सटेंशन ऑफिसर आ जाते हैं और उनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। तो उन पर काश्तकार लोग हंसते हैं। जहां पेडी ज्यादा होती है उसकी रोप यानि पौधें बनाने के लिए जब काश्तकारों को वे बताते हैं तो काश्तकार हंसते हैं कि ऐसा सिखाने वाले क्या आया है कि उसको खुद को ज्ञान नहीं है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां कपास ज्यादा पैदा होता है वहां पर हजारों का कपास बीमारी के कारण नष्ट हो जाता है और हर वर्ष नष्ट होता है। आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए गवर्नमेन्ट को व्यवस्था करनी चाहिए और समय पर दवाइयां देनी चाहिए ताकि खेती में फसलों का नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, गढ़ी तहसील में और बागीडोरा में पेड़ी ज्यादा होती है और उसमें आर्मी कीटाणु भी लगता है वह सारी खेती को नष्ट कर देता है। लोगों ने दवाइयां मांगी लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट हमेशा सुस्त रहता है। मैंने खुद ने दवाइयां खरीद कर खेतों के अन्दर उनका उपयोग किया और ग्राम–सेवक को पास रखा तो वहां पर खेतों में फसल बच गयी लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से इतनी ढिलाई है कि जहां हजारों मन चावल हर साल पैदा होता है, वहां बीमारी के कारण सारा चावल नष्ट हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर विभाग को अच्छे आदमी रखने चाहिए, अनुभवी आदमी रखने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कालेज से निकले हुए लड़के वहां एक्सटेन्शन ऑफिसर बना दिये जावें जिनको खुद को ही ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए वहां बीमारी के कारण फसलें नष्ट होती हैं। इसके अलावा वहां पर सिंचाई के साधन नहीं होने से पैदावार नहीं बढ़ती है। पैदावार के लिए गरीब आदमियों को साधन नहीं मिलते तो वे कोशिश करते है लेकिन गवर्नमेन्ट की की तरफ से इतनी ढिलाई है कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है बल्कि जो रुपया काश्तकारों को दिया जाता है सिंचाई के लिए या मेड-बन्दी के लिए या कोई और सार्वजनिक कामों के लिए अधिकतर वह रुपया भ्रष्टाचार में जाता है और उसकी कोई रोक थाम नहीं है। इसलिए बार-बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिए।

एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं पशु-धन के बारे में भी कहूंगा। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हजारों मवेशी हर साल मरते हैं ....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: यह झूठी बात क्यों कहते हैं? सारे राजस्थान में एक पशु नहीं मरा!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): फेमिन के टाइम के अलावा भी पशु मर जाते हैं।

Page No. 34

श्री नाथूराम: अध्यक्ष महोदय, पशु-धन को भी बचाना जरूरी है। उनके चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। पशु-धन की रक्षा होगी तो काश्तकारों को घी–दूध के साथ ही साथ गोबर भी मिलेगा। फैक्टरी में खाद बनती है जैसे एमोनियम सल्फेट के साथ अगर देशी खाद नहीं दी जाये तो जमीन ज्यादातर ऊपर हो जाती है। देशी खाद के लिए पशुओं की रक्षा करना जरूरी है। लेकिन गाय और बैलों को जब बीमारी लगती है तो वहां पर पशु चिकित्सक को सूचना दी जाती है तो वह अपना टी० ए० और डी० ए० बना लेता है लेकिन पशुओं का वक्त पर इलाज नहीं होता है और हजारों मवेशी मर जाते हैं। काश्तकार के पास जब दो बैल होते हैं और एक बैल मर जाता है तो उसकी तमाम खेती रुक जाती है। अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वेटनरी का एक डाक्टर रखा गया है लेकिन ८ साल से उसका तबादला नहीं हो रहा है। आज बांसवाड़ा के अन्दर ८ पंचायत समितियां हैं और डूंगरपुर में ६ पंचायत समितियां हैं और वह सब जगह दौरा करता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वह टी० ए०, डी० ए० कमाता है उसको कोई ज्ञान नहीं है और न वह समय पर जाकर पशुओं का इलाज करता है। जब लोग कहते हैं तो मजाक में वह टालता है। हमने गवर्नमेन्ट को उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि उसका ट्रान्सफर होना चाहिए लेकिन ८ साल से वह वहीं बैठा है। बांसवाड़ा से उसको डूंगरपुर हटाया लेकिन गवर्नमेन्ट की ढिलाई है कि ८ साल तक ऐसे ऑफिसर को एक जगह पर रखा जाता है। इसी तरह से पंचायत समिति गढ़ी के अन्दर बी० डी० ओ० है वह ८ साल से बराबर वहां है और उसका तबादला नहीं हुआ। इससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काफी भ्रष्टाचार होता है। जो एक्सटेन्शन ऑफिसर्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा यह भी निवेदन है कि आदिवासियों के लिये जो तरक्की की जा रही है वह ठीक है। मैं मानता हूं कि सर्विसेज के बारे में साढ़े बारह पर्सेन्ट आदिवासियों के लिए कोटा रखा गया है। ठीक है लेकिन यह साढ़े बारह पर्सेन्ट कागजों में ही है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और मीणों के कुछ लड़कों को सर्विसेज में लगाया होगा, यह ठीक है, लेकिन आज बी० ए० और एम० ए० कई भीलों के लड़के हैं, वे मारे मारे फिरते हैं और उनको ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को पहले निवेदन किया था उस पर कुछ सर्विस में लिये। समाज कल्याण विभाग में आदिवासी लड़कों को सर्विस में लेना चाहिये। लेकिन अधिकतर लड़के आज बेकार फिरते हैं। वैसे जो सरकार ने नियम बनाया है और हमारे लिए कोटा रखा है ठीक है लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे उनका पालन नहीं होने देते हैं।

आज आदिवासियों के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पर जो सर्विसेज का प्रश्न है, जो जो पढ़े-लिखे लड़के हैं, उनको कम से कम समाज-कल्याण विभाग में जगह मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग में ऐसे महानुभाव बैठे हैं, जो न तो पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं और न उन्होंने कभी सेवा का काम किया है। वे सही स्थिति को नहीं जानते हैं। आज किसी सवर्ण को कह

(श्री नाथूराम)

सर्विस नहीं मिलती तो समाज-कल्याण विभाग में रख दिया जाता है। आदिवासियों के बी० ए०, एम० ए० पढ़े-लिखे लड़कों को भी सर्विस नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और हाउस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाली विरोध के लिए ही विरोध न करें, लेकिन विरोध के साथ सही सुझाव भी दें, और जैसा कि भ्रष्टाचार हो रहा है उसके सही स्वरूप को लाकर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मोहन और उसके बाद श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री **ललित मोहन** (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सामने ६४-६५ का बजट पेश है। इसको शुरू से अन्त तक मैंने पढ़ा। इसमें आदिवासियों के लिए जो कि राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, और प्रांत का बहु भाग जहां ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है और जिसके लिए हमारी गर्वनमेंट बराबर यह कहती है और हमारे मुख्य मंत्री जी भी अपने भाषणों में सुना देते हैं पब्लिक की मीटिंग में और यहां कि हम इनके लिए सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और इनकी सेवा ही भगवान की पूजा है, उसमें कुछ नहीं है। जनता-जनार्दन के सड़े अंग को वे उठाना चाहते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए धन दे रहे हैं। हमको आजाद हुए १५-१६ साल हो गये। और यह बजट एक एक साल में निकलता है, उसके आंकड़े भी हम देखते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार यह कहा कि आदिवासियों के लिए हमने शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा काम किया है। मैं यह मानता हूं कि किसी समाज में यदि शिक्षा का स्तर नहीं उठे तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका आर्थिक और दूसरे प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन गये साल जब मैं बोला था तो मैंने कहा था कि आदिवासियों के साथ बेकारी बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ नहीं है। मैं आज भी बलपूर्वक कहता हूं नम्रता के साथ कि यहां पर हमको ऊंचे शब्दों में ऊंची हिन्दी में भुलावा दे सकते हैं, समय को टाल सकते हैं, लेकिन ऐसी वस्तुस्थिति छिपी नहीं रह सकती है। वस्तु स्थिति यह है कि जब आदिवासियों की शिक्षा का सवाल लेते हैं....अध्यक्ष महोदय, मुझे समय ज्यादा ही देंगे, मैं आप से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप चिन्ता न करें बोले जाइये।

श्री **ललित मोहन** : शिक्षा के बारे में यह है कि आपने होस्टल खोल दिये, लेकिन वहां पर लड़कों को खाना बिल्कुल खराब मिलता है। जिस स्टैण्डर्ड का विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। जो मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रियों के बच्चों के बारे में अच्छी व्यवस्था रहती है कि उनको समय पर दूध मिलता है, कार में समय पर स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन आदिवासियों के लड़कों को होस्टल में सड़ा-गला खाना मिलता है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि दूसरी संस्थाओं में देश का बहुत सा पैसा बरबाद हो रहा है वह बिल्कुल सही है। सेन्ट-पर्सेन्ट वह बात सही है। वहां पर जो दलाल बैठे हुए हैं,

(श्री ललित मोहन)

मुझे मजबूरी से ऐसा शब्द कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो हर संस्था में कोई महिला परिषद् बना दी और उसने होस्टल डाल दिया, लेकिन वहां जो दलाल बीच के हैं वह पैसा ले लेते हैं और लड़कों को अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं। उस पैसे को अपने निजी काम में लेते हैं। उनको सड़ी-गली दाल और मक्का की रोटियां देते हैं। मारवाड़ में बाजरी होती है तो वहां बाजरी की रोटियां देते हैं और इधर हमारे यहां मक्का मिलती है तो मक्का की रोटियां देते हैं। इसके कारण से जो शिक्षा में तरक्की होनी चाहिए थी इन १५ सालों में, इस समय में जो अन्य देश तरक्की कर पाये हैं, वैसी हमारे यहां नहीं हुई है। यह हमारे प्रति उपेक्षा बरती जा रही है।

मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं और मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा है कि साढ़े बारह पर्सेन्ट सर्विसेज में जो आदिवासियों और हरिजनों को लेने का सवाल है उस हिसाब से वे नहीं लिये जा रहे हैं। वे दर-दर भटकते फिरते हैं। मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब के पास जाओ और सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं तो वह ध्यान नहीं देते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि एम० ए० पास लड़के भटकते फिरते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के वे घर जाते हैं तो वे कहते हैं कि कल आ जाना और कल गया तो कहा कि परसों आ जाना। फिर गया तो कहा कि भाई मैं क्या करूं? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। रात-दिन भाषणों में आप कहते हैं, लेकिन होता क्या है? आप कहते हैं कि लड़के नहीं मिलते हैं। और असल बात यह है कि लड़के होते हुए भी लड़के नहीं लिये जाते हैं। उनके लिये कहा जाता है कि वे थर्ड क्लास हैं। तो उनको किस तरह का खाना मिलता है। उनको अगर अच्छा खाना मिलता तो फर्स्ट क्लास में आते, सेकण्ड-क्लास में आते। आप बहाना बना देते हैं कि थर्ड में आ गया। नम्बर अच्छे नहीं हैं। आपको मैं बताऊं कि सोशयल वेलफेयर विभाग आपने खोल रखा है। वहां पर जो लोग लगे हुए हैं, वे ऐसे हैं कि पहले से नौकरी में लगे हुए थे उनको आप निकाल नहीं सकते, इसलिए लगा रखे हैं। हमारा एक लड़का बी० ए० पास है, उसको वहां पर लगाने की जगह नहीं है। उसमें भी ऐसा है कि जो साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन है उसकी वे निगरानी तो रखें। वे यह नहीं देखते हैं कि आदिवासी लगे हुए हैं कि नहीं। एक आदिवासी वहां पर १० साल से लगा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। क्योंकि यदि नाम लेता हूं तो उसको हरेस कर सकते है। वह अभी तक टेम्प्रेरी में ही पड़ा हुआ है। पहले जो धारीवालजी मंत्री थे उनका कोई रिलेटिव था उसके लिए उसको हटाने की कोशिश की तो उधर बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के, वे गये और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को रिक्वेस्ट की कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अलग हो जायेंगे। धमकी तो नहीं लेकिन नम्रतापूर्वक कहा तब जाकर उसको रखा नहीं तो निकाल दिया जाता। मैं जोरदार शब्दों में कहता हूं, और आपकी

(श्री ललित मोहन)

आज्ञा शिरोधार्य है और आपसे (श्री अध्यक्ष) भी निवेदन करता हूं कि खास तौर से जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनका जंगल के साथ गहरा सम्बन्ध है। वहां आपने लाकर ४०) रुपये के हल लाकर रख दिये कि खेती करो। हमारा जंगल का बहुत सम्बन्ध है। हम वहां गोंद इकट्ठा करके और शहर लाकर बेचते हैं। वह हमारी आजीविका का साधन है। आप उसे हमसे छीनने जा रहे हैं। यहां हमारे भील भाई भीखाभाई बैठे हैं वे भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या करें? बेचारे वे परेशान हैं। उनको सुखाड़िया साहब का मुंह ताकना पड़ता है और उनके हुक्म में चलना पड़ता है। आदिवासी लोग चाहे खड्डे में जाये लेकिन उनके हुक्म की उदूली नहीं होनी चाहिए। आज जंगल बरबाद हो रहे हैं। हम जंगल से एक लकड़ी लाते हैं ५ आने की और उसका हल बनाते हैं तो वह एक रुपये में तैयार हो जाता है और हमारे छोटे-छोटे बैलों से उसके द्वारा खेती करते हैं तो उस सम्पत्ति से हमको अलग कर दिया है और कहते हैं कि बेटा लो, इससे खेती करो। हमारे जो पुराने साधन हैं उनसे हमको महरूम रखा जाता है। जंगल बरबाद कर दिये। हमारे यहां के किसानों के बैल कमजोर हैं। वे उस अंग्रेजी हल से खेती नहीं कर सकते, किसान उस हल को खरीद नहीं सकते। इसकी तरफ़ ध्यान नहीं, हमारे मिनिस्टर को इसका ध्यान नहीं। इसलिए मैं आपके द्वारा इस सरकार को बताना चाहता हूं, यद्यपि उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमारे यहां एक कहावत है कि "राखोड़े पर घोड़ो दोड्यो और राखोडो उड्यो" इनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है कि उस पर कोई असर नहीं होने वाला है कितना भी करो। इनका इलाज तो वही होगा जैसा कि महुआ में हुआ है। ये कितनी ही गम्भीरता से भाषण देते हैं लेकिन आम जनता यह महसूस करती है कि यह बीमारी बढ़ रही है. इसको हटाये बिना कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि शिक्षा के बाद में इसकी चर्चा है कि जंगल बरबाद हो रहा है वे बरबाद नहीं होने देने चाहिये।

यातायात के साधनों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जमाने में, चाहे शिड्यूल्ड एरिया में हो, चाहे और जगह हो, विकास के आधार पर यातायात के साधन बढ़ाना जरूरी माना गया है। शिड्यूल्ड एरिया में, पिछड़े इलाके में, इनके दोस्त, मिलने वाले, सगे सम्बन्धी और पार्टी के लोग हैं उनको इन्होंने परमिट दे रखे हैं और वे लोग अपनी पुरानी मोटरों को वहां पर चलाते हैं जो दस-दस दिनों तक खराब पड़ी रहती हैं। मैं कोटरा ९ तारीख को गया था वहां भी मैंने इसी तरह की हालत देखी। कोटरा से अगंवाली, उदयपुर से सागवाड़ा, उदयपुर से मनपुरा आदि रूट्स पर चलने वाली गाड़ियां ठीक नहीं हैं। लेकिन इन पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं है। लोगों ने कई बार दरख्वास्तें दीं, आर० टी० ओ० को कहा, कलेक्टर को कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ये लोग तो खाली वोट का ध्यान रखते हैं। वोट कहां मिलेंगे? इस बात का उनको ध्यान रहता है और वोट ही इनका मेन परपज रह गया है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का मामला हो मेन ध्येय इनका यह रह गया

(श्री ललित मोहन)

है कि वोट मिलेगा या नहीं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक शोषण हो रहा है। वह इस प्रकार से कि जहां हमारे शिड्यूल्ड एरिया को घोषित करने और रिजर्वेशन का सवाल है वहां ये लोग तहसीलदार से मिल कर आंकड़े गलत बता देते हैं। आज रिजर्वेशन के सवाल को सही तरीके से और गहराई से देखा जाय और डिटेल में जाया जाय तो ज्यादातर गलत आंकड़े बताये जाते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ यही हो रहा है। आप नोट लगाकर इसकी जांच करावें तो सही हालत का पता चलेगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य ने एक शब्द कह दिया तो उस शब्द पर आपने इतना गौर कर लिया। शब्द पर इतनी तत्परता बता कर दोष लगाने और उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। और डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को मोशन लाने की जरूरत नहीं है। मन्त्री लोग भी कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं। गलत बातें भी यहां पर बता देते हैं ये लोग। यहां पर इस तरह की बातों से काम नहीं चलेगा। आप तो जनता का आर्थिक ढांचा ऊंचा उठाने की बात करिये। सत्य की परम्परा डालिये; भ्रष्टाचार को दूर करिये। उन्होंने माफी भी मांग ली है। शब्दों के हेर फेर से बड़ी बात होने वाली नहीं है।

यह कहा जाता है कि इस इलाके के लिये सुखाड़िया जी ने बहुत कुछ किया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए दबे हुए लोगों के लिये अगर कुछ किया है तो मैं समझता हूं ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उदयपुर सिटी में कुछ हो गया हो, वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया है लेकिन वहां की जनता का पेट उससे भरने वाला नहीं है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने वाली नहीं है।

यह भी कहा जाता है कि उदयपुर के आदमी हैड ऑफिस में, और ऊंचे पदों पर बहुत हो गये हैं। ठीक है कोई आदमी काबिल है, तो हो सकता है। जयपुर के आदमी भी काबिल हों तो सेन्टर में पहुंच जायं। उदयपुर के हैं, कोटा के हैं, और वे काबिल हैं, और हो गये हैं, तो ऐसी हर्ज की कोई बात नहीं है। पहले बंगाली डाक्टर बहुत हमारे यहां भी हुआ करते थे। बहुत से लोग बंगाल के यहां पर मिलते थे। वे काबिल हैं इसलिए आते थे। इसलिये यह बार-बार कहा जाय कि उदयपुर के लोग बहुत हो गये हैं, यह सही नहीं है।

आपको नम्रता से निवेदन करता हुआ यह आशा करता हूं कि आदिवासियों या ट्राइब्स के लोगों की ओर आप अवश्य ध्यान देंगे। मिनिस्टर को बार बार आगाह करने के लिये आपको कहता हूं कि आप इनको सम्भालिये नहीं तो ये बहुत खतरनाक हैं। करने के काम तो वे करते नहीं हैं और दूसरे दूसरे काम करते हैं और अपना टी० ए०, डी० ए० ज्यादा कमाते हैं। मोटरें दौड़ाते हैं। जहां देखो वहां इनकी स्टेट कार खड़ी मिलती हैं। ये जनता के धन का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। इसके लिये नियम होने चाहिये। इतना कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No. 39

(श्री अध्यक्ष)

और फिर श्री गोकुल प्रसाद।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के १९६४—६५ के बजट पर पिछले पांच दिनों से बहस इस सदन में चल रही है। बहस में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने अधिकांशतः यह बजट समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, इस बात को दोहराया है। मैं यहां पर उस बात को नहीं कहना चाहता। लेकिन माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस बजट में जहां अमेरिका के प्रेसिडेन्ट को याद किया वहां भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति को याद क्यों नहीं किया? यह उनकी अपनी निष्ठा और श्रद्धा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट तैयार किया है, उन्होंने उसमे लिखा है कि यह बजट राज्य की बड़ी नाजुक परिस्थिति में तैयार किया जा रहा है, नाजुक परिस्थिति में, नजाकत की भाषा में और नाजुक हाथों से, मगर कठोर हृदय से यह बजट जो उन्होंने पेश किया सदन के सामने और जिस के सम्बन्ध में उधर से बोलने वाले सदस्यों ने और इधर से भी, पिछले ५ दिनों में बहस में भाग लेते हुए अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। कल कृषि मन्त्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि विरोधी दल के सदस्य सरकार पर आरोप ऐसा लगाते हैं और फिजा पैदा करते हैं जैसे समुद्र में व्हेल मछली होती है जिसके मुंह में धुंआ निकलता है, लेकिन होशियार शिकारी होता है वह ताक कर निशाना लगाकर उसका शिकार करता है। यह शिकार इधर होता है या नही लेकिन यह सही है कि पिछले दिनों दो बार उन्होंने इस्तीफा देकर राजस्थान में फिजा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन कुशल शिकारी सुखाड़िया ने ऐसा तीर मारा उनको अपने साथ आस्ट्रेलिया और अमेरिका ले जाकर, कि हमेशा के लिए उनको अपने पास बैठा लिया। व्हेल मछली का सा उन्होंने किया होगा नाटक।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जब किसी बात का सवाल खड़ा होता है तो इन सारी बातों को दबाने के लिए, राजस्थान के भविष्य, पंचवर्षीय योजनाओं और विकास का नाम लेकर सारी गतिविधियों का संचालन करना चाहती है। मगर, अध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री जी ने राजस्थान राज्य के जो आंकड़े राजस्थान के माली हालत के और विकास के सदन में पेश किये, मैं इतना तो कहना चाहता हूं, कि वे आंकड़े किस हद तक सही हैं यह तो आगे आने वाले वित्त मंत्री कहेंगे, लेकिन इस सदन के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री हरिभाऊजी ने जो आंकड़े पेश किये थे उनके बारे में हमको यह जानकारी हो गई कि वे आंकड़े कितने गलत थे। यहां यह बताना, उनका राजनैतिक विरोध है या नहीं—यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन राज्य के आंकड़ों का और सही हालत का उनको ज्ञान नहीं था यह आपके भाषण से सिद्ध हो गया। राज्य कितनी कठिन माली हालत से गुजर रहा है इसकी जानकारी उन्होंने देने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कृषि है। राज्य की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

२६ पर्सेन्ट आमदनी कृषि से होती है। राज्य को २६ पर्सेन्ट आमदनी खेती-बाड़ी देती है और २६ पर्सेन्ट आमदनी देने वाली खेती बाड़ी के संबन्ध में मुझे सख्त अफसोस इस बात का होता है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कल आंकड़े पेश किये उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और सदन के सामने यह बात नहीं रखी कि पिछले दो सालों में किस प्रकार राजस्थान की पैदावार गिरती जा रही है। उन्होंने आंकड़े पेश किए टोटल प्रॉडक्शन के। हो सकता है कि टोटल प्रोडक्शन के कुछ आंकड़े बढ़े होंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के युग में, आज की योजना और विकास के युग में पर-एकड़ पैदावार बढ़ना विकास होने का मापदंड है। टोटल प्रॉडक्शन से आप सही अन्दाज नहीं लगा सकते। उसके साथ पॉपूलेशन बढ़ती है, एरिया ऑफ प्रॉडक्शन बढ़ता है। सवाल यह है कि खेती-बाड़ी उत्पादन के सिलसिले में राजस्थान में पर-एकड़ ईल्ड गिरी है या बढ़ी है? मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की पर-एकड़ ईल्ड बुरी तरह गिरी है। लेकिन इसमें इतने अफसोस की बात नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान के सारे राज्यों से यदि राजस्थान की पर-एकड़ ईल्ड सबसे कम हैं तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक शर्म और अफसोस की बात हो नहीं सकती। हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के बारे में १९६०-६१ में नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड साईंसेज एण्ड रिसर्च की ओर से लोकनाथन ने रिसर्च किया, सारे स्टेट्स की एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के आंकड़े इकट्ठे किये, उनके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, उस कौंसिल ने रिपोर्ट में कहा है कि सारे हिन्दुस्तान भर के अन्दर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, पर-एकड़ प्रॉडक्शन केरल के अन्दर सबसे ज्यादा है ५२२, और राजस्थान के अन्दर सबसे कम है ८४। सारे हिन्दुस्तान की रियासतों का यदि एवरेज १०० माना जाय तो सौ रुपये सारे प्रान्तों के अन्दर हो तो राजस्थान का, अध्यक्ष महोदय, ४५ रुपया आता है। इतना ही नहीं, आउट पुट पर–एकड़ के बारे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है :

"In case of all-India output per acre, the range of variation was great. Madhya Pradesh and Rajasthan being on the lowest rung of the ladder."

अध्यक्ष महोदय, नेट-आउट के सिलसिले में आज हिन्दुस्तान में सारी रियासतों में राजस्थान का राज्य ऐसा है जो लोएस्ट लेवल पर आता है, पर-एकड़ नेट आउट–पुट सबसे कम है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसका कोई कारण है तो वह यह हो सकता है, मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा, कि राज्य को आमदनी में २० प्रतिशत कृषि से आमदनी आती है और खेती-बाड़ी का उत्पादन १९६२-६३ में कम हुआ है, १९६३-६४ में कम हुआ है। सबसे लोएस्ट पर-एकड़ ईल्ड है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की माली हालत को यदि सुधारना है, विकास के दृष्टिकोण से कुछ करना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि खेतीबाड़ी की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये, यह टॉप प्रायोरिटी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, और टॉप प्रायोरिटी का डिपार्टमेंट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्य के हैड के पास होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री जी में राजस्थान का भविष्य उज्जवल बनाने की कामना है और यह आकांक्षा लेकर चलना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसा कि केन्द्र का आदेश है, स्वयं मुख्य मंत्री को अपने हाथ में रखना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वे इन्कास्पीटेन्ट हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिनों दिन के प्रशासन में आने वाली तकलीफें, रेड टेपिज्म और फेवरिटिज्म के कारण आने वाली जो दिक्कते हैं वह अगर यह डिपार्टमेंट राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव हैड के पास रहेगा तो वह आने वाली रोज की दिक्कतें दूर हो जायंगी। जैसा केन्द्र का संकेत है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन की पोर्टफोलियो है वह मुख्य मंत्री को लेनी चाहिए। यह हो सकता है कि वे ऐसे ही विभाग लें जिनमें ज्यादा एक्टीविटीज हों, जैसे होम डिपार्टमेंट लिया है, उसमें पुलिस पर हुकूमत चलती है तो पुलिस तो वैसे भी आपके मातहत रहती है। आपको मुख्य मंत्री होने के नाते आज भी सलाम करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कन्सेन्ट्रेशन ऑफ पोलिटिकल पॉवर अपने हाथ में लिया है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, और होम की पोर्टफोलियो, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह लेकर, वैसा हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नही है, किसी में रेवेन्यू और होम मुख्य मंत्री के हाथ में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पॉवर की दृष्टि से अपने पास रख सकते हैं लेकिन अगर राजस्थान की माली हालत को सुधारना चाहते हैं तो माली हालत को सुधारने, उत्पादन को बढ़ाने और भविष्य की उज्जवल कामना करने की दृष्टि से राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन तीव्र गति से करने और उपज को बढ़ाने के लिए मुख्य खेती बाड़ी की ओर ध्यान देना होगा। यह महकमा शुष्क है, नीरस है और इसमें पलिटिकल पॉवर नहीं है, रोब दोब घटने के कारण उन्हें खुशी नहीं होगी और कोई किसान नहीं बनना चाह कर थानेदार बनना चाहेगा। किसान वही बनेगा जिसमे कुछ करने की आकांक्षा है, राजस्थान का भविष्य उज्जवल करने की कामना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेतीबाड़ी की दृष्टि से, हमें इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान के अन्दर विकास की बात कितनी ही की जाय, इस सदन में कितनी ही चर्चायें हों, चम्बल के एरिया की बात करें, राजस्थान के भाखरा एरिया की बात करें, सूरतगढ़ फार्म की बात करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो विकास का काम हो रहा है उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं। जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है।

हम राजस्थान का नक्शा सोच कर चल रहे है, इस विकास के अन्दर जो बड़ी बड़ी पूंजी खर्च की है उसका फायदा आजकल में नही मिलने वाला है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नहीं मिलने वाला है। १९७० तक जाकर, सात साल के बाद, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में जाकर जितना केपीटल इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ मिलेगा। क्या राजस्थान के लोग उस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समय तक भूखे रहें ? क्या राजस्थान की दो करोड़ जनता, राजस्थान की बढ़ी हुई आबादी १६७० तक इस बात का इन्तजार करेगी कि राजस्थान सरकार ने कैपीटल इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किया है, उसका फायदा १६७० में मिलेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को अपनी इकोनोमी में बेलेन्स रखना चाहिए और राजस्थान में वर्तमान की आवश्यकता है कि लघु सिंचाई कार्यक्रम हो जिससे प्रोडक्शन इमिजियेटली बढ़ सके। इस प्रकार की योजनाओं के बारे में विचार करके अपनी योजना का हमको निर्माण करना चाहिए। इस डिसीजन के द्वारा, इस निर्णय के द्वारा तुरन्त जो -श्यकता लोगों की है उसको इमिजियेटली और स्ट्रिक्टली पूरा किया जा सकता है। हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो भूतकाल की नदारियों का और भविष्य के प्रावधानों का ख्याल रखते हैं और फिर बजट बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि राजस्थान जिस प्रकार की माली हालत में से गुजर रहा है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, इस दृष्टि से विचार नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि भूतकाल की देनदारियों के बारे में सदन को जानकारी होनी चाहिए। आज राजस्थान के ऊपर २ अरब ६२ करोड़ रुपये का कर्जा है, १६२ करोड़ के पब्लिक डेट राजस्थान के ऊपर हैं और राजस्थान की माली हालत ऐसी है कि जिसमें हमें एक साल का ६ करोड़ रुपया ब्याज चुकाना है, उसमें से साढ़े तीन करोड़ रुपया ही ब्याज चुकाया है, ढाई करोड़ रुपया ब्याज का नहीं चुका सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह परिवार और वह व्यक्ति जो समय के ऊपर कर्ज का ब्याज नहीं चुका सकता उस परिवार और व्यक्ति की बुरी हालत होती है चाहे उसके पास कितने ही असेट्स हों, कितना ही कैपीटल इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी हवेली हों कारखाना हो, मोटर हो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो पूंजी ली है उस पर ब्याज नहीं चुका सकता, उसके पास इन्सोलवेन्सी के लिए कोर्ट में जाने के अतिरिक्त और रास्ता नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान को हम एक दिवालिया स्टेट बनाना चाहते हैं? क्या राजस्थान सरकार और वित्त मंत्री को अपनी देनदारियों के बारे में ख्याल नहीं है। आप यह ख्याल रखते हैं कि आप केन्द्र को पैसा दे दें, राजस्थान के विकास की योजनाओं में कटौती कराते हैं लेकिन केन्द्र को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि उसमें से वह कुछ छोड़ दे, कुछ राइट ऑफ कर दे। उसमें से कुछ खत्म कर दे, कर्ज में कुछ कम कर दे। राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस बात में बड़ी माहिर है कि राजस्थान सरकार का लाखों करोड़ों रुपया बकाया पड़ा रहे, लोगों में बकाया रकम पड़ी रहे, उसका वे दुरुपयोग करते रहें, मिस-एप्रोप्रियेशन करते रहें, एम्बेजलमेंट करते रहें—इस के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार सोचती नहीं। सहकारी समिति, खादी घर में, भारत सेवक समाज में और अन्यान्य समाज में इस प्रकार दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रियेशन और एम्बेजिलमेंट होता रहे लेकिन राजस्थान सरकार अपनी बकाया वसूल नहीं कर सकती। आज राजस्थान सरकार और वित्त मंत्री टैक्सेज प्रपोजल्स सदन में लाते हैं, लेकिन

Page No. 43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान सरकार की कितनी बकाया है, उसका अनुमान नहीं लगाते। उसका अनुमान लगायें और वह कैसे वसूल की जा सकती है इसका अनुमान लगायें। लेकिन मुझे अफसोस है कि राजस्थान की माली हालत को राजस्थान के वित्त मंत्री इस प्रकार नहीं सुलझाते और जिन लोगों में बकाया है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं। जिसको अपनी देनदारियों का, अपने पैसे का पता नहीं वह साहूकार नहीं होता। आप अपने आप को साहूकार नहीं कह सकते। जो लोगों को कर्ज देकर बट्टे खाते में डाल दे, राइट ऑफ कर दे वह साहूकार नहीं मूर्ख होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार के सामने अपनी बकाया को वसूल करने का सवाल नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार ने एक अधिकारी को मुकर्रर किया इस काम के लिए कि राजस्थान सरकार की कितनी बकाया बट्टे खाते में डाली जा सकती है। अधिकारी इसके लिये मुकर्रर नहीं किया जा सकता कि कितनी बकाया है, उसको किस प्रकार वसूल किया जा सकता है; बल्कि आपने अधिकारी इसलिए मुकर्रर किया कि कितनी बकाया बट्टे खाते में डाली जा सकती है?

अगर हजार या कोई लाख हो तो भी बर्दाश्त किया जा सकता है। मगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि बट्टे खाते १० करोड़ ९१ लाख रुपया डाला जाता है। यह समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम बट्टे खाते डाली जाती है।

(विराम)

लेकिन आप उस बकाया रकम की वसूली करने के लिये ऑफिसर मुकर्रर नहीं करते है। आप ऑफिसर मुकर्रर करते हैं बट्टे खाते रकम डालने के लिये। अध्यक्ष महोदय, अगर इसके आंकड़े कौल साहब चाहेंगे, तो मैं बता दूंगा। अगर इसी तरह से हम चलते रहे और जो रकम लोगों में मांगते हैं वह वसूल न कर पाये और देने हैं उनको तो हमे देने ही पड़ते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? आपने बजट पेश किया है और वाह वाही लूटी है। आपने चारों तरफ से वाह वाही लूटी है यह कह कर कि आपने गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगाया है इस नये बजट में। इस नये बजट में आपने पूंजीपतियों पर और बड़े-बड़े लोगों पर टैक्स लगाये है, मगर मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस और पूंजीपति आपस में एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं—ये शब्द बिड़लाजी ने कल अपने भाषण में कहे है। उनके शब्दों से मालूम होता है कि समाजवाद आसानी से जिन्दा नहीं रह सकता। वे कहते हैं कि कांग्रेस और हमारा ५० वर्षों का संबंध रहा है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस का या तो मतदाताओं से या धनदाताओं से काम पड़ता रहता है। दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं। कांग्रेस की नीति हैं राजनैतिक नारा देना और जनता से वोट लेने के लिये कांग्रेस ने हमेशा नारे दिये हैं, कांग्रेस के शासन में चाहे कुछ करें लेकिन बाहर तो कांग्रेस की नीति जब वे मंच से भाषण देते हैं हमेशा यही कहते हैं कि हम बेकारी और बुर्जुआओं को दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते है कि राजस्थान में कितना हाउसिंग स्कीम के लिये रुपया दिया भूमिहीन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसानों को, लेन्डलेस लेबरर्स जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, उनको जिनके लिए १२॥ करोड़ रखे गये हैं । लेकिन आप उनको इसके लिये रुपया नहीं देते । राज्य के गावों में जो भूमिहीन लोग हैं, उनको मकान बनाने के लिये शत प्रतिशत सेन्ट्रल गर्वमेन्ट ने लोन्स देने की तीसरी प्लान मे व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि, यह सारा का सारा····

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं आप बतादें कि हाउसिंग के लिये सेन्ट-पर्सेन्ट की कौनसी स्कीम है सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: मैं आपको बताता हूं ।

रूरल हाउसिंग स्कीम में प्राविजन रखा १२.७ करोड़ और पहले साल में ६६ लाख का खर्चा हुआ और तीन साल में २.९ करोड़ खर्च हुआ । इसके मायने यह हुए कि कुल आय का २५ पर्सेन्ट ऑफ दी प्लान प्राविजन खर्च हुआ । सारी स्टेटों को कहा गया था कि हाउसिंग स्कीम के लिए लेन्डलेस लेबरर को सेन्ट परसेन्ट सब्सिडी देंगे । यह सेन्टर की तरफ से कहा गया, अध्यक्ष महोदय, आज यह हालत है कि आप हाउसिंग स्कीम के लिए रुपया मुहैय्या नहीं कर सकते । सेन्ट्रल गर्वमेंट ने एक दूसरी स्कीम क्लीअरेन्स की पास की जो राजस्थान की आज गन्दी बस्तियां हैं उनको सुधारने के लिये, मगर उनमें जाकर रह कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वे इतनी गंदी हैं कि कोई रह नहीं सकता । तो उसके लिये दिये हुए पैसे का उपयोग भी सरकार नहीं कर सकती । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रहवास करने वाले हजारों लोग हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है । आप प्लाट के लिए टैक्स की बात करते हैं । मकान है तो कर्जा नहीं और कर्जा है तो म्युनिसिपेलिटीज की इजाजत नहीं और पैसा नहीं तो छोड़ने का वक्त आता है । क्या आपने कभी मनुष्यता के दृष्टिकोण से इस पर विचार किया है ? क्या आप राजस्थान के लोगों को ये सारी सुविधाऐं दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज केवल नारे देने से नहीं होता । यह तो वास्तव में कार्य करने से आता है । समाजवाद का नारा रखा है वह इस तरह का है जैसे मच्छरदानी है इसमें मच्छर नहीं आ सकते ! इसी तरह से इसमें समाजवाद नहीं आ सकता। आप कहते हैं समाजवाद है । क्या आपने फुट-पाथ पर सोने वालों के लिये कोई व्यवस्था की है ? क्या आपने चौड़े रास्ते से सिविल लाइन जाते समय सिविल लाइल पर झोपड़ियों मे रहने वालों की तरफ देखा है ? आप आज प्लॉट को एक्वायर करते हैं । मैं कहूंगा कि इससे बड़े लोगो को ही फायदा होगा । इसके बाद आप उस जमीन को दो रुपये गज पर एक्वायर करते हैं । धनी-मानी लोगों को १० रु० गज में देते हैं । आज आपने जनता कॉलोनी के नाम से प्लॉट दिये हैं । क्या आपने जनता को खरीदने के लिये सुविधाएं दी हैं ? क्या आपकी गरीब जनता प्लॉटों को खरीद सकती है ? आज आप देखेंगे कि प्लॉट का भाव १८) रु.

Page No. 45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गज का है। आपने नाम दे दिया जनता कॉलोनी और आप उसको कहते हैं जनता कॉलोनी। आप बतावें कि क्या वहां पर किसी सर्विस क्लास के व्यक्ति को प्लॉट मिले हैं? नोन इन्कम टैक्स वाले को कोई प्लॉट मिला है? प्लॉट मिले हैं तो बड़े २ धनवानों को। आपने १८)रु. गज के भाव से जमीन दी और आपने उसके किये नारा दिया जनता कॉलोनी। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आज राजस्थान सरकार ने एक रुपया टोकन किराये पर जमीन दी है गवर्नर के आदेश से। हर जगह गवर्नर महोदय ने स्पेशल आर्डर निकले हैं कि टोकन एक रुपये किराये पर जमीन दी जावे। राजस्थान सरकार बड़े बड़े लोगों को इस प्रकार टोकन किराये पर मकान के लिये जमीन दे देती है। अध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है इस राज्य में? कोई देखने वाला नहीं हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की हजारों बीघा जमीन जो रेकार्ड में चाही भूमि के नाम पर दर्ज है यदि वह बट जावे और राजस्थान सरकार को इत्तिला नहीं होती है तो यह बड़े शर्म की बात है। राजस्थान सरकार का जोर चलता है तो छोटे से कर्मचारी पर। वह एक छोटे से कर्मचारी को मोअत्तिल कर देती है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। एक घटना जयपुर के पास की है। यहां पर सांगानेर तहसील है उसमें Engineering College बन रहा है। इसके लिये राजस्थान की सरकार ने कुछ जमीन दी लगभग ३१८ बीघा जो १० लाख गज जमीन होती है। वह सिवाय चक जमीन है। यह ठिकाने की जमीन है और ठाकुर नाबालिग है। सदन को जानकर, अध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब होगा कि १० लाख गज जमीन कॉलेज के लिये दी जाती है यदि उस जमीन का मुआवजा एक रुपये, प्रति गज के हिसाब से दिया जाय तो भी १० लाख होता है और प्लॉट की इजाजत दी जावे तो एक करोड़ रुपया होता है। जमीन सिवाय चक में रेकार्ड में दर्ज है। इसके लिए कॉन्सिप्रेसी बनाई गई। तहसीलदार वहां का छुट्टी पर गया हुआ था। वह १५ दिन की छुट्टी पर था। उसके स्थान पर एक नायब तहसीलदार जिसको रिवर्ट कर दिया गया था काम करने के लिये लगाया और उसने उस जमीन पर मकान बनाने की इजाजत दे दी।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, १० लाख गज जमीन। मैं मानता हूं। मुझे शाम को ३॥ बजे इस बारे में सूचना मिली। मैंने ४॥ बजे चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया कि क्योंकि सदन तो था नहीं मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने जांच कराई और दूसरे रोज नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप यह समझते हैं कि तहसीलदार ने यह किया? क्या यह १५०) तनख्वाह पाने वाला तहसीलदार इस प्रकार का घोटाला कर सकता है? यह १० करोड़ का घोटाला वह नहीं कर सकता। यह तहसीलदार की हिम्मत नहीं। इसके अलावा यह नायब तहसीलदार तो पहले ही रिवर्ट हो चुका था। १५ दिन के लिये वह लीव में जो तहसीलदार वहां पर गया था उसको ओफिसियेट करने के लिये गया था। मैं अपनी जानकारी सदन को देना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं कि इसमें किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। जहां तक मेरी जानकारी है वह भारत सरकार की सेवा में नहीं है। उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी ? ये पहले राजस्थान सरकार की सेवा में थे। पहले इत्तिला दी, ये हमारे माननीय मेनन साहब भूतपूर्व बोर्ड ग्राफ रैवेन्यू के चेयरमैन, उनका इसमें हाथ है। जागीरदार तो नाबालिग है और वह १२ साल का बच्चा है उसकी कोई देख-भाल करने वाला नहीं। आपने उसको कहा कि १० लाख का जमीन का मुआवजाव दूसरी सारी कम्पेन्सेशन दिलावेंगे। जमीन दिलावेंगे, यह होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ मिनिस्टर से कि तहसीलदार को सस्पैन्ड करने से काम नहीं चलेगा। आप आगे क्या कर सकते हैं इसको आप ही देख सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस संबन्ध में स्पेशल अधिकारी नियुक्त करें और जांच करावें। आपने इस संबन्ध में तुरन्त कार्यवाही की, उसके लिये धन्यवाद।

मैं आपको इस सबन्ध में यह कहूंगा कि जो कार्यवाही करनी हो करें। अगर इस प्रकार की कार्यवाही राजस्थान की राजधानी जयपुर में होती रहे, ऐसे घोटाले यहां पर होते रहें, तो बाहर का क्या हाल होगा ? लोग चिल्लाते रहेंगे और आप उनकी जमीन को हड़प कर जावेंगे। वहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बन जावें, और आप यह कहें कि तहसीलदार मिल गया और उसने अपने नाम पर सारे काम कर लिये और आपके सीलिंग के कानून और ट्रान्सफर को इल्लीगल करने का कानून धरा रह गया। ये सारी बातें कैसे हुई ? यह सारी बातें किसने की सारी बातों को जांच करें। अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहां सारे मंत्रि-मंडल की बैठक है तो बाहर की हालत क्या होगी ?

अलवर का तेज टाकिज का सिनेमा ५०० रुपया महीना पर है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं इसका ५००० रुपया महीना दूंगा, वह सरकार को लिख कर भेजता है कि मैं इसका ५००० रुपया महीना देने को तैयार हूं। लेकिन कोई कृपा पात्र कहता है कि मैं जो ५०० रुपया देता हूं उसकी जगह २५०० रुपया दे दूंगा। ये सारे तथ्य मैं समय की कमी के कारण अभी नहीं रख सकता। मैं ये सारे तथ्य मुख्य मन्त्री जी को दूंगा। वित्त मन्त्री महोदय नोट करलें, राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, वहां राजस्थान की जितनी मिल्कियत है, राजस्थान के जितने एस्टेट्स हैं, प्रोपर्टी है, उनके प्रोपर यूटिलाइजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। यदि इनके प्रोपर यूटिलाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे तो राजस्थान को इन ऐस्टेट्स से काफी आमदनी होगी। यह पांच हजार का सिनेमा, अलवर का तेज टॉकीज, १० हजार रुपया महीना में जा सकता है, वह २५०० में जा रहा है। ३१ मार्च तक का पीरियड बढ़ाया है। इससे पहले पहले कार्यवाही नहीं की तो १० साल का ठेका २५०० रुपया माहवार में मिल जायगा और दस साल के लिये लीज होने के बाद सरकार कहेगी कि अब हम क्या करें ?.......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): सब रुका हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रुका हुआ नहीं है, फिर कह देंगे कि हम क्या करें? मैं पूछना चाहता हूं अजमेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का क्या हुआ? माथे पर हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। लाखों रुपया लगा कर चम्बल की बिजली अजमेर ले गये, पर अजमेर को चम्बल की बिजली नहीं मिली। बिजली के खम्भे गाड दिये गये। उन खम्भों पर बिजली के तार लगा दिये गये। उनमें करेंट पहुंच गया। पर अजमेर को चम्बल की बिजली नहीं मिल रही है। ऊपर से बाला बाला ही चली गई। ऐसा हिन्दुस्थान में और कहीं नहीं हुआ होगा। हाई कोर्ट में जीत कर भी आप देखते ही रह गये। हाई कोर्ट में आप के पक्ष में फैसला हुआ, अजमेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया। पर आप डर गये सिर्फ इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करदी, उससे आप डर गये। आज लाखों-करोडों रुपये की धनराशि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगती है। ब्यावर ले जानी थी तो आखिर आप अजमेर क्यों ले गये? वहां से खम्मे गाड कर वापिस ले गये यह क्या तरीका है आपका? क्या रवैया है आपका? फिर आप कहते हैं कि हम राजस्थान में समाजवादी राज्य स्थापित करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हम स्टेट ट्रेडिंग करेंगे। दरअसल यह सरकार पब्लिसिटी में विश्वास ज्यादा करती है। विजिलेंस कमेटी बैठाई पिछले साल। सरकार की एक चिट्ठी मेरे पास आई कि तुम्हें विजीलेंस कमेटी में रखना चाहते हैं। मेरे को उस चिट्ठी का जवाब देने में ७ दिन की देर होगई, इतने में सरकार का दूसरा पत्र आगया कि जल्दी जवाब दो। मैंने देखा कि वास्तव में सरकार जल्दी ही काम करना चाहती है पर आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि उस बात को डेढ साल होने आये, उसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। महंगाई बढ गई। मै कहूंगा कि महंगाई बढने में राजस्थान के वित्त मंत्री को स्वार्थ है। आप पूछेंगे कि क्या स्वार्थ है? तो मैं यह कहूंगा कि जितनी ज्यादा महंगाई बढेगी, जितनी ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा सेल्स टैक्स आयेगा। तो एक वित्त मंत्री के नाते, उनका यह स्वार्थ हो सकता है। पर राजस्थान के लोकतन्त्रीय शासन के पापुलर मंत्री होने के नाते, महंगाई बढने में उनका हित नहीं हो सकता। पिछले साल में बहुत अधिक कीमतें बढीं। मैं सरकार को चार्ज करना चाहता हूं, यह सरकार और ट्रेडर्स के बीच में कौन्स्पिरेसी थी। आपने महंगाई को रोकने की क्या कोशिश की? क्या आपने फूड ग्रेन्स डीलर्स लाईसेन्सिंग आर्डर का प्रयोग किया? नहीं किया। महंगाई को रोकने के लिये आप किसी तरह का प्रेशर नहीं लाये। सवाईमाधोपुर में बैंक ने व्यपारियों को पैसा देना बन्द कर दिया तो कीमतें चार रुपये नीचे आगईं। पर आपने कुछ भी नहीं किया। आपने कीमतें नीचे लाने की कोई कोशिश नहीं की, - और उसका नतीजा आज यह हो रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। राजस्थान की आम जनता पिस रही है। महंगाई से गरीब मजदूर, और कर्मचारी पिस रहे हैं। कर्मचारियों के लिये आपने महंगाई भत्ते में ५ रुपये की वृद्धि कर दी। क्या हो सकता है इन ५ रु० से? आपने रावत कमेटी बैठाई थी, उसकी रिकमन्डेशन्स मालुम है आप को? उसने रिकमन्ड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया था कि, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है, रावत कमेटी ने जो रिकमन्ड किया, मुख्य मंत्री जी को याद होगा · · ·

(१० .५५ म. पू.)

(राव श्री नारायन सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसने यह रिकमन्ड किया था कि प्राइस कन्डेक्स में १० परसैन्ट की इन्क्रीज हो तो सरकार को महंगाई में वृद्धि कर देनी चाहिये। आपने जो १४५ के फीगर्स दिये हैं, वे गलत हैं, इनको यदि सही मान भी लिया जाय तो ११० पर आपने महंगाई भत्ते में वृद्धि दी थी ६० में, आज आप के दिये हुए फीगर्स के अनुसार कीमतें १४५ हैं। तो इस हिसाब से आपको महंगाई भत्ते में लगभग ३५ परसैन्ट की वृद्धि करनी चाहिये। पर आप करने को तैयार नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ किया उसको मानने को तैयार नहीं। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने तो स्पष्ट तौर से कहा कि तनख्वाह बढाओ पर आपने वह भी स्वीकार नहीं किया। आपने कह दिया कि इससे हम पर बहुत ज्यादा बोझा पड़ेगा। फिर आपने लिमिट रखी है ३२० की। ३०० जिसकी पे है और डियरनैस है, उसको इससे कैसे फायदा मिलेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : बेसिक पे ३२० रुपये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डीयरनैस अलाउन्स उसमें मिलाने पर उसे कैसे फायदा मिलेगा क्या कभी वित्त मन्त्री ने इसे केल्कुलेट किया है ? सैंट्रल गवर्नमेंट ने ४९९ तक का सिटी कम्पैन्सेटरी अलाउन्स रखा है। आपको भी वही रखना चाहिये और महंगाई के लिए ३९९ रखना चाहिये। जितने ४८५ तक तनख्वाह पाने वाले नॉन गजेटेड एम्पलाई हैं उनकी संख्या १००० से कुछ ही ज्यादा जायगी · · ·

श्री बालकृष्ण कौल : इनको देने से एक करोड़ रुपये का खर्चा और ज्यादा बढ़ जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५० लाख मुझे दे दीजिये मैं बढ़ा दूंगा। फिर एक करोड़ हो भी जायेंगे तो क्या बात है ? वैसे ही आप ११ लाख रुपया बट्टे खाते में डाल देते हैं। ये आपके कर्मचारी हैं इनमें अगर असंतोष रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा नहीं रहेगा। आप राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक को करोड़ों रुपया दे रहे हैं, उसका क्या हो रहा है ? ४० लाख रुपये के राजस्थान गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और साढ़े आठ करोड़ रुपयों की गारन्टी दे रखी है। उस बैंक का कितना ओवर ड्यू है ? कितनी बकाया है ? जिस की साढ़े आठ करोड़ की आपकी गारन्टी है, ४० लाख के आपके शेयर हैं, १९६३ तक इस बैंक की ओवरड्यूज एक करोड़ आठ लाख होगई है, और और बढ़ रही है। किस हालत में बढ़ रही है ? झुंझनू बैंक का साढ़े आठ लाख का घोटाला एन्टी करप्शन के पास चल रहा है। पाली के कोऑपरेटिव बैंक में १८ लाख १५ हजार का घोटाला है, वहां दो मैनेजर हैं, आपस में झगड़ा है, जोधपुर कोआपरेटिव बैंक में २४ लाख ७१ हजार बकाया है। आज राजस्थान की पब्लिक का [illegible] इस तरह के इन्वेस्टमेन्ट में पड़ा हुआ है, जिसका [illegible] इन्ट्रेस्ट नहीं। फिर आप किन [illegible] स्टेट ट्रेडिंग करोगे ? प्रिन्टिंग का आपका खुद का डिपार्टमेंट है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपका खुद का प्रेस है। किन्तु राजस्थान विधान सभा की कार्यवाहियां आप दूसरे प्रेसेज से छपवाते हैं। जो आपके डिपार्टमेंट्स आपसे चलते हों वे ही संभालिए, फिर आगे क्यों लपकते हो? आप वास्तविकता के आधार पर विचार कीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात निवेदन करूंगा कि इस समय विजिलेंस कमीशन की मांग चल रही है। इस सदन में भी यह बात आयी।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा समय न लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे स्वयं भी समय का ध्यान है। एक बात कहना चाहूंगा कि इस सदन में एक मांग की गई कि राजस्थान की जनता का धन लूटने वाली कुछ ऐसी बोगस चिट फंड कंपनियां राजस्थान में आती हैं और सदन के सदस्यों ने मांग की है कि सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। आप उस संबंध में कुछ करें या न करें लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बढ़ती हुई मंहगाई और राजस्थान में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक आप इस पोलिटिकल करप्शन, राजनैतिक भ्रष्टाचार को बन्द नहीं करेंगे। आप इस सारी कैपीटलिस्ट क्लास से चन्दा वसूल करते हैं और वसूल करने के बाद आप उसके प्रेशर में रहेंगे। जो पैसा आप वसूल करते हैं उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। दुरुपयोग होता है। भयंकर दुरुपयोग होता है लाखों रुपयों का। अलवर के अन्दर ८ लाख रुपये नेहरूजी के नाम पर इकट्ठे कर लिए। ऐसे महापुरुष के नाम पर आपने इकट्ठे कर लिए। नेहरूजी का नाम उसके साथ क्यों जोड़ा? आपने उसका उपयोग क्या किया? क्या क्या हिसाब है? आप कहेंगे कि यह हमारा आन्तरिक मामला है। आपका आन्तरिक मामला यदि सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है तो सार्वजनिक जीवन पर उसके गहरे परिणाम होते हैं। आपको विचार करना होगा। यदि लोगों के धन का इस प्रकार दुरुपयोग होता है तो साधारण चीज नहीं। उस मामले में कोर्ट ने क्लीयर स्ट्रिक्चर्स पास किए। कैबीनेट की मीटिंग अलवर में २४ जनवरी, १९६० को हुई। उसमें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष थे, श्री मथुरादास माथुर थे, उन्होंने आश्वासन दिया मुख्य मंत्री के सामने। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके सार्वजनिक जीवन पर व्यापक असर पड़ते हैं। आज राज्य के अन्दर कर्मचारियों में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, जब तक आपकी रूलिंग पार्टी, उसके नेता, उसके अधिकारी और राज्य के कार्यकर्त्ता जीवन में सुधार नहीं लायेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता और इसलिये....

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार का क्या ताल्लुक है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार जिससे पैसा लेती है उसको ओब्लाइज करती है। आप १८ लाख रुपये आम चुनावों के लिए कलकत्ता से ऐसे ही नहीं, लाए। इंडस्ट्रीज की बोली लगती है नीलाम होते हैं। असर तो पड़ता ही है। आप यदि किसी का चाय का कप पी लेते हैं फिर चाहे कई दिन के बाद उसको भी आप पिलाते हों तो असर तो होता ही है।

एक माननीय सदस्य : आप भी चाय पिलाते हैं क्या?

Page No. 50

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पिलाता हूं तभी तो आप मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। सदन की जानकारी के लिये और माननीय मुख्य मंत्री के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन्स इस संबंध में क्या हैं ? आंध्र के अन्दर रेड्डी साहब इस्तीफा दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ग्राब्जर्वेशन्स पर, तो आपके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन्स आती हैं, विचार कीजिए। लिखते हैं:—

"As regards the accounts position I think it proper to observe that on the record of the present case lot of material has been brought against Shri Shobha Ram in particular and his group to some extent. Shri Shobha Ram is neither a party to this case, nor has he appeared as a witness. It will be, therefore, hardly proper to pronounce any final opinion in the matter, but I cannot help observing that looking to the manner in which the coupons were issued, the manner in which the rondition of accounts was delayed inspite of repeated protests. It may be stated that all was not well and that the conduct of some of the leaders of the party was not what it should have been."

आज हाई कोर्ट के जजमैण्ट्स आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ऐसा सर्टिफिकेट देती हैं। इसलिए कहता हूं कि आज ऐसे नेताओं को आप राजस्थान की जनता के विकास के काम देते हैं। आप कहेंगे कि यह कैसे रिलेवेण्ट है ? वह इसलिए कि आपने श्री शोभाराम को अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलवर का चेयरमैन बनाया जो पैसे का हिसाब नहीं रखता, जो डबल डबल कूपन्स छपवाए जिसकी डुप्लीकेट कॉपीज में, सीरियल नम्बर्स नहीं। आपकी डी. सी. सी. के खिलाफ जजमैण्ट हुआ है। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है। कूपन्स में सीरियल नम्बर डालने से इन्कार कर दिया। उन लोगों को आप विकास का काम सौंपें और उनको इम्प्रूवमैण्ट ट्रस्ट का चयरमैन बनाएं। जिसको अलवर की एक तिहाई जनता ने अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्यों ? ये आपकी डैमोक्रैटिक फीलिंग्ज हैं ? हर बात पार्टीज के आधार पर ? इंप्रूवमैण्ट ट्रस्ट्स करते क्या हैं ? वित्त मंत्रीजी आपने अर्बन लैंड पर टैक्स लगाया है। आपने कभी इस बात का विचार किया कि राजस्थान के अन्दर कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम चालू क्यों नहीं की ? आपने अरबन कम्युनिटी पर टैक्स लगाया। राज्यपाल महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि अर्बन डेवलपमेंट स्कीम चालू करेंगे, वह क्यों नहीं की ? आपने परेशान किया स्त्री और पुरुषों को, पढ़े-लिखे नौजवानों को। इस संबंध में एक डेप्यूटेशन मुख्यमंत्री से मिला था। आदर्शनगर की हालत देखिए। आप उसकी सड़कों की हालत देखिए तो क्या है ? जिन लोगों ने बड़े-बड़े रेत के टीबों को सुधार कर बड़े बड़े बंगले बनवाए, जिनके दुख और कुर्बानियों पर हिन्दुस्तान की आजादी का भवन खड़ा हुआ, उन लोगों की दुर्दशा पर नजर नहीं जाती। आपने कभी इस बात का फैसला नहीं किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से एक कमिटमेंट चाहूंगा कि आदर्श नगर आखिर किसकी जिम्मेदारी है ? यू. आई. टी., म्युनिसिपैलिटी, रिहेबिलटेशन या पी. डब्ल्यू. डी. ? आज तक इस बात का फैसला नहीं कर सके ? मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अन्त में सरकार से निवेदन करता हूं कि सेल्स टैक्स की सारी स्टेट्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यूनीफॉर्म रेट्स होनी चाहिए, नहीं तो आपको सेल्स टैक्स कम मिलेगा। यहां आपने बुलियन और ओरनामेन्ट्स पर सेल्स टैक्स लगाया तो पड़ोसी राज्यों में उससे कम नहीं होना चाहिये। आप कोशिश इस बात की कीजिए कि राजस्थान के आसपास के इलाकों में सेल्स टैक्स के यूनीफॉर्म रेट्स हों। जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये। गांवों में किसानों की सरचार्ज वापिस लेना चाहिये।

मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर खास तौर से अनएम्प्लायमेंट की प्रोब्लम ज्यादा है और.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खतम कर रहा हूं। लगभग साढ़े तीन लाख व्यक्ति आपके अनएम्प्लॉइड हैं तीसरी पंच-वर्षीय योजना में जैसे कि आपने अनुमान लगाया है तो विचार कीजिए। आपको यदि राजस्थान की बहबूदी लानी है तो केवल बड़े उद्योगों से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के हर गांव में और हर कस्बे को कुटीर उद्योगों का केन्द्र बना दिया जाय जैसे पंजाब ने बनाए हैं। आज तो पंजाब राजस्थान को खा रहा है। पंजाब की कौटेज इंडस्ट्रीज राजस्थान को हजम कर रही हैं। मैं लिसाड़ा की बात नहीं कहता या घग्घर के नाले के लिए नहीं कहता जहां आपने सूरतगढ़ फार्म बनाया है जो एक दिन घग्घर के पानी से ही बह जायेगा। मैं सतलज और व्यास के लिये नहीं कहता। कम से कम राजस्थान के हर गांव में कुटीर उद्योगों को पनपाइये। यदि राजस्थान की माली हालत सुधारनी है तो आपको इस ओर ध्यान देना होगा। राजस्थान के बेकारों की समस्या के हल की ओर आपको ध्यान देना होगा। और मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह संकटकाल है, अकाल का समय है पाला पड़ा रहा है कुछ आप भी खर्च में कमी कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैंडीचर कम किया जाय और थोड़ा सा अपने ऐशो आराम को कम कीजिए।

मैं यह कह रहा हूं कि हर साल नई गाड़ी मत खरीदिये। दो साल गाड़ी चलाई कि उसको बदल ली। नई खरीद ली। हर दूसरे साल नई गाड़ी चलाने की आदत मत डालिये। मत खरीदिये। आठ गाड़ियां खरीदी हैं। १३ और खरीदने वाले हैं। १३ और ८-२१। मंत्री हैं ८। उप-मंत्रियों को तो नई गाड़ी मिलती ही नहीं। इसलिए इस खर्चे पर रोक लगाइये और उपाध्यक्ष महोदय आज राजस्थान की जनता की जो माली हालत है, वह माली हालत न बिगड़े उस पर पब्लिक डैट न बढ़े अधिक ब्याज न देना पड़े, केन्द्र में ज्यादा साहूकारी मत दिखाइये कि २॥ करोड़ दे देंगे बल्कि केन्द्र से तो यह कहिये कि हमारा रुपया माफ कर दीजिये। राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त है और वह रुपया नहीं दे सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितना उनका असर है, जो कुछ है, उसको बाकी जगह काम में न लें। उसको सैण्ट्रल में ले जाकर काम में लें। यदि राजस्थान कैनाल एक नेशनल प्रोजैक्ट न बना तो राजस्थान का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। कर्जा बढ़ता जायेगा और अन्तत: यह स्थिति हो जायगी कि ब्याज की रकम भी चुका नहीं सकेंगे। आज राजस्थान बड़ी ही नाजुक परिस्थितियों में से गुजर रहा है। मैं माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आगामी वित्तीय वर्ष में नॉन टैक्स रेवेन्यू की आमदनी बढ़ायेंगे, सरचार्ज को हटायेंगे खर्चा ज्यादा न हो इस पर रोक लगायेंगे, और कम करने का प्रयत्न करेंगे, राजस्थान की विकास योजनाओं को बढ़ायेंगे, इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक लेखा जोखा पिछले सालों का ६२-६३ का एक्चुअल और ६३-६४ का रिवाइज्ड और ६४-६५ का आगे होने वाला एस्टीमेटेड यह हमारे वित्त मंत्री महोदय ने रखा है और वित्त मंत्रीजी ने अपने ही शब्दों में उसे बेजायके कहा है। उन्हें स्वयं को ही जायका नहीं आता है तो लेने वालों को कैसे आ सकता है।

७२ करोड़ का संभावित बजट सामने रखा है उसमें १० करोड़ रुपया तो सिर्फ ऋण सेवाओं का है, ८ करोड़ रुपया ब्याज का दिया जावेगा और दो करोड़ के लगभग अब कर्ज के देने की बात कही है। दस करोड़ रुपया जहां ब्याज का हुआ है और दूसरे चार्जेज और दूसरे खर्चे हैं सरकार को कोई अधिकार नहीं है, नीचे से नीचे डिपार्टमेंट वाले उसको रद्दोबदल कर सकते हैं ८ करोड़ का उसमें खर्चा है। यानी ८ करोड़ वह खर्चा है जिस पर सरकार न कभी नियन्त्रण करती है, न सेक्रेटेरियेट ही नियन्त्रण करता है, जिला अधिकारी तक ही अपनी चीजों को बदल देते हैं। अगर मकान किराया का है तो उसको फर्नीचर में बदल सकते हैं, फर्नीचर का है तो पोस्ट और तार के खर्चे में बदला जा सकता है। इस तरह से ८ करोड़ का लेखा रखा गया है उसके बारे में न सदन को पूछने का अधिकार है और न बताया ही गया है। ६२-६३ में कम खर्चा हुआ। हमसे पास नहीं करवाते। किस तरह का हिसाब है यह हमसे पास करवाते हैं। हमारे सामने क्या पेश करेंगे इसको ? आपको स्वयं को भी मालूम नहीं है और आपके सामने भी नहीं आता है। इस तरह से जो खर्चा यह करते हैं, मंहगाई, यात्रा व्यय चिकित्सा के लिये सहायता इनमें डिपार्टमेंट में ही रद्दोबदल कर सकते हैं। सरकार तक नहीं आता है यह हिसाब। सदन तक तो यह आया ही नहीं क्योंकि सरकार को ही नहीं मालूम है।

वित्त मंत्रीजी ने बड़े ढंग से कहा कि हिसाब का जंगल है उसकी छोटी सी पोथी बनाने वाले हैं। चाहे आप दो लाइन का ही कर लीजिये। इतना जमा और इतना खर्चा। सदन मान लेगा। सरकार आपकी है। लेकिन हिसाब तो पूरा बताना ही चाहिये। आपको स्वयं पूरा पता नहीं रहता है। इस तरह से १८ करोड़ रुपया इस प्रकार से खर्च हो जाता है ७२ करोड़ में से जिसको सरकार को पता नहीं होगा।

अब रहा जैसा कि कुछ भाइयों ने यह कहा कि सरकार बहुत बड़े टैक्स बढ़ा रही है। मैं निवेदन कर दूं टैक्स के बारे में। जब राजस्थान बना था तो ११॥ करोड़ रुपये टैक्स की आमदनी थी। ६१-६२ में पूरा हिसाब आया तो २१ करोड़ रुपये टैक्स की आमदनी बताई गई। ९॥ करोड़ रुपया टैक्सों के रूप में बढ़ा। कैसे बढ़ा ? ४॥ करोड़ रुपया जागीरों के कारण से बढ़ा। ९॥ करोड़ में से ४॥ करोड़ वह चला गया।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

६ करोड़ रहे उनमें से स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी उसकी वजह से। सड़कों पर गाडियों के टैक्स की ग्रामदनी से २-२।। करोड़ रुपयों की ग्रामदनी हुई। बासी रोटी पर खुदा का कर्जा नहीं। रोड्स पर करोड़ों रुपया खर्चा किया है तो यह टैक्स लगा दिया तो बुरा नहीं। वित्त मंत्री यह कहते हैं कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसकी ग्राय हमें चौथी ग्रौर पंचवर्षीय योजना में मिलेगी। लेकिन वह यह कहना भूल गये कि २० करोड़ रुपया हमने सड़कों पर खर्च किया उसमें से २-२।। करोड़ रुपया टैक्स के रूप में मिलता है। उन्होंने यह बताये बगैर यह भावना ज्यादा फैलाने की कोशिश की कि ज्यादा टैक्स बढ़ाये हैं। टैक्स किस पर बढ़े हैं? सरचार्ज जमीन पर बढ़ा है। राजस्थान के गांवों में १.७० लाख व्यक्ति रहते हैं। उनकी ग्रामदनी ३७ पैसे से ग्रधिक नहीं जो ग्रापने ग्रांकड़े दिये हैं उनके हिसाब से भी। ग्रापके ग्रांकड़े सही हैं या नहीं यह दूसरी बात है। ३७ पैसे की ग्रामदनी वाले पर टैक्स बढ़ाये तो जरूर दर्द होगा। इसलिये जमीन पर जो सरचार्ज लगाया है उसको हटा लीजिये। जो लोग यह कहते हैं कि पर कैपिटा जमीन पर ज्यादा टैक्स है। ऐसी बात नहीं। दूसरे प्रान्तों में ग्राबादी ज्यादा है, ज़मीन कम है। हमारे पास ग्रादमी कम हैं ग्रौर जमीन ज्यादा है। उपजाऊ जमीन कम है इसलिये यह है। सरचार्ज वाला मामला जिस प्रान्त में हर तीसरे साल ग्रकाल पड़ता हो वहां यह मौजूं नहीं है। ग्रकाल पर तीन चार करोड़ रुपया फैंक देना चाहते हैं ग्रौर उसके बावजूद ग्राप सरचार्ज लगा रहे हैं।

उसके बाद में एक बात निवेदन करूं। जैसे ही मैंने उनको सुना, भाषण पढ़ने की बात तो बाद में ग्राती है, मैंने सुना कि ग्रकाल पड़ा तो उनको भगवान याद ग्राये। भगवान को कोसा कि ग्रकाल पड़ा। मैंने पहले सोचा केबिनेट भगवान को ग्रोलहम्बा दे रही है। बजट तो सरकार का है। भाषण तो वित्त मंत्रीजी का है। बुरा नहीं लगा जब यह मालूम हुग्रा। वित्त मंत्रीजी भगवान की बुराई करते हैं। वित्त मंत्रीजी ने जिस वंश में जन्म लिया है उसी वंश में भगवान दशानन ने जन्म लिया है। व्यक्तिगत दोष हो सकता है उनका। उस वंश में दशानन भी थे। हमने उनके दिल की बात समझी। मैं उनके वंश की सारी पौथी जानता हूं। दशानन ग्रौर वे एक ही वंश के हैं। उन्होंने कहा प्राइवेट सैक्टर में बहुत ग्रच्छा काम हो रहा है। उनके मन की बात सामने ग्रा गई।

एक माननीय सदस्य: यह दशानन कौन?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: दशानन भगवान, लंकेश रावण।

श्री दलपतसिंह (ग्राबू): ये लंका से ग्राये हैं?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: दोनों का एक ही ऋषि से जन्म हुग्रा है। ग्रगर ग्राप समाजवाद में विश्वास करते हैं ग्रौर समाजवाद में विश्वास करने वाले मंत्री प्राइवेट सैक्टर की बात करें...........

एक माननीय सदस्य: वे बात कर रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: वे जानते हैं ग्रौर हम जानते हैं।

यह भगवान की जब बात आई थी तब मैंने कहा था...

श्री चन्दनलाल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : उस वंश की बात फिर दोहरा दीजिये ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसी वंश में आपका भी जन्म है यानि वित्त मंत्रीजी का । आपने भगवान को याद कर के बात कही है इसलिये मुझे पिछली बात याद करके कहना पड़ता है कि आप कौन हैं ?

प्राइवेट सैक्टर की बात मैं अब करना चाहता हूं । समाजवादी सरकार के वित्त मंत्री ने प्राइवेट सैक्टर की तारीफ की है और कहा गया है कि प्राइवेट सैक्टर में काफी मुनाफा हुआ है । समाजवाद में विश्वास करने वाला सरकार के वित्त मंत्री प्राइवेट सैक्टर की इस प्रकार की तारीफ करें यह शोभा नहीं देता । आप प्राइवेट सैक्टर में सफल हुये हैं यह ठीक बात है । लेकिन उनको जो आपने नाम मात्र की कीमतों पर जमीनें दी हैं, सस्ती बिजली देते हैं, प्राइवेट सैक्टर वालों को सस्ता पानी देते हैं और टैक्सों में भी रिलीफ देते हैं और मोनोपाली कायम कर देते हैं इससे मुनाफा बढ़ जाता है और उससे आपको खुशी होती है कि यह बड़ा अच्छा काम हो रहा है । पब्लिक सैक्टर में हम देखते हैं कि अनुभवहीन लोगों को आप भेज देते हैं जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले कोलायत से आने वाले माननीय साथी ने कहा । यह इसलिये कि आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है पब्लिक सैक्टर में । इसलिये आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं ।

पब्लिक सैक्टर में आपका सोडियम सल्फेट चल रहा है । उसके लिये कहा जाता है कि अब की साल आमदनी हो जायगी । वर्षों पहले उसके लिये जर्मनी से मशीनें खरीदी गई और यह तय किया गया कि उसी फर्म के इन्जीनियर यहां आकर उन मशीनों को फिट करेंगे । वे तो आये नहीं और यहां के किसी आदमी को वहां ले जाकर बैठा दिया । यहां पर टरबाइन चलाने वालों की और बौइलर चलाने वालों की कमी नहीं है । क्योंकि यहां पर पावर हाउसेज बहुत थे लेकिन उन लोगों में से किसी को नहीं लेकर अनुभवहीन को ले जाकर वहां बिठा दिया । उसने उसको फिट किया । फिट करने के बाद उसको तीन-तीन बार काटा गया । आज दिन तक दस महीने का समय हो गया तीनों शिफ्टों का स्टाफ कायम है । लेकिन काम नहीं चल रहा है । पब्लिक सैक्टर में आपका विश्वास नहीं । इसलिये आप ऐसे आदमियों के हाथ में देते हैं जो अनुभवहीन हैं । जब आप पब्लिक सैक्टर में इस प्रकार की चीजें नहीं चला सकते तो समाजवाद की बातें करना ठीक नहीं है । आपने रोड्स पर टैक्स बढ़ाया है, यह आपको अधिकार है । जब आपने रोड्स बनाकर दी हैं तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है और उसको हर व्यक्ति देने को तैयार भी है । लेकिन मैं जिस बस में आता हूं अजमेर से यहां, उस पर मुझे ७५ पैसा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आप जब रोज कार से आते हैं और साथ में सात-आठ आदमियों को बिठाकर लाते हैं आप क्या देते हैं ? यह जजिया कर हम लोगों पर तो है लेकिन उन कार रखने वालों पर क्यों नहीं ? इन रास्तों पर जहां आपकी व्यक्तिगत १२ हजार गाड़ियां दौड़ती हैं जिसके लिये सड़कें बनाने को बीस करोड़ रुपया दे दिया उन गाड़ियों पर बैठने वाले पर टैक्स नहीं लगाते हैं । जो रात-दिन गाड़ियां चलती हैं । और मुझ से आप लेते हैं क्योंकि मेरे पास घर की गाड़ी नहीं है और मालदार को आपने टैक्स छोड़ दिया है ।

दूसरी तरफ आपने खाली प्लॉट्स पर टैक्स लगाने का विचार किया है, क्योंकि आप

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यह सोचते हैं जिनके प्लॉट्स खाली पड़े हैं वे नफा कमाने के लिये ले रखे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं ऐसे गरीब बाबू लोगों के भी प्लॉट्स खाली पड़े हैं जिनके पास पैसा नहीं है मकान बनाने के लिये, आप उनसे भी पैसा टैक्स के रूप में वसूल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप २५ करोड़ रुपया जो लोग मकान किराये के रूप में वसूल करते हैं, उनसे आप दस परसेन्ट भी ले लें तो ढाई करोड़ रुपया सालाना आपको आमदनी हो सकती है। जिन लोगों ने मकान इसीलिये बनाये हैं कि उससे किराया प्राप्त किया जाय एसे मनीलैन्डर्स से जिन्होंने बिजनैस पौइन्ट ऑफ व्यू से मकान बनाये हैं उनसे तो आप टैक्स के रूप में कुछ वसूल नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने पैसा न मिलने के कारण मकान नहीं बनाये पैसे के अभाव से जिनके पास प्लॉट लिये हुए पड़े हैं उन पर आप पहले हाथ मारना चाहते हैं, उसने प्लॉट ले लिया, उस पर टैक्स लेना चाहते हैं। इस टैक्स के बारे में, मैं आपसे कहूंगा कि इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिये जिन्होंने केवल अपने रहने के मकान बनाने के लिये प्लॉट लिया है और जिसने कमाई करने के लिये लिया है उनसे लीजिये। आपके हिसाब से २५ करोड़ रुपया किराये के रूप में मकान मालिक कमाते हैं। उनसे आप दस परसेन्ट लेकर काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखता है जिसने यह हिसाब बना कर दिया है उसका इरादा होगा किसी का प्लॉट लेने का।

आपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की है। उससे १ करोड़ और दस लाख रुपये का खर्चा बढ़ गया। लेकिन जिस अनुपात से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से यह वृद्धि दी गई है वह ज्यादा नहीं है। महंगाई उन लोगों की बढ़ाई हुई है जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जो अपने पैसे का अनाज लेकर रख सकते हैं, उन्होंने अनाज को इकट्ठा करके यह बाजार में महंगाई पैदा कर दी उससे सरकार को सवा करोड़ रुपया अपने कर्मचारियों को देना पड़ा। आप महंगाई के कुछ भी कारण बताते हों लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आपकी ओर से जो आंकड़े दिये जाते हैं वे ठीक नहीं होते हैं। मेरे पास आपके स्टेटिसटिक्स विभाग की किताब है जिनमें आंकड़े दिये गये। तीन सालों के हर साल में भिन्न भिन्न आंकड़े हैं। स्टेट की इन्कम का सवाल है उसमें भी तीनों किताबों में तीन भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े दिये गये हैं। ५१-५२ के आंकड़ों को देखें जिसमें ३६० करोड़ का अंक है। दूसरी साल की किताब में इसी वर्ष में चारसौ करोड़ का था और जब आप ५५-५६ का देखें तो उस वर्ष में वह ४५० हो जाता है। पिछले सालों की किताबों में हर किताब में फर्क रखा है। मुझे खास इस बात की भी शिकायत है कि आपका हिसाब-किताब भी साफ नहीं है। उसी किताब में गन्ने का उत्पादन एक बार तो १३ हजार टन बताते हैं, उसी किताब में आगे जाकर सात सात हजार टन बता दिया।

हमारे राज्यपाल महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, बीकानेर में अध्यापक रह चुके हैं उनको भी गलत आंकड़े दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ४९ में जब राजस्थान बना ही था शिक्षा पर केवल ९२ लाख ६० हजार रुपया खर्च होता था जिसकी ताईद मुख्य मंत्री महोदय ने भी की थी अपने भाषण के दौरान में। ४९ में कितना शिक्षा पर व्यय होता था उसके आंकड़े मेरे पास हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि सन् ४९ में १ करोड़ ८४ लाख का

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

खर्च हुआ था जब कि उसमें अजमेर राज्य शामिल नहीं था। राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलाया गया कि ४६ में ६२ लाख ६० हजार ही खर्च करते थे जब कि ४६ में खर्च करते थे एक करोड़ और ८४ लाख ४५,६२४ रुपया। लेकिन इसकी जगह ६२ लाख और ६० हजार की गलत सूचना राज्यपाल महोदय को दी गई। आपको उन लोगों को सुधारना चाहिये जो इस प्रकार गलत सूचनायें राज्यपाल तक को देते हैं। उसमें आप सुधार नहीं करेंगे।

इसके अलावा मुझे आश्चर्य होता है कौन साहित्यकार राज्यपाल का भाषण बनाने वाला था जिन्होंने सोडियम सल्फेट के बारे में कहा कि १०० टन उत्पादन वार्षिकी करेंगे जब कि आपके यानि वित्त मंत्री के भाषण में यह है कि १०० टन उत्पादन प्रति दिन होगा। इस तरह की गलत बातें भी जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे स्टेट के हैड हैं उनको भी बताई जाती हैं।

अब मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करूंगा। भ्रष्टाचार के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने भी माना है कि टैक्सेज की चोरियां होती हैं, इसमें भ्रष्टाचार होता है। उसको हद तक रोकने की कोशिश की जायेगी पूरी, नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय और दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय। अकाल पड़ा, लोगों ने अनाज इकट्ठा कर लिया। परन्तु राज्य सरकार को मैं इसके लिये बधाई देता हूं कि अकाल की सहायता के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। इस के साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि दूसरे लोग जिन इलाकों में अकाल नहीं है उन के बजाय अकाल क्षेत्र में काम ज्यादा किया जाय जैसे जैसलमेर राज्य जब से बसा है इतनी अकाल में सहायता कभी नहीं हुई जितनी सहायता हमारी सरकार कर रही है।

ऐसे हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ। हजारों वर्षों में वहां हजारों अकाल पड़े हैं। तो वहां जो अकाल सहायता सरकार ने दी है, उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं।

पर साथ में निवेदन यह करना चाहता हूं कि रिलीफ एक्ट का पालन वहां पूरा करवाया जावे। एक्ट में साफ लिखा है और सरकार की मंशा भी इससे साफ है कि छः दिन काम करने के बाद एक दिन बैठने की हाजरी का भी दिया जावेगा ताकि वे घर पर उस दिन बैठकर आराम से अपने कपड़े वगैरह धो सकें। अब यह रिलीफ सरकारी कर्मचारी उनको नहीं देते। वह यह समझते हैं कि काम अगर उनसे ज्यादा करवा लिया तो हमारी तारीफ होगी और कम पैसे में अधिक काम करा लिया यह भी उनकी तारीफ में शामिल होगा। पर यह सरकार की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। वहां भी गरीबों का शोषण हो रहा है इस अकाल की हालत में भी। तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों को ठीक करना चाहिये।

अब अकाल की स्थिति का फायदा उठा कर कुछ व्यापारी लोगों ने अन्न इकट्ठा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि महंगाई बढ़ी। भारत सरकार ने समझा अगर बैंकों से इनको पैसा दिलाना बन्द कर दिया तो शायद लोग होर्ड नहीं कर सकेंगे। पर वास्तव में स्थिति आज यह नहीं है। आज से बीस साल पहले तो यह उपाय कारगर हो सकता था। पर आज भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केट के द्वारा उन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वे सबल हो गये हैं। इतनी ताकत उनमें आ गई है कि वे स्वयं अपने

Page No. 57

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

ब्लैक मार्केट द्वारा और भ्रष्टाचार द्वारा इकट्ठे किये गये पैसे से होर्ड कर सकते हैं। तो इसलिये आज तो उनके खिलाफ कोई और भी ' सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वह सख्त कदम आप नहीं उठावेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा बुरे दिन हम लोगों को और जनता को देखने पड़ेंगे। वे बुरे दिन हमें नहीं देखने पड़ें, इसके लिये आपको यत्न करना चाहिये। आज का हिसाब-किताब तो नहीं जमेगा। आपके भ्रष्टाचारी अफसर भी आपको सही रास्ता नहीं बतावेंगे। आपको यह बताया जावेगा कि व्यापारियों को समझा दो, अपील निकाल दो, कन्ट्रोल निकाल दो। पर आज इससे काम नहीं चलने वाला है। यह तो आपने आज तक बहुत करके देख लिया। उन सब चीजों का वक्त निकल गया। आपको तो आज सख्त कदम उठाना होगा। मैं एक रास्ता इसका आपको बताता हूं।

पुराने जमाने में भी इसी प्रकार का कष्ट जनता पर पड़ा था उस वक्त भी एक पणिक नाम की जाति थी जो पण नामक स्वर्ण मुद्रा ले जाकर किसान को दे देती थी और उसके बदले में अन्न ले लेती थी, मोची को ले जाकर दे देती थी और बदले में जूते ले जाती थी.तो इसी तरह पण के बदले आदान प्रदान करके सारी चीजें अपने कन्ट्रोल में करली, होल्ड कर लिया उनका और जमाने में अकाल डाल दिया। यह पुराणों का किस्सा था। उस समय की इन्द्र की आज्ञा पर आप चलिये। तो अब वहां क्या होता है? लोग हाहाकार करने लगे। सब मिलकर इन्द्र के पास गये। वे लोग कुम्भ के मेले पर इकट्ठे हुए थे। आज कुम्भ का मेला भी उसी की परम्परा है। लोगों ने इन्द्र से कहा अकाल पड़ा है। जनता दुखी है। इन्द्र ने इस पर कन्ट्रोल बनाया, जैसा आप करते हैं। उन्होंने भी वैसा ही किया। तीन-तीन अंजुलि अनाज एक-एक को दिया। जिसकी नकल आज भी करते हैं, मरने पर तीन तीन अंजुलि आज भी देते हैं। आज उसके पीछे क्या किस्सा था यह भूल गये हैं। फिर भी अकाल नहीं मिटा। पणिक सोना दे जाते और चीजें ले जाते लोग अधिकाधिक भूखों मरने लगे। तब इन्द्र को बाध्य होकर आज्ञा देनी पड़ी कि जो पणिक ब्लैक मार्केट करता हो, मतलब अन्न की चोरी करता हो, उसकी चल अचल सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रहेगा। और उनको आश्रय देने वालों को मृत्यु दण्ड दिया जावेगा। अक्ल दुरुस्त हो गई उन बेईमानों की, जिन्होंने बेईमानी की।

आज आप इस तरह का एक्ट लागू करें। जिन व्यापारियों ने होल्ड किया है, ब्लैक किया है, भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों ने किया है, लोगों के खून को जिसने चूसा है उसकी चल अचल सम्पत्ति जब्त कर लें। उनके नागरिक अधिकार छीन लें। यह आप नहीं करेंगे तब तक इनकी आज अक्ल दुरुस्त नहीं होने वाली है।

(विराम)

आज बातों से, समझाने-बुझाने से, समझौतों से, कन्ट्रोलों से काम नहीं चलने वाला है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं आप इन ब्लैक मोर्केटियरों को, इन मुनाफाखोरों को काबू में लाने के लिये आज के आपके इन प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे मत रहिये। इनके भरोसे काम नहीं चलेगा। आपको एक चीज पर ध्यान करना चाहिये। मैं याद दिलाता हूं आपको। आप आज कल की नहीं १८-२० साल पहले की बात याद रख लीजिये जब कभी भी आप इनसे डील करें। आपका उस जमाने में एक सुखाड़िया अवार्ड बना

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

था। १८-२० और २४ पाने वाले श्रमिकों को ५४) आपने दिया था। वह अपने मिसाल का एक ही ऑर्डिनेन्स था जो उस समय हिन्दुस्तान में बना था जिससे देश के सरमायेदार थर्रा गये। उस समय आप शासन में आये ही थे। ऐसे लोगों के जी हुजूरों के घेरे में आप नहीं घिरे थे। इन 'सर' और 'हुजूर' करने वाले और खुशामदी चाटुकारों से आपका काम नहीं पड़ा था। आप एक शानदार वर्कर थे उससे ऊंचे उठे थे और उस समय के शानदार वर्कर गिने जाते थे। मजदूरों के लाभ के लिये आपने इन जी हुजूरों की पर्वाह नहीं की। उस वक्त आप ने अवार्ड बनाया था जब फौर्मर राजस्थान में आप श्रम मंत्री थे।

उसी तरह का ऑर्डिनेन्स आज आप निकालिये। जो आज की इन अकाल की परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करेगा, जो इस तरह से महंगाई पैदा करके गरीबों का खून चूसने की चेष्टा करेगा उसकी चल-अचल सम्पत्ति जब्त कर लूंगा। जिस दिन आपने ऐसा दृढ निश्चय करके ऑर्डिनेन्स निकाल दिया, ये सब कहीं टिकेंगे ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक अर्ज कर देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकारी व्यवस्था के बारे में, दो-चार मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

मैं शक्कर के कन्ट्रोल की व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। उसके वितरण की प्रणाली के बारे में बताना चाहता हूं। राज की व्यवस्था में शिकायत करना सही नहीं है। राज्य ने तो ठीक ही व्यवस्था की सोची। शक्कर अगर कम है तो कम लेंगे; नहीं होगी, नहीं खावेंगे। पर आप जो वितरण के लिये जनता को देते हैं, भीलवाड़ा जिले की लिस्ट मेरे पास है, इसमें आपने कहा है कि शहरों में इतनी दो, गांवों में इतनी दो। आपने तो ठीक कहा। पर हमारे यहां भीलवाड़े में क्या हुआ? मैं अर्ज करता हूं। आपने शक्कर दी। मानता हूं सरकार ने दी। पर वहां के अधिकारियों ने आपकी आज्ञा की अवहेलना की। आपने गांवों को १५०० क्विन्टल दी तो उन्होंने ६०० भी नहीं बांटी। पता नहीं शहर में क्यों अधिक दी? वहां एक एक परमिट पर चार-चार सौ किलो शक्कर दी है। एस० डी० एम० के मना करने पर भी एक बड़े आदमी के भाई को चिट्ठियों से दो दो चार चार बोरी शक्कर दे दी जाती है। बड़े आदमी के कहने पर। आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): किसके नाम दी? नाम बताएं आप।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सरकार जांच करायेगी, तो मैं सब बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास: सदन में आपने एक बड़े आदमी पर इल्जाम लगाया है। सदन में नाम भी बताइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: जांच में बता दूंगा। जांच करना सरकार का काम है।

श्री मुरलीधर व्यास: आप नाम तो बताइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप कहेंगे तो बता दूंगा नाम भी।

Page No. 59

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है नाम बताने की।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सरकार स्वयं जांच कराले। मैं नाम बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी मन्त्री का नाम है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसके बाद अर्ज करता हूं जमीन के बारे में। भीलवाड़े की बात बताता हूं। वहां दो सालों में इस बारे में क्या–क्या हुआ है? जिनके पास खेती की जमीन नहीं, जिन्सवार नहीं, खातेदारी हक नहीं, वे जमीन एक अपने नाम से खातेदारी करा लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं दूसरों को शहर में। वह आदमी तहसीलदार के पास जाता है कहता है वह जमीन फलां आदमी से ली है आप जिन्सवारी खुलवा दो, पटवारी को कह दो। आखिर में वह खुलवा देते हैं। ऐसे १०० आदमियों से वह कम नहीं हैं और वह अपने नाम पर जमीन करा लेते हैं मकान उस पर बना लेते हैं। हजारों रुपयों की वह जमीन एक २ आदमी मुफ्त में ले लेते तो लाखों रुपयों का अनुचित लाभ इस तरह का मामला इन दिनों में हुआ है। यदि चाहें तो लिस्ट आपको दे सकूंगा।

एक आदमी ७१० रुपये में १०१ बीघा जमीन भीलवाड़ा में किसी जागीरदार से ले लेता है जो लेबर कोलोनी के पास थी। सरकारी अधिकारियों ने मना किया कि आपके नाम पर जमीन दर्ज नहीं करेंगे। कलक्टर के पास गया, उसने भी ना देदी। कमिश्नरी में गया, कमिश्नरी ने इन्कार कर दिया। रेवेन्यू बोर्ड ने भी इन्कार कर दिया। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला मौजूद है। इसके बाद अब ६३ में जाता है तहसीलदार के पास, पता नहीं किसके जरिये से जाता है; कहता है, मेरे कब्जे में जमीन है, मेरे नाम कर दीजिये। ४८ बीघा कर दो। अगस्त में यह की जाती है और अक्टूबर में, दो महीने बाद ही इसमें से बीस बीघा जमीन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को १०००) बीघा के हिसाब से देने की बात की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शीघ्र समाप्त करें।

(व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं समाप्त करता हूं। आपकी बात तो कहना भूल गया।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दूसरों को समय देना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसमें किसी सरकारी आदमी के रिश्तेदार का हाथ था। उसको लाभ पहुंचाना था। उसे लाभ पहुंचाने के लिये सरकारी अधिकारियों से सांठ गांठ की गई। भीलवाड़ा शहर में वैसी जमीन योंही पांच दस रुपया गज में नहीं मिलती है। आज उस सौदे के नाम पर वह अपनी ४८ बीघा जमीन को रिहायशी जमीन में बदलने के लिये रेवेन्यू ऑथोरिटी में ले जाता है। आधा मकान बनाने के हेतु बेचने के लिये दे देते हैं और आधा सरकार को कीमतन। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आपको अधिकारियों का मुकाबला करना पड़ेगा। इनमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि उनकी चल अचल सम्पति की जब्ती का डर आप उनको नहीं दिखावेंगे काम नहीं चलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरसिंह १० मिनट बोलेंगे और फिर श्री हरिराम चौहान १० मिनट बोलेंगे। उसके बाद सरकारी जवाब होगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : पहले कौन बोलेगा ?

श्री अध्यक्ष : : श्री अमरसिंह।

श्री अमरसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदनके सम्मुख सन् १९६४-६५ का बजट पेश हुआ है। असल में देखा जाये तो बजट का पेश होना हम लोगों के लिए एक त्यौहार के समान है। अब देखना यह है कि इस त्यौहार का असर हम लोगों पर जो गांवों में रहते हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है ? गांव जहां राजस्थान की ८० प्रतिशत जनसंख्या है उस पर बजट का क्या असर पड़ा है उसको भी हमें देखना है। इस मौके पर जब बजट पेश हुआ तो किसानों की निगाहें इस तरफ भी थीं कि उन लोगों को इससे क्या राहत मिलने वाली है क्योंकि राज्य सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत कुछ अंशों में यह मान लिया कि यह अकाल का समय है। शीत लहर भी आई हुई थी। तो इस समय यह स्वाभाविक था कि वह किसान उम्मीद करते कि इस समय उनको आप कोई न कोई राहत पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उनकी यह सब आशा बेकार रही। इस समय मुझे एक कन्जूस पिता की बात याद आती है। जब बच्चा अपनी मां से पैसा लेकर पिता के पास पहुंचता है और पिता को फरियाद करता है कि उनकी तरफ से भी कुछ मिले। ऐसे मौके पर पिता वह कंजूस पिता उसके उस सिक्के को जो उसकी मां ने दिया था उसको भी लेने के लिए लालायित हो जाता है। परन्तु उस कंजूस पिता को मालूम है कि अगर यह सिक्का भी इससे ले लिया गया तो यह रोयेगा। इसलिए कि वह बच्चा चिल्ला नहीं पाये वह कंजूस पिता एक हाथ तो उसकी जेब पर धीरे से रखता है और दूसरा हाथ जो है उससे वह हाबू की तरफ इंगित करता है। हाबू नाम आपने सुना होगा, यह बच्चों के दिमाग पर काफी भय जमाने के लिए काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार कहीं किसान चिल्लाने लग जायें इसलिये आपने हाबू का संकेत अपने भाषण मे किया है। जो पहला हाबू जिसकी तरफ आपने इशारा किया वह प्रेसीडेन्ट कैनेडी की हत्या का था। यह हाबू आपने इसलिए दिखाया कि जिससे वह टेरोराइज्ड हो जायें दिमाग में, और वह कहने न लगजायें कि हमारे लिए क्या किया और हमें क्या राहत दी।

इसके बाद दूसरा हाबू जिसकी तरफ आपने इशारा किया वह चीन और पाकिस्तान की तरफ किया है और कहा है कि सरहद पर यह हो रहा है। यह इशारा इसलिए किया कि ताकि यह समझ जायें कि हम कैसे उनको ऐसे समय पर राहत दे सकते हैं। आपने तीसरी बात विकास के लिए कह दी कि हमने रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ा दी है। याने आपको किसी प्रकार की छूट दी जाये तो उसका सवाल ही नहीं है। आपकी यह विकास की रफ्तार किस तरह से तेजी से बढ़ रही है यह तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन समय थोड़ा होने के कारण उसकी तरफ थोड़ा इशारा मात्र करूंगा। चौथी बात आपने कही कि जागीरदारों को बड़ा बड़ा मुआवजा देना है और उसके लिए पैसे की हमें जरूरत है तो हम क्या करें? लेकिन मैं बताऊं आपने २.८० करोड़ जागीरदारों के मुआवजा के लिए प्रावधान रखा है जब कि बजट में आपने ४ करोड़ ६० लाख रुपये का दूसरा प्रावधान रखा है तो इससे तो आपने एक इन्वेस्टमेन्ट किया है। इसमें लोगों को डराने को और हाबू दिखाने की क्या जरूरत

(श्री अमरसिंह)

है ? इसके बाद आप और आगे बढ़े और लोगों को लाचार करने के लिये इससे अधिक क्या कर सकते हैं कि आपने कहा कि प्रकृति बड़ी चंचल है और अब की बार वह धोका दे गई है। आपमें सामर्थ्य नहीं है कि जो नेचुरल कैलेमिटी आई उससे लोगों को बचाते ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मानसून को कैसे बुलाते ?

श्री अमरसिंह : मानसून नहीं बुलाते, लेकिन ट्यूब वैल बनाते, लिफ्ट इरिगेशन के उपाय करते। यह तो करना चाहिये था।

फिर आपने देखा कि किसान भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा करने वाले हैं इसलिये इनको संतोष देने के लिये आपने कह दिया है कि यह भगवान की कुदरत है कि उसने इस बार ऐसा कर दिया है। आज समाजवादी सरकार बनाने वाले जो भगवान में भरोसा नहीं करते इस प्रकार की चीज कहें यह वाजिब नहीं था। और वह बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से उन भगवान को क्रिटिसाइज किया है। इससे उनके धार्मिक विचारों के ऊपर आघात पहुंचता है। उन्होंने बताया है कि यह भगवान की गलती है। तो लोगों के दिमाग में यह चीज लाना है कि हम भगवान से भी बढ़कर हैं। प्रजातंत्र में इस प्रकार से भगवान को क्रिटिसाइज करना ......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उन्होंने यज्ञ नहीं किया मिनिस्टर तो हैं।

श्री अमरसिंह : आपने कहा है दयालु भगवान के लिये यह चीज शोभा नहीं देती। यह भगवान को क्रिटिसाइज करना नहीं है तो क्या है ? लेकिन इन सब चीजों से आप उनके दिमागों को टैनेराइज कर रहे हैं कि वह चिल्लाने न पायें, कहीं वह लैण्ड रेवेन्यू की छूट के लिये चिल्लाने न पायें–इसीलिये आपने अपने भाषण में हाबू को पेश किया है। आपने दूसरे टैक्सेस फिर भी लगा ही दिये। उनके बारे में मैं बताऊं कि आपने ओरनामैन्ट्स के ऊपर और वह भी चांदी के ओरनामैन्ट्स पर लगाया है। पहले तो १४ कैरट वालों पर फिर आगे बढ़ा दिया और इसका असर गरीब किसानों पर पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दो तीन मिनट ही हुए हैं। मुझे राज्यपाल महोदय के भाषण पर भी टाइम नहीं दिया था।

इस प्रकार के जो टैक्सेज लगाये हैं उनका असर किसानों की जेबों पर पड़ेगा क्योंकि चांदी के गहने वही पहिनते हैं। खैर आपकी मर्जी है।

इसके बाद आप यह न समझें कि मेरा मतलब यह है कि टैक्स नहीं लगाये जायें। टैक्स तो विकास के लिए और प्रशासन के चलाने के लिये थोड़े बहुत लगाने जरूरी हैं। लेकिन वह इस प्रकार से लगाये जायें कि जिसे लोग सुविधा से दे सकें और उनकी सामर्थ्य के अनुकूल हों। जैसे आपको गायों का दूध बढ़ाना है तो आप उनको खाने के लिए खूब दीजिये उसके बाद देखिये कि वह कितना दूध देती हैं। इसी तरह से आप लोगों की आमदनी बढ़ाइये और फिर उनसे टैक्स लीजिये। उनके पास आज जो खेती के साधन हैं वह बिलकुल ठीक नहीं हैं। जैसे अभी अकाल पड़ा, तो कहीं पातालतोड़ कुए

Page No. 62

(श्री अमरसिंह)

कहीं लिफ्ट इर्रीगेशन आदि का प्रबंध करना चाहिये, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप के पास इसके आंकड़े हैं और आपसे यह पूछा जाय कि कितने नुक़्ते के केसेज़ आपने पकड़े तो आप कह देंगे कि हमको सूचना नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस प्रकार का प्रबंध करें कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर अच्छा बीज दें, अच्छे इम्प्लीमेन्ट्स रखें और वह लोगों को दिखायें। तो आपने ऐसे साधन भी नहीं जुटाये। आज हालत यह है कि किसानों को जो उपज होती है इसे ठीक दामों पर बिकने का कोई प्रबंध सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि उनको अच्छा पैसा टाइम पर मिले और अच्छा बीज मिले ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। यह घंटी जो बार बार बजती है उससे लिंक टूट जाता है। मैं अपनी पौलिसी की बात उपाध्यक्ष महोदय, अवश्य कहना चाहूंगा।

इसके बाद लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिये भी कहूंगा कि किस प्रकार से किसानों को उससे नुकसान हुआ है। उल्टे यह तो भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण हो गया। सरपंच जगह—जगह छोटे—छोटे तानाशाह बन चुके हैं। मैंने प्रश्नों के द्वारा पंचों के बारे में कहा था कि किस प्रकार डबल रोकड़ बही रखकर गड़बड़ियां की गई हैं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो आपके विभाग की तरफ से ऑडिट वगैरह किया गया था और ४०९ के और एम्बेजलमेंट के केसेज़ उनके खिलाफ थे उनको थानों में से और सेक्रेटेरियट से गायब करवा दिया और आप उनके मामलों को दबाना चाहते हो। और फिर आप कहते हैं कि किसानों की तरक्की के लिये यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री अमरसिंह : एक मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : No order please, श्री हरिराम चौहान।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही स्टिपुलेट कर दिया है कि १० मिनट में खत्म कर दें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय यह जो बजट आज हमारे सामने पेश हुआ है और कई रोज से इस पर बहस हो रही है। यह चार भाषाओं में लिखा हुआ है उर्दू, हिन्दी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में। इसके ऊपर बहुत ही दिमाग़ी तौर पर मेहनत करके हमारे वित्त मन्त्री महोदय हैं, उन्होंने पेश किया है।

वह टाइम था इनके लिए, कि ९ तारीख का दिन था जब कि वह दो करोड़ राजस्थान की जनता की वाहवाही लूट सकते थे, दो करोड़ की जनता को राहत दे सकते थे किसान और मज़दूरों को कुछ राहत दे सकते थे, कुछ उच्च तबके के ऊपर जो कि शोषण करने में विश्वास करता है चोट कर सकते थे उसको दबाने के लिए कुछ कर सकते थे। और आज जिस तरह की हालत है और जिन हालात के अन्दर यह बजट तैयार हुआ है एक तो बड़ी ज़बरदस्त मंहगाई की हालत में जो कि सारे हिन्दुस्तान में फैली हुई है,

(श्री हरिराम चौहान)

दूसरी राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति बड़ी भयानक रूप धारण कर चुकी है और संकट कालीन परिस्थिति जिसका कि यहां भी बारबार जिक्र करते हैं, इन तीनों चीजों के अन्दर महंगाई, संकटकालीन परिस्थितियां और अकाल इन चीजों का असर सारे राजस्थान की जनता पर पड़ रहा है सारे राजस्थान के किसानों पर पड़ रहा है, मजदूरों पर पड़ रहा है, छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है छोटे कर्मचारियों पर पड़ रहा है, और बेकार लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन हम यह देखना चाहते थे इस बजट के अन्दर कि क्या इसका असर हमारे राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल पर पड़ा? क्या इसका असर हमारे सेक्रेटेरियेट के जो मेम्बर हैं उनके ऊपर पड़ा? जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों पर पड़ा? हमारे जितने भी राज्य करने का दावा करते हैं उनके लिए मैं यह देखता हूं किस बजट के अन्दर जहां शिकायत की गई है भगवान से, जहां यह गिला किया गया है भगवान से, कि आपने हमारी फसलों को खराब किया है, तो मैं समझता था कि इस तरह का वित्त मन्त्री जो भगवान से इस तरह से रिक्वैस्ट कर सकता है जो भगवान से इस तरह से नाराजी जाहिर कर सकता है तो मैं देखना चाहता था कि उस वित्त मन्त्री का दिल किसानों और मजदूरों के लिए पत्थर का दिल नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि किसानों और मज़दूरों के लिए आज भी वित्त मन्त्री का दिल इन तमाम हालतों को देखते हुए भी पत्थर का है। दूसरी तरफ़ हम यह देखते हैं कि आज राजस्थान के सरमायेदारों के लिए वही दिल दयावान है। यह दो तरह की नीतियां हैं यह दो मुंही नीति इस बजट के अन्दर, हमारी सरकार के मुख्य मन्त्री हमारी सरकार के वित्त मन्त्री के अन्दर मौजूद हैं।

मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी बातों को पूरी तरह से रख सकूं और जल्दी जल्दी कहने में कुछ गड़बड़ भी होती है। मुझे यह देखने को १२ तारीख़ को मिला जब कि हमने यह कहा हमारी पार्टी ने यह कहा कि आप समाजवाद के अन्दर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। आपकी नियत समाजवाद लाने की नहीं है। लेकिन आप नारा देते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन जब १२ तारीख़ से उसका सरकार की तरफ़ से जवाब नहीं मिला। लेकिन पद्मविभूषण की उपाधि जिनके लगी हुई है वह बिरला जी तशरीफ़ लाये तो उन्होंने उसका पूरा जवाब दे दिया और कहा देखो राजस्थान के लोगों, राजस्थान के उद्योगपतियों, राजस्थान के व्यापारियों आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किस वक्त कहा गया? उस वक्त कहा गया जब कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी वहां मौजूद थे। उस वक्त कहा जब उद्योग मन्त्री मौजूद थे। उस वक्त कहा-जहां श्रम मन्त्री बैठे हुए थे। और तमाम राजस्थान का मंत्रि-मंडल भी उनकी मीटिंग में शरीक होता है और उस मीटिंग में शरीक होकर उनके सामने वह यह बात कहते हैं कि आपको इनके समाजवाद से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके नारे से घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनकी बेबसी है इन बेचारों को मतदाताओं के पास जाना पड़ता है और मतदाताओं के पास में वायदे करने पड़ते हैं और उन वायदों को न निभाया जाय तो छोड़ना पड़ता है। इस तरह के शब्द हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के सामने कहे जाय और फिर मुझे इनकी हालतों

(श्री हरिराम चौहान)

को देखकर बड़ा तरस और रहम आता है (कांग्रेस के पक्ष की ओर से 'धन्यवाद') बेचारे बेबसी से वहां पर बैठे हुए हैं इनको और अब क्या कहा जाय। उन्होंने इतना ही नहीं कहा यह जो आपने चैम्बर ऑफ़ कोमर्स के भवन के लिए एक रुपये के अन्दर जमीन दी, उस कारण बहुत से माननीय सदस्यों को बड़ी कुरकुराहट है, इधर बैठने वालों को भी है और उधर बैठने वालों को भी है कि यह लाखों रुपयों की जमीन एक रुपये साल पर दी जाती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। उद्योगपतियों के लिए, बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वे चन्दा देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): आपको भी देते हैं।

श्री हरिराम चौहान : इस बात का महत्व नहीं है लेकिन महत्व इस बात का है कि उन्होंने उस भवन के निर्माण के अन्दर जो नीति निश्चित की है उन्होंने खुले रूप से सुखाड़िया साहब के सामने ऐलान किया है कि यह जो आपका भवन निर्माण हो रहा है यह तमाम व्यापारियों के लिये आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु होगा। वह आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु होगा तो वह आन्दोलन किस बात के लिए होगा। वह आन्दोलन किसानों को राहत दिलाने के लिए नहीं हो सकता, वह आन्दोलन मजदूरों को राहत दिलाने का आन्दोलन नहीं हो सकता। वह आन्दोलन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढाने के लिए नहीं हो सकता। वह आन्दोलन किसी और चीज के लिये नहीं हो सकता। वह आन्दोलन जो निश्चित रूप में सरकार की घोषित नीति है, जो नीति सरकार ने आवाडी में तस्लीम की है, जो सरकार की पार्टी ने भुवनेश्वर के अन्दर तस्लीम किया है, उन तमाम नीतियों के खिलाफ दिल्ली में जब नन्दाजी के सामने मीटिंग हुई व्यापारियों की तो उसमें बिडलाजी ने कहा कि अब टाइम आ चुका है, आप होशियार हो जाइये। इसके पहले अंग्रेजों के टाइम में उद्योगपतियों की नीति सरकार के साथ चलने की थी। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। सरकार से वे सहूलियत हासिल करते थे इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन आज उनकी नीतियों के अन्दर परिवर्तन हुआ है। उस वक्त में वे गिडगिडाते थे। उस वक्त में वे खुशामद करते थे, उस वक्त में वे उनके तलुवे सहला सहला कर सरकार से रियायतें हासिल करते थे। अब बिल्कुल बदल गई हैं। अब ये खुद गिडगिडाते हैं। वे सिर पर डंडा लेकर चढे हुए हैं और कहते हैं कि खबरदार, अगर आपने हमारी इन नीतियों के खिलाफ, हमारे शोषण के खिलाफ, हम जो खुली लूट सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आपने कुछ किया तो पैसा लेने के लिए चुनाव में हमारे पास हो आना पडेगा। दिल्ली के अन्दर तो बिडलाजी के मुह पर घूंघट या कुछ पर्दा था वह उन्होंने सुखाडियाजी के सामने उतार दिया। क्यों? यहां तो डिग्रीज का फर्क आ जाता है। सैन्ट्रल के मिनिस्टर के सामने वह अपने आपको कमजोर समझते हैं और राजस्थान के अन्दर सुखाड़ियाजी के सामने अपने आपको कुछ ऊपर समझते हैं। इसलिए खुले रूप में कहा कि उनका कांग्रेस से पचास सालों का सम्बन्ध है। इसलिए व्यापारियों को घबराना नहीं चाहिये।

(श्री हरिराम चौहान)

उनको हकीकत देखना चाहिये कि कांग्रेस से हमारा क्या सम्बन्ध है। तो यह मंहगाई की बातें मुझे दिखता है कि दूर नहीं हो सकती।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि बिड़लाजी इस तरह की बात नहीं चाहते। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को मानते हैं कि बजट में उनकी नीतियों पर नहीं चलते हैं तो एक रुपये साल में दी हुई जमीन को जब तक बिड़लाजी अपने शब्दों को वापिस नहीं करते हैं, तब तक सुखाड़िया साहब को यह चाहिए कि कहें कि वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक बिड़लाजी इन शब्दों को वापिस नहीं लें कि आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु बनेगा, इसको कैन्सिल करते हैं।

(१२.०० मध्यान्ह)

यदि यह हिम्मत है तो वे कह सकते हैं, वर्ना इतना तो कहें कि जो कुछ बिड़लाजी ने भाषण दिया है वह गलत दिया है जिससे आम लोगों में जो निराशा फैल रही है वह न फैले। सारे राजस्थान की जनता सोच रही है कि कानून बनेगा मंहगाई रोकने के लिये और अनाज का व्यापार राजकीय क्षेत्र में होगा, पब्लिक सैक्टर में औद्योगीकरण होगा, बसों का राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन और जगह तो हो सकता है राष्ट्रीयकरण परन्तु उदयपुर में, मुख्य मंत्रीजी के जिले में राष्ट्रीयकरण बसों का नहीं होगा। और यदि होगा तो टेढे मेढे रास्ते से। इनको चुनावों के लिये पैसा चाहिये और वह पैसा उदयपुर के बस मालिकों से और मिल मालिकों से ही मिल सकता है। फिर आप बात करते हैं कि प्रजातांत्रिक समाज वाद लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सुखाड़िया साहब जवाब देंगे कि समाजवाद लाने की कौनसी ताकत है? कौनसे लोग हैं जो समाजवाद लाना चाहते हैं? कौनसे आपके सिपहसालार हैं? बिडलाजी आपके समाजवाद को लाने के सिपहसालार हैं या मंत्री मंडल में जो राजा और जागीरदार घुसेड़ रखे हैं क्या वे सिपहसालार हैं जो समाजवाद लायेंगे? समाजवाद कौन लायेगा? किसको समाजवाद की जरूरत है? समाजवाद की जरूरत है भूखों को, मजदूरों और किसानों को। किसान और मजदूर समाजवाद लायेंगे। समाजवाद की बात करने वाले लोगों! आप गौर करें। आपका बजट क्या कह रहा है? आपने टैक्स लगाकर कुल्हाड़ियों की तरह हमला किया है। जैसे कुल्हाड़ियों से हमला करते हैं। इसी तरह का प्रहार केन्द्र में आपकी सरकार ने किया है..............

श्री मानसिंह महार (आमेर): On a point of order, १२ बज चुके हैं इस सरकार के इसलिये मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये। आपने फरमाया था १२ बजे से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता मुख्य मंत्रीजी को।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): १२ बज चुके हैं इसलिये इनको १५ मिनट का विश्राम और दिया जाय।

श्री हरिराम चौहान: आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है। मैं एक बात का जवाब चाहूंगा, इतना टेक्स केन्द्रीय सरकार ने ८०० करोड़ का....

Page No. 66

एक माननीय सदस्य : इनको १० मिनिट का टाइम दिया था और वह टाइम खत्म हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : Please, be quick.

श्री हरिराम चौहान : मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please, मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। १० मिनट का मैंने कहा है उसके अंदर इनको खत्म करना चाहिये लेकिन पार्टी का समय थोड़ा है इसलिये लैटीट्यूड है। फिर भी माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि within a minute or two आप खत्म कर दें।

श्री मानसिंह महार : स्वतंत्र पार्टी का समय खत्म हो चुका क्या ? कितना समय बाकी है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये पूछते हैं कि स्वतंत्र पार्टी का समय खत्म हो चुका क्या, सो उसका समय तो खत्म हो चुका।

श्री उपाध्यक्ष : स्वतंत्र पार्टी का समय तो है, लेकिन यहां नियमित समय खत्म हो चुका।

श्री मुरलीधर व्यास : स्वतंत्र पार्टी का समय गया।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : मुझे पूरा तो करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : आपने·····

श्री मानसिंह महार : मुख्य मंत्री खड़े हो गये, यह गलत चीज है। हम भी बोलेंगे हमारी पार्टी का समय बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की व्यवस्था के हित में आप खत्म करें।

श्री हरिराम चौहान : मेरी तकरीर को तो खत्म होने दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं।······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से और इनकी सांठ गांठ से खड़े हुए हैं।

श्री हरिराम चौहान : मुझे २ मिनिट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं दे सकता। If the members have objection.......... please don't speak.

श्री हरिराम चौहान : इस तरह से तो हम पहले से ही एतराज कर सकते थे। मैं तो दो ही मिनिट मांग रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : १० मिनिट मुझे भी दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं बिल्कुल असमर्थ हूं।

श्री हरिराम चौहान : जितना टाइम अब लगा है उतने में तो मैं खत्म कर देता।····

Page No. 67

श्री उपाध्यक्ष : आसन से शिड्यूल्ड टाइम था कि १२ बजे सरकारी पक्ष का जवाब होगा, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। तीन घंटियां बजा चुका हूं और इसी प्रकार माननीय श्री गोकुलप्रसादजी को भी बंद करना पड़ा था।

श्री हरिराम चौहान : उनको १० मिनिट बाद बंद करना पड़ा था।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.
मुख्य मंत्री जी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस वर्ष का जो इस सदन में बजट प्रस्तुत किया गया, मुझे इस बात की खुशी है कि आम तौर से इस बजट का स्वागत किया गया। यह स्वाभाविक है कि अलग अलग दलों से जो आये हुए माननीय सदस्य हैं वे पूरी तौर से तो बजट का समर्थन राजनैतिक कारणों से भी नहीं कर सकते और इसके विरोध में कुछ न कुछ तो कहना चाहिये, इसलिये माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने अपने विचार प्रकट किये।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान में क्या क्या होना चाहिये, किस प्रकार राजस्थान का विकास हो सकता है इस संबंध में जहां तक आगे की कल्पना है, मैं समझता हूं सभी तरफ से यह कहा जाता है कि बेकारी दूर होनी चाहिये, लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिये और चीजों के भाव गिरने चाहिये, राजस्थान के अंदर सुविधाएं प्राप्त होनी चाहियें, इस संबंध में कोई मतभेद जैसी बात सामने नहीं थी..........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सरचार्ज छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : लेकिन जब प्रश्न खड़ा होता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाय, तो उस वक्त अलग अलग बातें, अलग अलग दृष्टिकोणों से सामने आने लगती हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस विवेचन में नहीं पडना चाहता कि राजस्थान क्या था और हम आज कहां पर हैं? हमको एक तथ्य स्वीकार करके चलना होगा कि आज जो कुछ हमारे सामने आर्थिक दृष्टि से, आगे तेजी से बढ़ने की दृष्टि से, जो कुछ समस्याएं खड़ी हुई, वे एक प्रकार से डेवलपमेंट की क्राइसिस इसे कहते हैं जो तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं। ये सारी पेचीदगियां हैं जो हरेक राष्ट्र के सामने आती हैं।

राजस्थान में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करीब १०५ करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमने २३६ करोड़ रुपयों की बनाई इन २३६ करोड़ रुपयों में, हमारे साधनों में, कमी के बारे में बाद में जो ओवर ड्राफ्ट था उस ओवर ड्राफ्ट को जो सेल ऑफ लैंड और बैटरमेन्ट लेवी से जो हमने कैपिटल रेवेन्यू के बारे में, कल्पना की थी उसमें कमी होने की वजह से, २३६ करोड़ के बजाय कोर ऑफ दि प्लान २०८ करोड़ का हमने बनाया। इस २०८ करोड़ के बारे में माननीय सदस्यों ने इस बात की कल्पना की थी और सदन में कहा गया कि हम शायद कोर ऑफ दि प्लान को भी पूरा न कर पावें। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के लिये जो बजट में प्रावधान किया गया उस सबका टोटल १५५ करोड़ होता है,

Page No. 68

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

जिसकी अपने चौथे वर्ष में पूर्ति होती है। इस साल के एनुअल प्लान में ४.६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और उसका मतलब यह होता है कि अगर अगले वर्ष, जो १५५ करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं उसे खर्च करने के बाद ५३ करोड़ रुपया और हम प्रोवाइड करते हैं तो जो कोर ग्राफ प्लान हमने रखा है उसकी पूर्ति हम कर लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूं जो कोर ग्राफ प्लान के लिये इन्वैस्टमेंट की कल्पना हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में की है उसको करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा और उसकी पूर्ति हम राजस्थान के अन्दर कर सकेंगे। कोर ही नहीं बल्कि घघ्घर फ्लड के लिए और दूसरी योजनाओं के लिये, जो उस वक्त नहीं थीं और अब आउट ऑफ प्लान राजस्थान म ले ली गई हैं एक परमानेन्ट प्लान के लिए—सबके इन्वैस्टमेंट के लिए जो उस वक्त में सैक्टर था, उस सैक्टर में न होकर—सैक्टर डिफरेन्ट हो सकता है—दूसरे सैक्टर में हो लेकिन टोटल एक्सपेंडीचर २०८ के ऊपर, राजस्थान में होगा।

मैं हमेशा यह बात कहा करता हूं। मैं समझता हू मेरे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे और जो बडे जोर शोर से चेम्बर ग्राफ कौमर्स में हुए भाषण के बारे में कह रहे थे, मैं उस भाषा में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों को इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश ने एक मिक्स्ड इकोनोमी को स्वीकार किया है और उसको स्वीकार करने के बाद पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर—दोनों के रोल्स डिफाइन्ड हैं। दोनों के रोल इसमें होंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि दोनों का रोल होने के बाद जो भी स्टेट है उसका कुल विकास इस बात पर निर्भर करने वाला है कि उसमें टोटल इन पुट कितना होता है? स्टेट सेक्टर के जरिये, सैन्ट्रल सैक्टर के जरिये और प्राइवेट सैक्टर के जरिये। इसलिये राजस्थान के अन्दर इस नीति को अपनायें कि प्राइवेट सैक्टर का काम-काज राजस्थान में नहीं बढने देना है और सारा काम पब्लिक सैक्टर में करना है......

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : पब्लिक सैक्टर के वे खिलाफ हैं। उन्होंने एलान कर दिया है कि हम इन चीजों के खिलाफ आन्दोलन करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरी बात सुनने की, सोचने की कोशिश करिये। अगर हम प्राइवेट सैक्टर को कहते हैं कि राजस्थान में अवसर नहीं दिया जायगा, तो यह हम सब चाहते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो, हरएक जगह-हनुमानगढ़ और बीकानेर में चाहते हैं वहां काम होना चाहिये, अलवर में चाहते हैं कि वहां काम होना चाहिये और और जगह के लिए चाहते हैं कि वहां काम होना चाहिये। प्रश्न यह आता है कि इस सदन में इस बात का जिक्र किया जाता है कि राजस्थान नहर में हमारे प्लान में से इतना रुपया लगा रहे हैं, इस रुपये का एक कौर्पोरेशन बने या नेशनल स्कीम बने या आउट साइड ऑफ सीलिंग हो—इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है और इसके लिए हम इतना फंड प्रौवाइड नहीं कर सकते। सवाल यह आता है चाहे आप पब्लिक सैक्टर में करें—चाहे पौवर जनरेशन करें, रोड्स बनायें, चाहे एजूकेशन के लिये काम करें—कुल मिलाकर जितना

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
आपके पास रुपया है उस रुपये में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी और उन प्रायोरिटीज को डिसाइड करने से क्या इम्पैक्ट होगा ? राजस्थान के ऊपर यह बात लक्ष्य में रख कर चलना होगा। यदि इस बात को तय करें, राजस्थान में हम दूसरी साइड, जो राजस्थान कैनाल और दूसरे बडे बडे प्रोजक्ट हाथ में लेने की वजह से सोशल सर्विसेज के सैक्टर में जितना इन्वस्टमेंट किया जाना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिये उसमें काफी कमी होती हुई चली जा रही है और अगर हम पब्लिक सैक्टर का काम अपनी सीमा के बाहर ले जाते हैं तो उसका असर दूसरी तरफ पड़ता है। इन दोनों को लेकर एक सवाल आता है, साथ साथ यह सवाल·······

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा): घिसी-पिटी तकरीरों से काम नहीं चलता है।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आप नहीं समझ पायेंगे, आसान नहीं है।

श्री **हरिराम चौहान** : घिसी-पिटी तकरीरों से काम नहीं चलेगा।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आप थोडा समझने की कोशिश कीजिये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): जल्दी समझ जाते, अगर गेहूं मिलता तो।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : पब्लिक सैक्टर में पैसा मिलता है तो किसी भी इन्डस्ट्री मे इन्वैस्ट किया जायगा। एक बात मानकर चलना चाहिए, एक पीरियेड होता है, जो प्रोजेक्ट में काम हाथ में लगे इनीशियल स्टेज में प्रभाव होगा। पब्लिक सैक्टर को बढाने के लिये। हम इस बात की कोशिश में हैं, जितना बढ सके हमारे साधनों को देखते हुए और हमें रिटर्न मिल सके–ऐसी योजनायें हाथ में लेनी चाहिये। जैसे नेशनलाइजेशन आफ ट्रान्सपोर्ट के काम को हाथ में लिया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, वह भ्रम में हैं, कि उदयपुर साइड में नेशनलाइजेशन की योजना नहीं हुई है। अहमदाबाद तक भीलवाड़ा और अजमेर से लगा कर नेशनलाइजेशन होने के लिये जितनी कार्यवाही होनी चाहिये वह कर ली गई है। वे भले ही भाषण-मात्र देने के लिये भाषण दे दें। लेकिन अगर नोटिफिकेशन और दूसरी चीजों को देखा होता तो अन्दाज हो सकता था। एक उस काम के अन्दर फंड्स की शोर्टेज का सवाल था इसलिये············

श्री **हरिराम चौहान** : हाईकोर्ट का स्टे कब आ रहा है ? कुछ-लेकुना वैकुना रखा गया होगा जिससे स्टे आ जाय।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : वह हो जायगा तो आप कहेंगे कि वह भी आप लाये हैं। और कहीं दूसरी जगह से आगया तो वह भी हम लाये हैं।

श्री **हरिराम चौहान** : यह जानकारी तो है कि लैकुना रह गया है।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आप बोल रहे थे तब मैंने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। मैं निवेदन करता हूं···

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर): आपने इनको बोलने कहां दिया ?

Page No. 70

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मैं अर्ज कर रहा था, जिन चीजों में जल्दी रिटर्न हो सकता है उनको हाथ में लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त कीमतों के बढ़ने के बारे में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। मैं इस बात को स्वयं मानता हूं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, प्लान का कन्सैप्ट है, उसका मतलब केवल इन्वेस्टमैंट नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ जुड़ी हुई बातें हैं कि जो इन्वेस्टमैंट किया जाय, या पर-कैपिटा इन्कम के अन्दर बढ़ोतरी हुई है वह रियलिस्टिक तभी हो सकती है जब कीमतों के भाव स्थिर रहें अगर कीमत और भाव उस अनुपात से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो निश्चित है कि उसका असर यह पड़ता है, कि पर-कैपिटा इन्कम में डिक्रीज होती है और वह अपसैट हो जाती है। इसलिए यह सवाल सारे भारतवर्ष के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से भारत सरकार से कहा है। हम चाहते हैं राजस्थान में जो व्हीट है या पेडी हिन्दुस्तान में है-यह दो बेसिक चीजें जिनके उपर फूड की कीमतें इधर-उधर होती हैं इनका एक्सपोर्ट राजस्थान से रोका जाय और उसके साथ साथ जो सरप्लस है उसके बारे में चाहते हैं कि इसको वितरित स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा किया जाय और जो बचे उसे यहां से दूसरी जगह भेज दें। और भाव ऊंचे नीचे हों-यह ठीक नहीं है। तो प्रिन्सिपली हम स्टेट ट्रेडिंग के हक में है। मैं चाहता हूं, माननीय सदस्य इस बात को सामने रख कर चलें। जब समूचे लोगों को साथ में रख कर चलते हैं तो यह प्रश्न जुड़ा हुआ होता है कि शुरू शुरू में दिक्कत आ सकती है। उन दिक्कतों की वजह से उस चीज को एक तरफ ट्रेड वाले क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी तरफ हम करते हैं तो हमारे पर्पज को पूरा करने में पेचीदगियां पैदा होती हैं। भारतवर्ष की नीति है, वह अखिल भारतीय नीति है। मूवमैंट ऑफ फूड ग्रेन्स, इस के बारे में सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए फैसला करना है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो होर्डिंग करते हैं, जो रूल्स के अगेन्स्ट में काम करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी और प्राइसेज को बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्टली रोका जायगा......

श्री **हरिराम चौहान** : सख्त कार्यवाही क्या करेंगे ? उसके बारे में खुलासा बता दें।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : नीति तो स्पष्ट हो जानी चाहिये। नीति क्या है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हमको मान कर चलना चाहिये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : चेम्बर के भवन में बैठ कर रोका जायगा।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : इस सदन में हम बैठे हैं। चैम्बर के भवन में बैठने का सवाल नहीं है, यहीं बैठ कर रोका जायगा।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कौन सा एक्शन लेंगे ? यह बतायें ? इससे स्पष्ट कीजिये।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : जो आज कानून है उसके अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार हैं, उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे।

Page No. 71

एक माननीय सदस्य : हाउस में बताया नहीं जा सकता क्या ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह अधिकार था, इसका प्रयोग किया नहीं, कहीं नहीं हुआ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : प्राइसेज जब हाईएस्ट थीं उस बीच जो अलग अलग जगह से शिकायतें आने लगीं तब इसके अनुसार कदम उठाया था और चीप प्राइस शौप्स के जरिये लोगों को दिया है। अब भी इनके जरिये किया जायगा। यह राजस्थान में कदम उठाया गया है इसका निश्चित परिणाम हुआ है कि पिछले दिनों में प्राइसेज नीचे आई हैं साथही साथ हम यह भी एश्योर करना चाहते हैं कि प्राइसेज सर्टेन लेवल के नीचे जायेंगी तो किसानोंसे अनाज गवर्नमेंट ठीक कीमत पर खरीदेगी। दूसरे आदमीएक्स्प्लौइट कर सकें, इस बात का उन्हें मौका नहीं देगी · · ·

श्री **हरिराम चौहान** : जिनके पास बहुत अधिक अनाज का स्टाक पड़ा हुआ है उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है ? उदयपुर के अंदर बड़ा भारी स्टाक है। उसके खिलाफ मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं, भूख हड़तालकर रहे हैं, वहां उचित इन्तजाम सरकार क्यों नहीं करती ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य बीच में भाषण नहीं करें।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : On a ponit of clarification, Sir मैं यह क्लैरिफाई कराना चाहता हूं कि क्या असेन्शियल कौमोडिटीज कन्ट्रोल आर्डर के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह फूड ग्रेन्स पर कन्ट्रोल कर सकती है ? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को बाजरा जाय इसका नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार न निकाला है। आज भी राजस्थान सरकार को पावर्स हैं कि एसेन्शियल कौमोडिटीज कन्ट्रोल आर्डर के प्रावधानों का उपयोग करके फूड ग्रेन्स पर कन्ट्रोल कर सकती है। तो फिर आप भारत सरकार से इसकी परमिशन क्यों चाहते हैं ? यह आप क्लैरिफाई कर दें।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : स्थिति बहुत साफ है पार्लियामेंट में बहस हुई है फूड ग्रेन्स के इन्टर-स्टेट मूवमेंट को रोकने के लिये भारत सरकार को ही अधिकार है, वही रोक सकती है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने के बारे में कभी भी सफलता बीच के रास्ते से नहीं मिल सकती। जो कुछ हम कर सकते हैं पूरी सतर्कता के साथ कार्यवाही की जा रही है और की जायगी

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : On a point of information, Sir.

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : What is this, I do not understand.

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कब लिखा भारत सरकार को ?

श्री **उपाध्यक्ष** : आप भाषण के तारतम्य को नहीं जमने देते।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं पूछना चाहता हूं कि कब लिखा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : तो मैं माननीय उपाध्यक्षजी · · · ·

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। फूड ग्रेन्स के इन्टरस्टेट

Page No. 72

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मूवमेन्ट पर कन्ट्रोल करने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को सबसे पहले आपने कब लिखा था ?

श्री **उपाध्यक्ष** : Order ! please

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : इसके बारे में क्या बात की गई, क्या नहीं की गई इसकी जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं। मैं पर्सनली गया हूं, मैंने बात की है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में प्रोडक्शन के सिलसिले में यह जिक्र किया गया कि राजस्थान का प्रोडक्शन सारे हिन्दुस्थान से पर एकड ईल्ड कम है। मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं और माननीय सदस्य भी जानते हैं, फिर भी जानते हुए यह कहते हैं। राजस्थान को सारे को एक साथ लेकर पर एकड ईल्ड निकालने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि सारे हिन्दुस्तान में डैजर्ट का सबसे बडा हिस्सा राजस्थान में है। इसलिये पर एकडईल्ड कम आयेगा। जहां फ्लोइरिगेशन है, उन कंडीशन्स में व्हीट के बारे में आज स्थिति यह है कि पर एकड ईल्ड हिन्दुस्थान में पंजाब का हाईयेस्ट है और राजस्थान का सैकिन्ड नम्बर है। तो यह भ्रमक बात है कि पर एकड ईल्ड में राजस्थान सारे हिन्दुस्थान से लोएस्ट है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस वक्त हमारे राजस्थान में खास तौर से सारे देश म जो डेढ दो साल पहले चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया उसके कारण एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी उससे सारे देश में एमर्जेन्सी डिक्लेअर की। सारे प्रयत्नों के बावजूद भी पाकिस्तान हिन्दुस्थान में सम्बन्ध सुधरने के बजाय और तनाव में जाते रहे। इस वक्त जब हमारा सदन मिल रहा है, पाकिस्तान के जो स्टेटमैंट्स आते हैं, जो बातें आती हैं, वे काफी तनावपूर्ण और विरोधी भावनाओं को लिये हुए आती हैं। इन विशेष परिस्थितियों में पाक स्पाइज और ऐन्टी नेशनल एलीमैन्टस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने के लिये कहना स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में एन्टी-नेशनल्स पाकिस्तान की दृष्टि से भी और एन्टी-नेशनल्स चाइना की दृष्टि से भी हो सकते हैं। हमारे देश में चाइना के समर्थक मौजूद हैं और पाकिस्तान के इधर-उधर करने वाले भी मौजूद हैं।

श्री **हरिराम चौहान** : आप क्या हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : हम क्या हैं, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है पर आप इस बात को सम्हालियें कि एन्टी नेशनल्स कहां मिलेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : ऐसा कह कर भय दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आप बहुत से डिमौन्स्ट्रेशन्स कर के देश के दिमाग को इन प्रश्नों से दूर ले जाना चाहते हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : डिमौन्स्ट्रेशन्स हम नहीं कराते, देश की भूखी जनता डिमौन्स्ट्रेशन्स करती है। आपने उसे भूखों मार मार कर डिमौन्स्ट्रेशन करने के लिये मजबूर कर दिया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : Order ! please Order

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने भूखी जनता को डिमौन्स्ट्रेशन करने के लिये मजबूर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
किया है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं....

(शोर–गुल मेजों को थपथपाने की ध्वनि)

आपने साजिश कर रखी है इन लोगों से

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order, Order Please

श्री मोहनलाल सुखाडिया : चैम्बर ऑफ कामर्स हिन्दुस्थान की है, हिन्दुतानियों की है, किसी दूसरे देश के साथ मिल कर हम देश को धोखा नहीं दे सकते, वह खतरा हो सकता है तो दूसरी पार्टियों से हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने अच्छा हथकण्डा अपनाया है इस मौके पर सब बातों को टालने का। पर मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यू. के., यू.एस. ए. से आप मिले हुए हैं इससे देश को बडा भारी खतरा है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मुख्य मंत्री इस प्रकार का ऐलिगेश नहीं लगा सकते, यह ज्यादती है। आप नाम बताइये उस पार्टी का। यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार का स्वीपिंग एलीगेशन लगायें पार्टीज पर। कौनसी पार्टी ऐसी है इस देश में जो हमारे देश की गद्दार है ? आप नाम बताइये वरना अपने शब्द वापिस लीजिये।

श्री हरिराम चौहान : वह स्वतन्त्र पार्टी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : छागला साहब यू. एन. ओ. से वापिस आये तभी यह बात मुख्य मंत्रीजी आपसे कहते हैं सैविन्थ फ्लीट वाले लोगों की।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने आप पर आक्रमण नहीं किया है, मैंने तो यह कहा कि देश में और स्पाईज हैं उनसे सचेत रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम भी यही करते हैं गरीब जनता को भूखों तो आप मार रहे हैं, कीमतें बढाने के लिये आप जिम्मेदार हैं, देश को डैफिसिट इकौनोमी आपने दे रखी है, प्रौडक्शन आपका लो हुआ है, कन्ज्यूमर्स के साथ आपने धोखा किया है, प्राइसेज को इतना हाई जाने दे कर और फिर ऊपर से आप कह रहे हैं कि आप भडका रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : Order Order please.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कम्युनिस्ट बहुत होशियार हैं, यह नहीं कहना चाहिये आपको।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी में, जब चीन द्वारा देश पर आक्रमण किया गया था तब आपके अन्दर कई दिनों तक बहस हुई थी कि आया चीन ने आक्रमण किया उसका विरोध किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

इससे एक बात तो जाहिर है कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो चीन के आक्रमण को जस्टीफाई करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैनन, त्यागी, भगवत झा, आजाद ने भुवनेश्वर में आपकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पार्टी में कहा था कि आपकी इकोनोमी डैफिसिट इकोनोमी है। तो पार्टियों में बहस हो सकती है। चीन आप का भी एक दिन दोस्त था।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): मैनन-फैनन कहेंगे तो कांग्रेस से निकाल देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : और हमें इन बातों को और सारी चीजों को अपने लक्ष्य में रखते हुए उन चीजों पर कदम उठाकर चलना चाहिये, क्योंकि आपको तो केवल राजनैतिक दृष्टि से अपना भाषण देने की चिन्ता हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि प्राइसेज जब बढती हैं तो उसका क्या असर होता है। इन बढती हुई प्राइसेज का असर हमारे प्लानिंग पर पडता है इसी से गवर्नमैंट को एक करोड रुपया महंगाई भत्ते के तौर पर देना पडा है। इसलिये इस बढती हुई प्राइसेज के इम्प्लीमैन्टेशन को गवर्नमैंट अच्छी तरह समझती है और गवर्नमैंट यह चाहती है कि इसे बढने से रोका जाए।....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): ब्लैक हो रहा है और गवर्नमैंट उसको रोक नहीं सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसका हिन्दुस्तान और दूसरे राज्यों से संबंध है। इन सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए इन समस्याओं का हल करना होगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपकी चिन्ता को सही समझें किन्तु आपने ब्लैक मार्केटिंग को नहीं रोका है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि आपको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। आप जिस समय बोलते हैं उस समय मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता...

(सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा और मुख्य मंत्री महोदय साथ साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : Order ! please

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समस्या बहुत गंभीर है। प्राइसेज बढती जा रही हैं और आपके यहां राजस्थान में गोदाम भरे हुए हैं जिनका स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया गया है और वह अनाज ब्लैक हो रहा है। आपने आज तक किसी भी ब्लैक करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया और इस वजह से अनाप-शनाप ब्लैक हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अगर आप मुझे आकर एक भी जगह, जहां अन-डिक्लेयरड स्टाक पडा हुआ होने की सूचना दें और मैं उस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं करूं तो आप यह आरोप लगा सकते हैं। आप सूचना दीजिये। हम कार्यवाही तुरन्त करने के लिये तैयार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका विजिलन्स डिपार्टमैन्ट किस काम का है ? आप कह दें कि राजस्थान में कोई स्टौक नहीं पडा है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में स्टौक पडा हुआ है और ब्लैक से बिक रहा है। अभी आपने गंगानगर की तरफ देखा होगा कि बैंकों ने नाज पर लोगो को क्रैडिट देना बन्द कर दिया है और इसके कारण गेहूं की प्राइसेज में ५) रु० मन की कमी आई है और भाव नीचे गिरे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके लिये आप चिन्तित हो रहे हैं, ऐसा मालूम होता है।

Page No. 75

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्टौक के बारे में मैं यह कहूंगा कि.........

(सर्व श्री हरिराम चौहान और श्री गोकुलप्रसाद शर्मा एक साथ बोलने लगे।)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह तो आप मानते हैं कि ५ मन गेहूं के भावों में ५) रु० कम हुए हैं।

(शोरगुल)

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, मुरलीधर व्यास और गोकुलप्रसाद शर्मा साथ-साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं......

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : अभी ७ दिन पहले ही सरकार ने सूरतगढ फार्म में ५० हजार मन गेहूं जो स्टौक में था उसको ७५) क्विन्टल के भाव से नीलाम करके बेच दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उनको अपने यहां क्यों नहीं रखा ? जबकि सरकार खुद खरीद कर बेच रही है, तो सरकार ने इस स्टौक को क्यों बेचा ?

(घण्टी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अभी आपने ७५) क्विन्टल बताया, तो आप बतावें कि क्या भाव पड़ा ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : आप गुमराह न करें....

(शोरगुल)

मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस मामले में जानकारी करेंगे और सही तौर से कार्यवाही करेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ७५) रु. क्विन्टल से क्या भाव पड़ा ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, मुरलीधर व्यास, गोकुलप्रसाद पुनः एक साथ बोलने लगे)।

Order please ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भ्रष्टाचार की बात।

(सर्व श्री गोकुलप्रसाद और मुरलीधर व्यास एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

(शोरगुल)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में इस प्रकार की बातचीत नहीं करें। जो जवाब दिया जा रहा है उसको पहले सुनलें। उसके बाद में बहस करने के लिये और भी तरीके हैं। कट मोशन्स पर आप कह सकते हैं, एप्रोप्रियशन बिल आए उस समय आप कह सकते हैं। यह सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये भी ठीक नहीं है। इसलिये आप सदन

Page No. 76

(श्री अध्यक्ष)
की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। यदि इस प्रकार की बातें करना शुरू कर दें तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं ·

श्री अध्यक्ष : Order please!

मैं माननीय सदस्यों से यह बताना चाहता हूं कि········

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे किसी को संतोष नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते और अपनी ही अपनी कहते चले जावें, यह तो उचित नहीं है। I cannot allow any discussion like that.

श्री हरिराम चौहान : (तिजारा) On a point of Order, Sir. मैं आपसे यह चाहूंगा कि आपने पहले जब कभी इस तरह के आपके रिप्लाईज हुए हैं और आपने जो आंकडे दिये हैं वे सही नहीं हैं और जब गलत आंकडे रखते हैं तो जरूर पूछना पडता है और कहना पडता है कि ये आंकडे गलत हैं······

श्री अध्यक्ष : Order please! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंकडे जो रखे जाते हैं उसका वाद और प्रतिवाद व्यवस्था के अनुसार होता है। अगर आंकडे रखे गये हैं वे गलत हैं तो आप कट मोशन आदि अनेक व्यवस्थाओं द्वारा भी चैलेन्ज कर सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था का ढंग नहीं रहना चाहिये कि जब चाहे आपने कह दिया और दूसरों की सुनें ही नहीं यह तो ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तो सदन की प्रतिष्ठा की बात नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्पष्टीकरण तो होना चाहिये। स्पष्टीकरण के लिये तो कह ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण का जहां तक प्रश्न है वह जरूर होगा। मगर इस तरह से एक सैन्टेन्स बोले और आप इन्ट्रप्ट करें और फिर दूसरा सैन्टेन्स बोलें और इन्ट्ररप्ट करें, और बोलने नहीं दें, यह तरीका तो सदन में ठीक नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : हम तसल्ली से सुनने को तैयार हैं। हमको कोई एतराज नहीं कि इतनी देर क्यों बोलते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जो समस्या है, उसका हल तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं का आदर किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में भाषण देने वाले माननीय सदस्यों को यह मान कर चलता हूं कि वे विचार करते हैं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको गुमराह करने की कोशिश न करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : गंभीरतापूर्वक इनके सारे पहलुओं पर सोचते हैं, उनके इन सारे पहलुओं को एप्रीशियेट करता हूं। मैंने यह कहा कि इन प्राइसेज को कन्ट्रोल करने के लिये जो एक्सपोर्ट राजस्थान से होता है उसके रोकने के लिये हमने इसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बारे में विशेष तौर से भारत सरकार को निवेदन किया है और मैं समझ नहीं पाया कि इस बात के कहने पर भी यह प्रश्न किस प्रकार से खड़ा होता है कि हम इस बात से चिन्तित नहीं हैं. यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक मूवमेन्ट ऑफ फूडग्रेन को कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता तब तक मार्केट फ्री होता है तब तक प्राइसेज को कन्ट्रोल करना बहुत मुश्किल है। स्टेट ट्रेडिंग तब ही संभव हो सकता है जब इससे पहले मूवमेन्ट ऑफ फूड का कन्ट्रोल रेगुलेट किया जाए। जब तक यह नहीं होगा प्राइसेज को कन्ट्रोल करना मुश्किल है। आज सारे हिन्दुस्तान में स्टॉक भेजा जा सकता है, यह सही है लेकिन इसके बारे में, मैं कह रहा हूं और मैं तो यह आशा करके चलता था कि हमारे माननीय सदस्य जो बोले हैं और इससे पहले भी बहुतों ने इसका जिक्र किया है, वे इस बात को पसन्द करेंगे, कि अगर हम स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिये सबसे पहले मूवमेन्ट ऑफ ग्रेन कन्ट्रोल को रेगुलराइज करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ साथ हम यह मान कर चलते हैं कि अगर मूवमेन्ट कन्ट्रोल किया जावे तो फसल बाजार में आवे उसी समय तक के लिये न हो। अगर इसको एडॉप्ट किया जावे तो पूरे साल के लिये मूवमेन्ट कन्ट्रोल किया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जब १९५४ में तिब्बत चीन को दे दिया तो क्या आपके लिए लोग नहीं कह सकते हैं ....

(व्यवधान)

श्री. उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय उपाध्यक्षजी मैं तो इस बात को कह रहा था कि अगर हिन्दुस्तान में चीनी स्पाईज पाकिस्तानी स्पाईज कोई भी इस मामले को आगे बढ़ाता चलता है तो अब तक हमारी जितनी व्यवस्था है उससे और ज्यादा हम सख्त व्यवस्था करेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम जानते हैं कि राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है और इस समय हमारे सामने यह सवाल काफी गंभीरता के साथ खुद राजस्थान के लिये आ रहा है। इसलिये इस बारे में पूरी सतर्कता से कार्यवाही की जायेगी और सख्त से सख्त कार्य किया जायगा और कहीं भी इस प्रकार का मामला आता है तो मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग भी इस मामले में हमें प्राप्त होता रहे।

(१२-४० म. पू.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

माननीय अध्यक्ष जो : . ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देखिये आपकी प्रौटेक्शन के लिये आ गए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी, जो मंहगाई के बारे में बढ़ोतरी की गई उसके लिए कहा गया कि कम है। लेकिन फिर भी जो बढोतरी की गई उसके बारे में जो ओल्ड एज पैन्शन के लिए किया उस संबंध में और दूसरी पैन्शन्स के बारे में जो कुछ रिलीफ दिया गया, उस संबंध में यहां एक एप्रीसियेशन हुआ। मैं यह निवेदन करूं कि हमने जो मंहगाई यहां पर बढ़ाई है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके लिए एक माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ मंहगाई बढ़ाई गई है, उस मंहगाई बढ़ने से जो इन्डैक्स नम्बर में बढ़ौतरी हुई है उससे उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि १९६१ में इन्डैक्स नम्बर एवरेज जयपुर में १३४ था, १९६२ में १३६ हुआ, १९६३ के अन्दर १३४ था लेकिन इस वर्ष दिसम्बर के अन्दर यह इन्डैक्स नम्बर बढ़कर १४५ तक पहुंच गया। अगर हम एवरेज १३५ याने पिछले तीन वर्ष का लें तो उसको लेने के बाद जो बढ़ोतरी इन्डैक्स नम्बर के अन्दर हुई, वह ८.२ पर्सेन्ट के करीब बढ़ौतरी होती है। हम आज लोएस्ट पेड आदमी को सामने रखें क्लास फोर कि जिसकी तनख्वाह, टोटल इमौल्यूमेन्ट्स आज के दिन ५८ रुपये होते हैं। उसको जो पांच रुपये की बढ़ौतरी दी गई है, उसका मतलब ५८ से उसका मिनिमम अब ६३ होगा। उस ६३ का मतलब ८.६ पर्सेन्ट उसके वेजेज के अन्दर इन्क्रीज़ होती है। बढ़ौतरी जो भावों में हुई है, वह ८.२ पर्सेन्ट है । ५ रुपये मिलने से जो लोएस्ट पेड है उसमें इतना फर्क पड़ता है। जिनकी ज्यादा सैलरीज़ हैं उनके अन्दर पर्सेन्टेज धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जायगा। लेकिन जो लोएस्ट पेड है जिसको मैग्जीमम रिलीफ की आवश्यकता है, उसकी पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है।

यहां यह भी कहा गया कि सैलेरीज के अन्दर जो डिस्पैरिटीज़ हैं, लोएस्ट पेड की और हाइएस्ट पेड की वह ज़्यादा है, राजस्थान सोश्यलिज़्म की बात करता है और डिस्पैरिटी बढ़ती हुई चली आ रही है और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले राजस्थान के अन्दर १९५४ में जो लोएस्ट पेड व्यक्ति था उसको मिनिमम ४० रुपया मिला करता था और हाइएस्ट पेड को उसी कैटेगरी में जो हाइएस्ट ग्रेड वाला था उसका लोएस्ट ग्रेड ३८५ रुपये था जो आइ. ए. एस. का होता है। उसी प्रकार जो मैक्सीमम की साइड में है ५४ रुपये क्लास फोर का हुआ करता था और दूसरी तरफ जो हाइएस्ट पेड है उनकी इन्कम टैक्स डिडक्ट करने के बाद २,००० रुपये आमदनी हुआ करती थी। अब जो इन वर्षों के अन्दर चेन्जेज यहां मैंने बताई उनका परिणाम यह है कि जो लोएस्ट ग्रेड शुरू होता है उस जगह डिफरेन्स टैन टाइम्स है। लोएस्ट और मैग्जीमम के अन्दर ४४ टाइम्स का डिफरैन्स। हाइएस्ट पेड व्यक्ति जो राजस्थान के अन्दर था और लोएस्ट पेड जो व्यक्ति है उसके मैक्सीमम के बीच में ४४ टाइम्स का डिफरेन्स था। आज यह अंतर पडा है कि एक तरफ मिनिमम ६०) रुपए होता है और दूसरी तरफ जिसको ३८५) रुपए था उसको ४००) रुपये मिलते हैं। दूसरी तरफ उसी हाइएस्ट के अन्दर ६५ होते हैं लोएस्ट पेड के और दूसरी साइड में जो हाएस्ट है उसको २०२९ मिलते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मिनीमम ६० बेसिक सैलरी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: बेसिक सैलरी प्लस डी. ए. किया है और दूसरी तरफ वह जिनकी मैग्जीमम सैलरी है माइनस इन्कम टैक्स जो उनको नैट मिलता है क्योंकि वही कम्पेरेबल फिगर होगा कि किसके पास कितना पैसा पहुंचता है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): कितना गुना फर्क है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पहले लोएस्ट पर टैन टाइम्स और हाएस्ट पर ४४ टाइम्स। अब चेंज के बाद जो नीचे लोएस्ट हैं उनका डिफरैंस १० टू १७ टाइम्स हुआ और ऊपर जो ४४ टाइम्स था वह २१ टाइम्स हो गया। इसलिए इस बात को समझें कि पहले जो डिफरैंस ऑफ मार्जिन था वह बढ़ता जा रहा है गवर्नमेन्ट सर्विसेज के अंदर, वह न होकर नीचे के वे.जे.ज को बढ़ाकर; ऊपर के साइड में करीब स्टेशनरी और इन्कम टैक्स और दूसरी टैक्सेज़ आने की वजह से यह डिफरैंस इसके बीच में कम होता हुआ चला जाता है और वह डिफरैंस इसके अंदर कम हुआ है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जितने हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं हम इस मामले में जो कुछ कर सकते हैं वह करेंगे।

हम जानते हैं कि जो हमारे लो पेड ऐम्प्लाईज हैं उनके सामने तकलीफें हैं और आज के इस जमाने में जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें और बहुत सी चीजों में फर्क है। लेकिन ये सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि हमारे साधन कितने बढ़ पाते हैं। हमारी पंच वर्षीय योजनाओं जिसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके रिटर्न्स बहुत देर से होने वाले हैं, उसके लिए यह सुझाव रखा गया। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान कैनाल के लिये इसको नेशनल प्रौजेक्ट बनवाने के लिये पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल को हर लैवल पर हम पर्स्यू कर रहे हैं, और इन्हीं दिनों आज कल में प्लानिंग कमीशन की तरफ से सारी बात की स्टडी करने के लिए एक सीनियर ऑफीसर राजस्थान के अंदर आ रहे हैं जो इस बात को देखेंगे कि यह नैशनल प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। हम खुद जानते हैं कि इस राजस्थान कैनाल का इस पंच वर्षीय योजना में जितना हमारे पर वजन आया है, चौथी पंच वर्षीय योजना में पौंग डैम, राजस्थान कैनाल, सतलज, व्यास इन सब चीजों के लिये जो एप्रोक्सीमेट ऐस्टीमेट्स तैयार हुए हैं २००, २२५ करोड़ रुपये चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए प्राप्त करने होंगे जो कि राजस्थान के रिसोर्सेज के लिये बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमने बारबार उनके सामने अपनी दिक्कतें रखी हैं और इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर आगे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रौजेक्ट में जो हमारा सोशो इकोनौमिक आउटलुक है उसको भी इम्प्लीमैंट करने का मौका है। अगर फन्ड्स पूरी तरह से हों तो सब बातों के बारे में डैफीनिट पौलिसी इवौल्व की जा सकती है और उस चीज को इम्प्लीमैंट किया जा सकता है जिसको इम्प्लीमैंट करने से न सिर्फ वह राजस्थान के लिए अच्छी चीज हो सकती है, बल्कि सारे देश के लिए वह चीज हितकर बन सकती है। इसलिये उस दिशा में हम उस दृष्टि से आगे बढ़ने के लिये लगातार प्रयत्नशील हैं।

माननीय अध्यक्ष, इस सिलसिले में लसाडा डैम के बारे में माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया और उठा कर यह कहा कि लसाडा डैम की जो ड्रेन कन्स्ट्रक्ट की जा रही है उससे राजस्थान को काफी परेशानी होगी और राजस्थान को काफी नुकसान होगा। इस स्थिति में पहले भी इसके संबंध में हम जिक्र कर चुके हैं और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
करना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रीजी को इसी सम्बन्ध में इन्टरवीन करने के लिए लिख चुका हूं क्योंकि राजस्थान के लिए यह काफी गम्भीर प्रोब्लम खड़ी हुई है जिससे हम को नुक्सान हो सकता है ।

इस संबंध में जहां तक टैक्निकल ओपिनियन का सवाल था पंजाब ने पहले फ्लड्स स्कीम को हाथ में लेने के लिये कहा था उस मौके पर भी टैक्निकल कमेटी ने भी फ्लड वाटर को ड्रेन करने के लिये इस बात को सजेस्ट किया था कि चान मान डैम के जरिये सतलज में उसके पानी को डाला जाय । इसलिये वह चीज यहां लाई जाती है तो राजस्थान तब तक उसको स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि टैक्निकल एक्सपर्ट्स बैठ कर राजस्थान को नुक्सान न होगा डिटेल्स में उसको तय कर लें । यदि पंजाब यूनिलेटरी इसको करता है तो राजस्थान निश्चित रूप से राजस्थान के गांवों को फ्लड से डूबने से रोकने के लिए हमें जो कार्यवाही करना है हम भी करेंगे । हम यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे गांवों को वे फ्लड कर दें । हमें कोई विरोध नहीं है कि पंजाब में वाटर लौगिंग है उसके लिये वे कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंन्ट करना चाहें, हम इन्कार नहीं कर सकते हैं, देश के हित में ऐसी चीज को हाथ में लेना चाहें हमें कोई विरोध नहीं है । लेकिन सवाल यह है कि जो घग्घर की योजना बनाई जो इस ड्रेन से पानी आयेगा उसके लिये पहले से व्यवस्था नहीं की गई । घग्घर फ्लड की योजना भी टैक्निकल बोर्ड द्वारा एप्रूव नहीं की गई और जो स्कीम वे हाथ में लेकर काम में ले रहे हैं वह एप्रूव्ड स्कीम नहीं है । पूरी चीज को देखने के बाद जो पानी सरप्लस आता है उसको कहां डाइवर्ट किया जा सकता है बहा करके, ड्रेनेज करने के लिये उसके लिए योजना बना कर कार्यान्वित की जाय हम यह कहते हैं ।

मुरलीधर व्यास : डैम के संबंध में स्पष्टीकरण कर दीजिये कि सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के स्टेटमेन्ट के मुताबिक यह है कि राजस्थान के कृषि मंत्री पंजाब के कृषि मंत्री और केन्द्र के कृषि मंत्री ने जो प्रपोज़ल मंजूर किये हैं उनके आधार पर यह हुआ है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिलकुल गलत है । पंजाब सरकार जो योजना डैम के बारे में कर रही है उसको राजस्थान के किसी मंत्री ने किसी स्टेज पर मंजूर नहीं किया है ।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : गलती से किया हो ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : नहीं । ऐसा नहीं हुआ ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : आपने कोई प्रतिवाद निकाला ? इन्डियन एक्सप्रेस में यह न्यूज आयी थी कि भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी को यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजस्थान ने यह कह दिया तो !

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : न्यूज पेपर में समाचार आये । मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, तो वह कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है ।

Page No. 81

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले ही कह देना चाहिये था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले ही कह चुके हैं । उनकी तरफ से यह बात हुई और एग्रीमेन्ट के खिलाफ हो रही है उसके कॉन्ट्राडिक्शन की आवश्यकता नहीं । फिर भी आपने कहा आपके सामने उस बात को स्पष्ट किया ।

उसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष, गंग केनाल में पानी कम आने की बात और भाखरा में पानी कम आने की बात समय समय पर आती है और उसकी वजह से राजस्थान के गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोडक्शन पर भी काफी असर हुआ है । इस संबंध में इसका स्थायी हल करने की दृष्टि से हमने शुरू से ही जोनल कौंसिल की मीटिंग में इस बात को रखा था कि ऑटोमैटिक रैगुलेटर्स के द्वारा जो हिस्सा पानी का हमारा है उसका इन्तजाम किया जाना चाहिये । अभी रिसेन्टली हमने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी और भारत सरकार के जो इर्रीगेशन मिनिस्टर हैं, उनको भी इस बात के लिये निवेदन किया है राजस्थान के इन्जीनियर्स को पंजाब में से जो पानी हमारा आता है उसको बराबर चैक करने के लिए हम रखें उसके बारे में वे स्वीकृति दें । मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार और पंजाब सरकार स्वीकृति देंगी जिससे इस प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की शंकाएं न उठ सकें, वास्तविक स्थिति से अवगत रहें । यह हल निकल सकेगा । यह इसलिये भी आवश्यक है कि राजस्थान में गंग केनाल, भाखरा केनाल और राजस्थान केनाल में ज्यादातर पानी उधर से ही आता है । उसके रैगुलेशन और उसकी पूरी क्वान्टिटी मिलते रहने की व्यवस्था हो यह आवश्यक होगा उस दृष्टि से इस ओर जो प्रयत्न किये जा सकते हैं, किये जा रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इतनी देर से यह प्रयत्न क्यों किये जा रहे हैं, इसका भी कोई जवाब है ? क्या सिंचाई मंत्री चार साल तक सो रहे थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो स्टेट के बीच का मामला है । हमने निवेदन किया कि ऑटोमैटिक रैगुलर वाली बात दो साल नहीं, तीन साल से भी ज्यादा हुआ होगा उसको जोनल कौन्सिल में तय करवाया गया था । इसीलिए हमने कहा है कि उनकी केनाल से जितना पानी आता है या तो पंजाब सरकार के एग्रीमेन्ट से या भारत सरकार के इन्टरवीन करने से हमारे अफसर वहां बैठे रहें यह देखने के लिए कि पानी की सप्लाई हम को बराबर होती रहे । सोते नहीं रहे हैं, जागते रहे हैं । दूसरी स्टेट में जाकर कब्जा करने से तो रहे । उस चीज को लिखा पढ़ी से जितना एजीटेट किया जा सकता है किया जा रहा है, जिस पौइन्ट ऑफ व्यू से रखा जाना चाहिये उसके अनुसार रखा जाता है और यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिये हम कभी भी झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा ।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपका रुख बहुत नरम है । पंजाब सरकार और भारत सरकार के सामने बहुत झुकते जाते हैं ।

Page No. 82

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को आप सेफ गार्ड नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जितनी बात कही गई है और जो कुछ किया गया है वह राजस्थान के इन्ट्रेस्ट के अन्दर ही किया गया है। कभी राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को ओवर लुक नहीं किया गया है और पंजाब में जाकर के जहां से पानी आता है उसको कन्ट्रोल करने की बात सोच लेते हों तो लीगल प्रोब्लम को सोच लेने की बात है··

श्री मानिकचंद सुराणा : We want net results and not the protest notes alone like the Government of India. चीन ने हमला किया तो प्रोटेस्ट नोट भेज दिया। पंजाब सरकार ने किया तो चिट्ठी भेज दी। We want net results and not the protest notes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : १९५९ से लेकर आज तक १९६४ में पांच साल में कितने रेगुलेटर लगवा दिये हैं? कितने अफसर ड्यूट हो गये और कितने अफसरों ने इस चीज को ट्रेस आउट किया है कि गंगकेनाल एस्केप केनाल चल रही है? १९५५ में भाखरा की सप्लाई शुरु हो गई। १५ पर्सेंट का राइट है। १० प्रतिशत एक्सीड नहीं हुआ। पांच साल में क्या कौन्क्रीट स्टैप लिये? केवल यह कहना कि यह किया वह किया इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

(१.०० म. पू.)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस संबंध में पहले भी कह चुका हूं। किस किस डेट को क्या क्या कार्यवाही की गई। इस वक्त सारी डेट्स मेरे पास मौजूद नहीं हैं। यह सवाल बार-बार उठाया गया है और उठाया जाता रहा है हम विधान के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं। हम कौन्स्टीट्यूशनल मैथड के अलावा और कोई रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते, उस भाषा में बोलने में भी हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे वाजिब हक हैं और दूसरी तरफ से ज्यादतीवाली बात है उसका भी हल होने वाला है उस बारे में हम पूरी तरह से सतर्क हैं और समय पर जो भी कदम उठाना आवश्यक होता है वह उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूँगा कि जब आप यह मानकर चलते हैं कि पंजाब सरकार के इस डैलीबरेटली कम पानी दिये जाने की वजह से जो लौस हुआ वह ४६ हजार मैट्रिक टन के करीब है। उस लौस के लिये कान्स्टीट्यूशनली ऐसी पोजीशन नहीं है क्या कि भारत सरकार इसमें इन्टरवीन करके राजस्थान सरकार को जो इस कारण लौस हुआ है उसको पंजाब सरकार से कम्पनसेट करवाए?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब तक वहां कितना पानी रिलीज हुआ कितना दूसरा हुआ यह सब बातें पूरी तरह से तय नहीं होती हैं जो इस साल लौस हुआ उस तरफ हमने ध्यान दिलाया है। इस सवाल को जब कि टैकनिकल एक्सपर्ट्स द्वारा क्या हमारे राइट्स थे आरबीट्रेशन के तरीके पर डिटेल्स में न जायं तब तक फाइनल इस संबंध में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कहना कि इतना लौस है, ठीक नहीं होगा। यह इस प्रकार का सवाल है कि इस बारे में थर्ड पार्टी ही डिसीजन कर सकती है। इस प्रकार डैमोक्रेटिक कन्ट्रीज में इस प्रकार का जब सवाल पैदा होता है तो थर्ड पार्टी उसका डिसीजन करती है हमारे लिये वह भारत सरकार हो सकती है, वह इस बारे में सोच रही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं जिस पौइन्ट को स्ट्रैस कर रहा हूं वह यह है कि पानी के न मिलने से जो हमको लौस हुआ है उसे कम्पेन-सेट कराया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम्पेन-सेट कराने की बात तो तभी ऐस्टेब्लिश होगी जब ऐक्जैक्टली यह मालूम हो जाय कि इतना पानी हमें मिलना चाहिये था उतना पानी हमारे यहां आया या नहीं। जैसा कि उनका कहना है कि उन दिनों वाटर रिलीज कम था इसलिये नहीं आया, इससे हमारे हक में कितना फर्क पड़ा, यह सब एस्टब्लिश न हो जाय तब तक दूसरा प्रश्न पैदा नहीं होता। यदि ये सब बातें तय न हों उससे पहले ही हम यह प्रश्न खड़ा करदें तो यह इशू साइडट्रैक हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं यह राइपेरियन राइट्स का डिस्प्यूट है। राइपेरियन राइट्स का डिस्प्यूट हो तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को यह निवेदन किया है कि इस समस्या को आर्बिट्रेशन के अन्दर रखा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब हम भारत सरकार से कहते हैं कि वे इन्टरवीन करें इसके लिये रास्ता उपलब्ध है। वे स्वयं इस सारे मैटर को बिना आर्बिट्रेशन के ही हल कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चार साल तो हो गये। आखिर कितने दिन तक ठहरे रहें ? कितने दिन तक इन्तजार करें ? राइपेरियन राइट्स का क्वेश्चन है इसलिये राजस्थान सरकार द्वारा आर्बिट्रेशन की मांग करना उचित होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक बार जिस सवाल को उनके सामने रख रखा है वह अगर हल नहीं होता है तो उसके बाद में इन मैथड्स को इवोल्व करने के बारे में विचार करना उपयुक्त होगा। मेरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया में जो पौइन्ट्स मैंने उठाये हैं उसको डिटेल्स में सारी पोजीशन से पूरी तरह से सीज्ड है। जो राजस्थान का हक है उसको देखते हुए वे निर्णय करेंगे। इस मौके पर भारत सरकार से यह मानकर न चलें कि वह ठीक नहीं करने वाली है इसलिये डाइरैक्ट आर्बिट्रेशन के लिये उनसे कहें यह उचित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या भारत सरकार से निवेदन किया कि वे स्वयं आर्बि-ट्रेशन करें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले वे अपनी तरफ से दोनों पार्टीज से बातें करते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
हैं। जब हम आर्बिट्रेशन के लिये कह देते हैं तो केवल अवार्ड देने की बात रहती है। पहले दोनों पार्टीज को बुलाकर समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद स्टेज आती है आगे क्या कार्यवाही की जाय?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय . .

श्री अध्यक्ष : मेरा यह कहना है कि इस पर मुख्य मंत्री भी सहमत होंगे कि माननीय सदस्यों की एक इन्फौर्मल कन्सल्टेटिव कमेटी बन जाय जो समय समय पर जो पानी चल रहा है उसके बारे में देखें। जैसे मिस्टर हांडा ने भी इस बारे में वक्तव्य दिया था गांवों में दिक्कत है; ये सारी बातें आपके सामने बैठकर माननीय सदस्य कर लें। इस तरह की कमेटी मीटिंग साल में दो चार बार हो जाय तो माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा कि सरकार की ओर से कदम उठाया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई एतराज की बात नहीं है बीच बीच में बैठकर बातें की जा सकती हैं। इसमें कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दूसरे माननीय सदस्य भी बैठकर विचार करके सलाह दे सकें। इसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक क्लैरिफिकेशन सीक करना चाहूंगा, यह कमेटी स्पौट पर जाकर भी देख सकती है कि ऐसी घटनायें होती है।

श्री अध्यक्ष : यहां ये सब बातें तय करना उचित नहीं होगा। मुख्य मंत्रीजी ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सदन में एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये ३२ करोड़ रुपये के एडीशनल टैक्स के लिये कहा था, उसकी जगह ४२ करोड़ रुपया वसूल कर चुके हैं, अभी अगला वर्ष बाकी पड़ा है। उस समय भी मैंने बीच में कहा था कि यह जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है। एडीशनल टैक्सेज के जरिये जो राजस्थान के अन्दर अब तक टैक्सेज लगाये हैं उससे तीसरे साल तक यह अन्दाज लगाया जाता है ३०.३१ करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। जो एक्साइज इकट्ठा होने की बात है वह ट्रेड इन्क्रीज की वजह से बढ़ा है ज्यादा स्ट्रिक्टनैस और दूसरे दूसरे स्टैप्स लेने की वजह से बढ़ा है। असल में टैक्सेशन की वजह से बढ़ोतरी होने वाली है। वह भी अगले साल के अन्त तक ३०.३१ करोड़ की होने वाली है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : एडीशनल टैक्सेशन से कितनी आय हुई है, यह बतलाइये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगले साल तक ३०.३१ करोड़ होगा और ज्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो ४१ करोड़ के आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये, उनको कान्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उन्हीं को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं।

फेमीन अफैक्टेड एरियाज के लिये १ करोड ८७ लाख का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने कहा, यह व्यवस्था जितनी की गई है वह इतने भीषण अकाल को देखते हुए कम है। इसके लिये ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। मैं इतना कह कर चल सकता हूं कि इस अकाल के कार्य के लिये अभी माननीय सदस्यों को पता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा यू. एस. ए. गवर्नमेंन्ट ने फूड ग्रेन्स की अपनी तरफ से एड दी है। हमने भी कुछ व्यवस्था रखी है। इस व्यवस्था के बाद भी यदि ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता होगी तो जैसे पहले भी मैं सदन में निवेदन कर चुका हूं और आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस बारे में खर्च का संबंध है, कोई कमी नहीं रखी जायगी। जहां भी रिलीफ वर्क के लिये आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था की जायगी।

फीडर बैंक के लिये भी सुझाव आया था उसके लिये भी व्यवस्था चल रही है। हम इसको भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसके लिये भी राजस्थान में कदम उठायेंगे।

कोल्ड वेव के बारे में भी प्रश्न किया गया यह मैं मानता हूं कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है। पहले भी मैंने सदन में निवेदन किया ऐसे इलाकों की रिपोर्ट जल्दी मंगाली गई है। कलेक्टर्स की कौन्फ्रेन्स हुई उसमें भी कहा है जिन इलाकों में नुकसान काफी हुआ है और वहां रिलीफ वर्क्स की आवश्यकता है तो रिलीफ वर्क्स के लिये आवश्यक कार्यवाही उस क्षेत्र के अन्दर की जायगी।

ट्यूब वैल्स की योजना है। २५० ट्यूब वैल्स भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं किस किस जगह कितने कितने कुए होने चाहियें इसके बारे में हमारा अन्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया का बोर्ड द्वारा इस काम को हाथ में लिया जायगा। इस पर जो भी धन खर्च होने वाला है वह बजट में रखा हुआ है उससे अतिरिक्त खर्चा होगा वह धन जुटाया जायगा। इससे हमें इरिगेशन और पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। ड्रिंकिंग वाटर के लिये ट्यूब वैल्स हो जायेंगे तो इसके फीडर बैंक्स को ओर्गेनाइज करने में आसानी हो जायगी। इससे जो हमारे यहां हर दूसरे साल अकाल पड़ने की समस्या होती है उसका काफी समाधान हो जायगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सब से ज्यादा जोर इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने दिया वह सरचार्ज ऑन लैण्ड रैवेन्यू हटाने के बारे में था। इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं यह भी कहा गया। इस बारे में वित्त मंत्री महोदय से मैंने चर्चा की थी। वित्त मंत्री महोदय ने इस बात की सहमति दी है कि जो हमने पिछले वर्ष जहां ५० रुपये की सीमा तक सरचार्ज लेने की बात कही थी। इस वक्त में जो कानून है उसकी वजह से कुछ गलतफहमी की वजह से जो एक खाते के अन्दर अगर दर्ज किया हुआ है अलग अलग हिस्सा है सैटिल-मेन्ट के परचे के अन्दर उसमें जौइन्ट खाते में टोटल लगान होता है उस आधार पर सरचार्ज वसूल किया जाता है। वित्त मंत्री जी से हमने बातचीत की उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया है ५० से बढ़ाकर वापिस उसकी लिमिट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

७५ कर दी जाय। साथ ही यह भी कर दिया जायगा जिसका सैटलमेन्ट खाते में अगर हिस्सा अलग से दर्ज है उसको अलग खाता मानकर ट्रीट किया जावेगा। उस खाते पर लगान चार्ज नहीं किया जावेगा। इससे काफी रिलीफ मिल जायगा। जिनका कि बारानी के हिसाब से है···

श्री हरिराम चौहान : Point of information, Sir,............

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये पहिले, वक्तव्य को समाप्त होने दीजिये। आप फिर पूछ लेना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चाही जमीन वाले को १।३ समझ कर लगान चला जावेगा जिसका मतलब यह हुआ कि जिसका लगान है ७५०) इरिगेटेड चाही का, तो २५०) रु० उसका समझा जावेगा। यह समझ कर वर्क आउट किया जावेगा। इससे जो बजट प्रावधान रखा गया है उसमें करीब बीस लाख का घाटा होगा, जिसके सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी बाद में कहेंगे। लेकिन जिन लोगों की जो दिक्कतें हैं इससे उनकी ये दिक्कतें दूर होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ प्राप्त हो जावेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : घाटे की घोषणा वे करें ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं जानना चाहूंगा....

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू):– सटलमेन्ट रेकॉर्ड में जैसा छपा होगा, उसकी लिमिट वैसी मान लेंगे। पर मुमकिन है पंचायतों में पिता की डैथ होने के बाद में भाइयों के हिस्से छूट जाते हैं तो उसमें कैसे लिया जावेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व):– इसका सरचार्ज से क्या सम्बन्ध ? उसका तो म्यूटेशन से है।

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। कानून और नियम जब निकलें तो उसमें सुझाव देंगे माननीय सदस्य तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्य : क्लैरिफिकेशन··

श्री अध्यक्ष : No clarification. अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। अब वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण देंगे। (अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

ये सारी बातें आप सोच लें। फिर बहस के टाइम पर ले लेंगे। अभी सारी चीजें आ नहीं सकती।

(घण्टी)

श्री हीराभाई : भूमिहीनों की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये जानना चाहूंगा। उस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? इसके बारे में आश्वासन चाहूंगा कि कैसे उनकी बढ़ती हुई संख्या को वे रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्रीजी को सुनिये आप।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):– वित्त मंत्री जी से एक रिक्वैस्ट करूंगा;

(श्री भैरोंसिंह)
मुख्य मंत्रीजी ने तो बीस लाख के कर हटाकर सदन की प्रशंसा प्राप्त की है । अब बाकी १५ लाख रह जाते हैं । तो कहीं वित्त मंत्री जी न चूक जावें ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों की अनुमति चाहूंगा कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जावे जब तक कि वे अपना भाषण समाप्त न करदें ।

(स्वीकृत)

सदन का समय तब तक के लिये बढ़ाया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : बशर्ते कि वे छूट की घोषणा करें ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री):– बजट भाषण के वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि जो बजट में पेश कर रहा हूं वह बेजायका है । लेकिन········

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण तो कहीं ऐसा नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन जो चार-पांच दिन की बहस हुई उस पर से इस किस्म का असर नजर आ रहा है । लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए और भाषण दे रहे थे तो कुछ माननीय सदस्यों से रहा नहीं गया और उन्होंने यह चाहा कि इस बेजायके को बाजायका कर दिया जावे ।

मैं समझता हूं कि उसके पीछे जो उनके लक्ष्य थे, मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं, कि ये आने वाले जो बाई इलैक्शन हैं, खास कर गंगानगर की तरफ, वे बाई-इलेक्शन अभी से उनको परेशानी पैदा कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह तो सदस्यों पर एक प्रकार का एस्पर्शन है । मैं अर्ज करूंगा वित्तमंत्रीजी से कि इस दृष्टि-कोण से नहीं, मंहगाई के दृष्टिकोण से यह सब कहा है ।

श्री अध्यक्ष : तो अब आप इसका वित्तीय पहलू बतावेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्······

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) आप तो इनमें हारने वाले नहीं हो आपको: क्यों फिक्र है इसकी ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो मुख्य मंत्रीजी ने अभी सरचार्ज में छूट दी है वह कहां तक उन माननीय सदस्यों को अच्छी लगी होगी जो इसका कैपिटल बनाना चाहते थे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम तो कहेंगे कि यह हमारे कहने से छोड़ दिया ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप यही मान लीजिये । आखिर किसान का भला तो हुआ है । यह बुरी बात नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कब से छूट दी है यह आपने ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये, मैं, चूंकि समय समाप्त हो चुका है और हर पहलू को मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे योजना मंत्रीजी ने, हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने, हर पहलू से अपनी बातचीत आपके सामने रक्खी । लेकिन

Page No. 88

(श्री बालकृष्ण कौल)
कुछ ऐसे विषय रह गये हैं कि जिनको मैं साफ कर देना ही मुनासिब समझता हूं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): अनाज पर से सैलटैक्स साफ कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : अपोजीशन की तरफ से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब भाषण दे रहे थे तो मैं बहुत गौर से उसे सुन रहा था। मैं कह नहीं सकता कि जो मुद्दे उन्होंने उठाये उनमें कितनी हकीकत थी। हो सकता है कि उनके पास जो खबरें हों, वे पूरी न हों, लेकिन उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिये मैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं, उनको साफ कर देना चाहता हूं।

शुरू में ही एक उन्होंने यह प्रश्न किया कि जब यह आठ करोड़ का घाटा था, इस बजट में, तो वित्तमंत्री ने किस तरीके से यह आठ करोड़ का घाटा पूरा किया। अगर साधारण तरीके से प्रश्न को वे रखते तो भी उसका जवाब मिल जाता, लेकिन आदत के मामूल उन्होंने इसके साथ जो क्वालिफिकेशन लगाई हैं, फ्रॉड की, उस पर ताज्जुब हुआ। क्या गवर्नमेन्ट इतना बड़ा भारी फ्रॉड कर रही है सदन के सामने?

श्री मानसिंह महार (आमेर): वह तो ज्वालाप्रसादजी की दोस्ती की वजह से है।

श्री बालकृष्ण कौल : जहां तक फ्रॉड का कहा, मैं आंकड़े रख देना चाहता हूं।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य याद करें कि जब पिछला बजट मैंने पेश किया था उस समय मैंने कहा था कि १.६ करोड़ का घाटा रहेगा और फिर आगे चल कर यह भी मैंने बताया कि दो साल के दौरान में हम एडीशनल एक्सपेन्डीचर ओन फ़ैमिन पर २.२ करोड़ करना पड़ेगा। इसी तरीक़े से सस्पेन्शन ऑफ़ रेवेन्यू के लिए कहा था कि १ करोड़ होगा और यह भी मैंने कहा था कि रिकवरीज में इस फैमिन के सबब से ५०लाख की कमी हुई है। और इसी तरीक़े से वह २० करोड़ का लोन, जो गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया से लिया था उसकी अदायगी के लिए २.७ करोड़ की कमी थी। तो यह सब मिलाकर ८ करोड़ होता है। यहां तक तो उनका आंकड़ा ठीक है। लेकिन इनका हम कैसे भुगतान करने जा रहे हैं और यह कैसे इक्वेट हो रहा है, वह शायद आंकड़ों से वाकिफ़ नहीं हैं,....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): मैं तो वाकिफ़ हूं। आप तो पढ़कर सुनायेंगे मैं वैसे ही सुना दूं।

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो अच्छी बात है। तो वह फ्रॉड नहीं था।

श्री भैरोंसिह : वह फ्रौड था। आपने जिस कान्फीडेन्स से हाउस में टैक्सेशन के प्रपोजल्स लाये उससे ४ करोड़ ४५ लाख रुपये बढ़ गये यह फ्रॉड था।

श्री बालकृष्ण कौल : खैर, अब वह फ्रौड होगा, आपकी निगाह में। इसलिये श्रीमन्, फ्रौड की व्याख्या तो आपके सामने हो गयी। अगर एक्सपैक्टेड रेवेन्यू किसी से की जाये और उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाये..

श्री भैरोंसिह : थोड़ा सा नहीं है।

Page No. 89

श्री बालकृष्ण कौल : जैसा मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़ीशियेन्सी के लिए जो लूप-होल्स थीं उनको हमने प्लग किया · · ·

श्री भैरोंसिंह : आपकी एफ़ीशियेन्सी तो आप नॉन-टैक्स रेवेन्यू में देख लेना।

श्री बालकृष्ण कौल : तो श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि यह फ्रौड की व्याख्या जो माननीय सदस्य ने की वह मुनासिब है या नहीं।

खैर, उन्होंने सब बातों के साथ साथ एक चीज़ मुख्यतः कही वह मैं नहीं कह सकता कि वह मेरे लिए कॉम्प्लीमेन्ट्स थे या नहीं। उन्होंने कहा कि वित्त मन्त्री मिसमेराइज करते हैं। काश कि वित्त मन्त्री आप पर भी असर डाल सकते और जो अल्फ़ाज़ आपने इस्तैमाल किये वह आपके मुख से नहीं निकलते तब तो वित्त मन्त्री मानते कि यह मिस्मेरिज्म जानते हैं। वित्त मन्त्री होते ही वह हैं जिनमें यह खूबी हो। अगर वित्त मन्त्री अपने आंकड़ों से मिसमेराइज न करें तो वह वित्त मन्त्री रहने के क़ाबिल ही नहीं है · · · ·

श्री अध्यक्ष : और मैस्मेराइज और फ्रौड में क्या फ़र्क़ है?

श्री भैरोंसिंह : वह एडवोकेट जनरल से पूछा जाये।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : यह खूबी कहां से सीखी आपने?

श्री बालकृष्ण कौल : आपकी ही कृपा से।

श्रीमन् जहां तक इस फ्रौड का ताल्लुक़ था उसका जिक्र तो मैंने कर दिया। इसके अलावा माननीय सदस्य ने इस पर भी ज़ोर दिया कि अगर एफ़ीशियेन्सी थी और कुछ लूप-होल्स को प्लग करने की हमारे में क़ाबलियत थी तो नॉन-टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ी · · · ·

श्री **माणिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : Point of clarification, Sir.

श्री **बालकृष्ण कौल** : क्लैरिफ़िकेशन आखिर में होगा।

श्री **माणिकचन्द सुराणा** : Point of clarification, sir, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ८ करोड़ के घाटे की बात कही थी और आप उसका चार्ट दे रहे थे वह दीजिए। ८ करोड़ का घाटा इस कारण से हुआ वह आपने कैसे पूरा किया इस सम्बन्धी चार्ट दीजिये।

श्री **बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्य लिखें।

श्री **माणिकचन्द सुराणा** : क्या लिखें?

श्री **बालकृष्ण कौल** : मैं आंकड़े बता रहा हूं।

श्री **माणिकचन्द सुराणा** : लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहां ५-७ रेकॉर्डिस्ट बैठे हैं, आप तो बता दें।

श्री **बालकृष्ण कौल** : श्रीमन्, यह पूरा कैसे हुआ, यह मैं आपको बतादूं। गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया से हमको एक्सेलरेटेड असिस्टेन्स मिली २.५ करोड़ की। हमारा सैन्ट्रल टैक्स से एडीशनल शेयर आया ६० लाख रुपया। इनकम टैक्स में, ५० लाख,

(श्री बालकृष्ण कौल)
एक्साइज में, फ़ैमिन में असिस्टेन्स आई १ करोड़ की और सेल्स टैक्स की रिकवरी में इम्प्रूवमेन्ट १ करोड़ का। एल. आई. सी. से ४० लाख रुपया, अजमेर वाटर वर्क्स का पड़ा हुआ है हमारे पास। एरियर सैन्ट्रल असिस्टैन्स से १९६१-६२ का ६० लाख आया, और १९६२-६३ का १।। करोड़ में से इस वक्त आ चुका है ७१ लाख रुपया। इस तरह से कुल ७९ लाख का अभी आना है गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया से। अब मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि पेज नं० ९....

श्री **भैरोंसिंह** : यह जो आपकी इन्कम हुई है यह सारी एफ़ीशियेन्सी का रिज़ल्ट है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : एफ़ीशियेन्सी तो उस दिन मैं पूरी मानूंगा और मुकम्मिल एफ़ीयशिन्सी उस दिन होगी जब माननीय सदस्य वहां से उठ कर इस तरफ़ बैठ जायेंगे....

श्री भैरोंसिंह : और आप सब लोगों को इधर पार कर दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तो ५ साहबान इधर तशरीफ़ लाये हैं, इतनी तो एफ़ीशियेन्सी मान ली। आप आयेंगे तो हमारी मुकम्मिल एफ़ीशियेन्सी हो जायेगी।

(विराम)

यह श्रीमन् पेज नं० ९ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १९६२-६३ में टोटल नॉन-टैक्स रेवेन्यू २२ करोड़ २९ लाख १६ हज़ार थी और वह १९६३-६४ में २८ करोड़ १८ लाख ४२ हज़ार थी।..

श्री भैरोंसिंह : इस अमाउन्ट में ग्रान्ट-इन-एड का अमाउन्ट जो शामिल है वह बाहर निकाल कर बताइये।

श्री **बालकृष्ण कौल** : वह सब निकालकर दिखा रहा हूं।

ख़ैर, श्रीमन्, यह एफ़िशियेन्सी की बात यहां कही गयी थी उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया। एक इसी एफ़ीशियेन्सी के मामले में माननीय सदस्य ने और विचार रक्खा और वह यह कि शायद उनका चार्ज अब नहीं होगा, क्योंकि सरचार्ज में घटाई हो गई है कि मैं और किन्हीं १०-२० चीज़ों में रूल्स के अन्दर टैक्स लगा दूं तो उसका कोई एतराज नहीं करेंगे माननीय सदस्य, क्योंकि यह अधिकार उन्होंने मुझको दिया है....

श्री भैरोंसिंह : सदन ने नहीं दिया।

श्री **बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्य ने दे दिया।

जो कुछ उन्होंने कहा उस पर एतबार करूं तो जितना मुझे नुक़सान हुआ है इस सरचार्ज में तरमीम करने के लिए वह मैं पूरा करलूं इसके लिए माननीय सदस्य तैयार हैं। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं किसी तरह से भी टैक्स लगाकर या सेल्स टैक्स बढ़ाकर इस घाटे को पूरा कर लूं....

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने एश्योरेन्स दिया उसको पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। बशर्ते कि जो ३५ लाख रुपये का विथड्रा आपने सरचार्ज में किया है मैं जिन चीज़ों के ऊपर कहूं —उन पर वह टैक्स लगायें और मैं जिसके लिए कहूं उसमें ख़र्च में कमी कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन् , यह मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इतनी थोड़ी और तकलीफ़ करें कि वहां से उठकर यहां आ जायें तो मैं उनकी बात मान लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे थोड़ी देर के लिए जाने पर अगर वे मेरी डिमान्ड को मन्ज़र करते हैं तो मैं अभी जाने को तैयार हूं।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : वहां पर जो बैठे हुए हैं वे भी मांग कर रहे हैं उनकी बात तो मन्जूर कर लें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप उसको हटाना चाहते हैं तो लास्ट ईयर से उसको इम्प्लीमेन्ट करके जो सरचार्ज काश्तकारों से वसूल किया गया है उसको रिफ़ण्ड कर दिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : पिछले साल का कोई सवाल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप उधर वालों की बात तो मानते ही नहीं हैं फिर इधरवालों की क्या मानेंगे ?

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : जो सरकार की मन्शा थी उसके खिलाफ़ जो किसानों से वसूल किया गया है तो उसको वसूल करने का क्या आधार था ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो लॉ था उस वक्त और कोई वसूली गलत की गई है तो वह जरूर वापिस होगी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अनाज पर सेल्स टैक्स लगा रखा है और आपने कहा है कि सेल्स टैक्स में लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हो गया है ९८ लाख, तो फिर नाज पर जो सेल्स टैक्स है उसको क्यों नहीं हटाते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे खबर नहीं है कि किस मद में आया है।

श्रीमान्, अब एक बात जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उन्होंने यह कही कि १४ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर यह चीज़ एक करोड़ रुपये की हो गई है। श्रीमान् मैंने कोशिश की जानने की वे १४ कौनसी चीज़ें हैं और उनसे क्या मिनिमम टैक्स आ सकता है और क्या-क्या उस पर टैक्स लगाया गया है, तो मैं इतना कह देता हूं कि जहां भी कोई नोटिफिकेशन निकला तो अधिकतर उन चीज़ों के लिए निकला है कि जहां हमको प्लानिंग करना था सेल्स टैक्स के इवेजन को। इसलिये कि जहां सेन्ट्रल टैक्स हैं, वह इवेड हो रहा था उस सैन्ट्रल टैक्स के इवेजन को रोकने के लिए वहां हमने परचेज़ टैक्स का लफ्ज़ निकाला है। टैक्स की रेट को कोई नहीं बढ़ाया है। इस तरीके से अपने टैक्स की चोरी को रोकने के लिये यह प्लानिंग किया गया है। इसलिये, श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी कोई स्टेटमैन्ट दें, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूं।

श्री भैरोंसिंह : १४ जो आइटम्स थे जिन पर कि आपने टैक्स लगाया है वह कौन कौन से थे उसको क्लियर कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं। इसी तरह से हाइड्स एण्ड स्किन्स पिकोक फ़ैदर, काटन यार्न, गुड़ एनीमल बोन्स इनको सिर्फ़ इसलिए किया है कि जो टैक्स इवेड हो रहा था उसको प्लग करदें।

श्री भैरोंसिंह : कोटन यार्न पर कोई टैक्स नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : जिन पर लगा दिया उनको वापिस मिलेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : उस पर भी आऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जादू के पिटारे में से निकलेगा धीरे-धीरे।

श्री भैरोंसिंह : पिकोक फैदर्स पर कोई टैक्स नहीं था।

श्री बालकृष्ण कौल : देखिये साहब, उस पर सैन्ट्रल सेल्स टैक्स था, पर्चेज़ टैक्स नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : अपने यहां पर नहीं था।

श्री बालकृष्ण कौल : अपने यहां का और बाहर का सवाल नहीं है। जो इवेड होता था सेल्स टैक्स, उस चीज़ को बचाने के ख़ातिर टैक्स लगाया है। रेट नहीं बढ़ाया है। इस तरह से अडैप्ट किया था। कई चीज़ें और हैं।

कई माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब पिछली दफ़ा फ़ाइनेन्स बिल आया तो कैजुअल ट्रेडर्स को भी डीलर माना है। इसी तरह से कुछ कैजुअल डीलर्स यहां से चीज़ें ले जाते थे और हमारा टैक्स इवेड होता था, उस चीज़ को रोकने के ख़ातिर हमने टैक्स की मदों में उसका ज़िक्र कर दिया, यह जीरा, धनिया, मेथी दाना, and so on.

श्री दलपतसिंह : जीरा और धनिये पर क्या किया ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनको कैजुअल ट्रेडर्स के दायरे में नोटिफ़ाई कर दिया।

श्री दलपतसिंह : किसानों पर किस कारण से लगा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो भी चीज़ लगी है ग़लत लगी है।

श्री भैरोंसिंह : कैजुअल ट्रेडर्स का टर्न ओवर फ़िक्स अप किया है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह होता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : होता नहीं तो मारे गये।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिए मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह से जीरा, धनिया पर आबू रोड से जाते समय टैक्स लिया गया है तो वापिस रिफ़ण्ड कर दिया जायगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : किस से ?

श्री दलपतसिंह : काश्तकारों से।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि अगर किसी काश्तकार से क़ानून के ख़िलाफ़ टैक्स लिया गया है तो वापिस होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इस क़िस्म के टैक्स हैं जिन पर टैक्स लगा हुआ था, लेकिन उनका क्लैरिफ़िकेशन नहीं था जैसे एक्स-रे इक्विपमेन्ट फ़ोटोग्राफ़ी का सामान तो उनको नोटिफ़ाई किया। क्लैरिफ़िकेशन की जो चीज थीं उनको क्लैरिफ़ाई किया गया है। इस तरह से जो नोटिफ़िकेशन हैं, वे इन मदों के हैं। यह कह देना कि नई चीज़ लगाई है, नई चीज़ों का ख़ास तौर से कहा है तो यह मुबालग़ा हो सकता है ऐग्ज़ेजरेशन हो सकता है।

(श्री बालकृष्ण कौल)
इतनी चीज़ों से एक करोड़ का नफ़ा हो जाय यह भी मैं समझता हूं कि एक ऐग्जेजरेटेट स्टेटमेन्ट होगा।

श्री **भैरोंसिंह** : कितना हुआ?

श्री **बालकृष्ण कौल** : हो सकता है कि १०-१५ लाख हो। मैं नहीं कह सकता क्यों कि अलग अलग चीजें नहीं रखी जाती हैं।

लेकिन यह मानना आपको नहीं चाहिये कि डिपार्टमेन्ट ने पहिले से तत्परता नहीं दिखाई, मेहनत नहीं की। यह नहीं समझिये कि यह चीज़ ख़त्म हो गई। मुझे पूरी तरह से सैटिस्फ़ैक्शन नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, लेकिन जो उन्होंने किया है वह तो प्रसंशनीय है। इतना मानना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य भी मेरे साथ इत्तिफ़ाक करेंगे।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : बक़ायात कितनी है एक्साइज़ में?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : माननीय मुख्य मन्त्री की तरह आप भी छूट की घोषणा करें ताकि लोग तालियां बजादें। अनाज के ऊपर जो टैक्स है उसकी छूट की घोषणा करें।

श्री **बालकृष्ण कौल** : वह तो आप पर लगता है। वह किसान पर लगता ही नहीं है। किसान अनाज ख़ुद पैदा करता है और ख़ुद खाता है।

श्री **नाथूलाल करोल** (चाकसू) : व्यापारी जब ख़रीदता है तो वह टैक्स का हिसाब लगाकर ग़ल्ला ख़रीदेगा। वह किसान पर पड़ता है। वह किसान से सस्ता लेता है उस हिसाब से। मैं स्वयं किसान हूं और रोज लाता हूं और बेचता हूं।

श्री **बालकृष्ण कौल** : आप जैसे किसानों पर तो लगना चाहिये। छोटे किसानों पर नहीं लग रहा है। आप जैसे किसानों पर लग सकता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : देखिये कितने दुबले-पतले आदमी हैं?

श्री **नाथूराम करोल** : मैं कोई बड़ा किसान नहीं हूं, छोटा ही हूं।

श्री **बालकृष्ण कौल** : मैं दुआ करता हूं कि आप बड़े हो जायें, बड़ों के साथ बैठते हैं।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : ये बहुत बड़े हैं, आपको धोखा देते हैं।

श्री **बालकृष्ण कौल** : श्रीमान्, मैं एक बात और अर्ज़ कर देना चाहता हूं। यहां हमारे कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जिनको किसी तांगे में बदबू आती है और कुछ शराब में बदबू आती है।....

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : शराब में तो बदबू सबको आती है, आपको नहीं आती है, ऊंचे दर्जे की है वहां कम आती है।

श्री **बालकृष्ण कौल** : यह तजुर्बे की बात कह रहे हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : बिल्कुल बराबरी का तजुर्बा है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : कहते हैं साथ में किया, बराबरी का तजुर्बा किया....

श्री बालकृष्ण कौल : यह क्लेरिफ़िकेशन है या पौइन्ट ऑफ़ ऑर्डर है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ़ इनफ़ार्मेशन है ।

श्री बालकृष्ण कौल : तांगें में बदबू जिनको आती है । मुझे यक़ीन है· · · ·

श्री विजयसिंह झाला : यह तांगा और बदबू क्या है, जरा समझाइये कि कौनसी बदबू है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे बोलने दीजिये । जिन माननीय सदस्यों को तांगें में बदबू आई, मुझे यक़ीन है माननीय सदस्यों को स्वयं से यह बदबू आई या बदबू के वातावरण से बदबू आई· · · ·

श्री विजयसिंह झाला : यह बदबू पर भाषण हो रहा है या बजट पर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहां बदबू और कहां तांगा ? इन दोनों का क्या सम्बन्ध है ?

श्री विजयसिंह झाला : आपको खुद में से बदबू तो नहीं आ रही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस वातावरण से स्वयं को दूर रखें ताकि स्वयं में बदबू न हो ।· · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पहेली क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिनको शराब में बदबू आई· · · ·

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, दो बज गये और अब तक शुरूआत भी नहीं हुई, कुछ फ़रमावें तो ।

श्री बालकृष्ण कौल : जिनको शराब में बदबू आई उनसे अर्ज़ करूंगा· · · ·

श्री विजयसिंह झाला : आपके पास कोई बदबू का विभाग है क्या ? आप बदबू मन्त्री हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको क्या परेशानी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : अब काफ़ी मिस्मेराइज्ड हो चुके हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, जहां तक सरचार्ज का ताल्लुक़ है· · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, टाइम की घंटी नहीं बजायेंगे क्या ?

श्री मानसिंह महार : यह हम लोगों पर क्यों लागू होती है ? मन्त्री ईर्रिलैवेन्ट बोलें तो उनको भी रोकना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बातें जानना चाहते हैं तो उत्तर में देरी लगेगी ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सबका जबाब देने लगूं तो मेरे पास ६ कापियां भरी हुई हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जवाब दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : ऐसा न करिये शोर्ट कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी ने ६ घंटे की तैयारी की है । मैं समझता हूं मनानीय सदस्यों को एन्टर्टेनमेन्ट सदन के बाहर कहीं नहीं मिलेगा इसलिये आप ६ घंटों तक बैठे रहें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अपने रूल्स में कोरम का प्रोविज़न है उसको रिलैक्स कर दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो आदमियों से भी सदन चल सकेगा, आपसे और इनसे।

श्री अध्यक्ष : ६ में से कितनी किताबें ख़त्म हो चुकी हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : एक किताब से कुछ पन्ने ही गये हैं, लेकिन मैं सब की बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने जिस पृष्ठभूमि में अपना वक्तव्य दिया है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी उनका बयान कर चुके हैं वे उसके लिये बेताब हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरचार्ज का जहां तक ताल्लुक है, मुख्य मन्त्रीजी अपने भाषण में कुछ घोषणा कर चुके हैं। मैं इतना ही अर्ज कर दूं कि जो ७५ रु. से नीचे वाले थे उनको बिल्कुल ही छूट दी गई है और जो ७५ से ऊपर वाले हैं उनको २५ पर्सेन्ट देना होगा और जो २५० से ऊपर के हैं उनको ५० पर्सेन्ट सरचार्ज देना पड़ेगा और मेरा ख्याल यह है····

एक माननीय सदस्य : चाही ज़मीन पर?

श्री बालकृष्ण कौल : चाही में ११३ २२५ रुपयों तक····

श्री विजयसिंह झाला : इसमें मुझे एक इन्फ़ोर्मेशन चाहिये······

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे कहने दीजिये बाद में इन्फ़ोर्मेशन पूछ लेना।

श्री विजयसिंह झाला : एक बात मैं माननीय बदबू मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो सैटलमैन्ट के समय खेत में हिस्से थे उनको तो आपने मान लिया लेकिन, सैटलमेन्ट के बाद भी हिस्से क़ायम हुए हैं सैटलमैन्ट हुए किसी किसी गांव में तो २० वर्ष हो गये हैं। सैटलमैन्ट के बाद में एक-एक प्लाट पर पांच-पांच आदमियों के हिस्से हैं उनको डिवाइड करने के बाद ७५ रु. से ज्यादा होता है उस पर आप सरचार्ज लगाते हैं, सैटलमैन्ट के समय हिस्से हुए हैं, उनको तो आप मानते हैं लेकिन जो सैटलमैन्ट के बाद हिस्से हुए हैं उनको आप मानेंगे या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : जो स्पैसिफ़ाइड शैयर्स हैं सैटलमेन्ट रेकॉर्ड्स में, मसलन तीन आदमियों का नाम है और उसमें लिखा है कि हिस्सा बराबर या पांच आदमियों के हिस्से हैं किसी का वन फ़ोर्थ, किसी का वन फ़िफ्थ या वन सिक्स्थ, इस प्रकार जिन के डिफ़ाइन्ड शेयर्स हैं, उन डिफ़ाइन्ड शेयर्स के मामले में सरचार्ज वसूल करते समय केल्कूलेशन का तरीक़ा यह होगा कि जितना शेअर डिफ़ाइन्ड है रिकार्ड में उसकी कितनी लगान है उतनी लगान को सैपरेट खाते में माना जा सकता है। यदि अन्यत्र उसके पास भूमि न हो तो, सैपरेट खाता मानकर वहां सरचार्ज पेएबल होगा यानी ७५) रु० से बिलो है तो नहीं लिया जायगा ऐबव, है तो लिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : बिलो आयगा उसके सम्बन्ध में और कहना है····

श्री बालकृष्ण कौल : और बादमें पूछ लीजिये ····

श्री भैरोंसिंह : तांगे का नोटिफ़िकेशन इश्यू किया, विथड्रा किया, फिर इश्यू किया फिर विथड्रा किया, यह क्या बात है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्लगिंग हंगिंग का क्या मामला है ?

श्री **बालकृष्ण कौल** : दोनों चीजों से आप वाक़िफ़ हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप दोनों के दोनों वाक़िफ़ हैं, लेकिन सारा हाउस वाक़िफ़ नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने बड़े ज़ोर से कहा था कि सरकार ने क़रीब १० करोड़ रुपये राइट ऑफ़ कर दिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल्कुल ग़लत है। आप मुझे वे आंकड़े दें ताकि मैं अपनी राय बदल सकूं····

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तो कितने रुपये राइट ऑफ़ किये ?

श्री बालकृष्ण कौल : कुछ नहीं किये। छोटे मोटे पुराने स्टेटस के चले आते होंगे, उनको किया होगा तो अलग चीज़ है।

मैं यह कह रहा था कि पुरानी स्टेट्स के चले आते थे और जिनका अकाउन्ट नहीं मिलता है, वे राइट ऑफ़ किये हैं तो नहीं कह सकता····

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : पुरानी स्टेट्स के अलावा किसानों और मज़-दूरों के किये हों तो बताइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि १० करोड़ ९१ लाख, क़रीब ११ करोड़ के राइट ऑफ़ नहीं किये ?

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं किये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको शायद मालूम नहीं होगा कि श्री सिन्हा को स्पेशल ऑफ़िसर मुकर्रर किया था, उन्होंने हर डिपार्टमेन्ट में जाकर पता लगाया। मैं आपको फ़िगर्स दे दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आप मुझे दीजियेगा। मुमकिन है कोई चीज चल रही हो, मेरे पास नहीं आई हो, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप मेरी मदद कीजिये कौनसे आंकड़े हैं मुझे दी जिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आंकड़े में बता दूं क्या ? उन रक़मों का क्या हुआ जो १९६० की जनलेखा समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित हुई हैं ? उन लोगों ने दिवाला निकाल दिया हैं, इसलिये ये रुपये राइट ऑफ़ किये गये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राजस्थान बनने से पहले के हैं, यह तो सब को मालूम है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : राजस्थान होने के बाद के भी हैं, इसमें लिखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : राइट ऑफ़ तो राजस्थान बनने के बाद ही करने पड़े होंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह एतराज उठाया था। उन्होंने कोपआरेटिव बैंक के बारे में कहा कि कोआपरेटिव बैंक में सरकार की जो गारन्टी है उसमें सरकार को बड़ा नुक़सान होने जा रहा है। मैं नहीं कह सकता, कहां से वे आंकड़े लाये। जहां तक मुझे मालूम है, लास्ट रबी में ९५.१६ लाख की रिकवरी की है और फिर खरीफ में हमने १.२५ करोड की रिकवरी की है।

(श्री बालकृष्ण कौल)
और इसी तरह से झुन्झुनू का ज़िक्र किया उन्होंने, वहां से २ लाख की इस फ़रवरी में रिकवरी की और अगर वहां घोटाला है जैसा वे कहते हैं, वह पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसलिये जहां कहीं काम होता है वहां घोटाला हो सकता है, लेकिन सरकार की क्या नीयत है, सरकार की क्या नीति है—उसको देख कर बात करें तो ज्यादा मुनासिब हो· · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आज जादू काम नहीं कर रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं साहब, बहुत सी बातें हैं।

श्रीमन्, तांगे की बात थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : फिर तांगा आ गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं· · · ·

श्री विजयसिंह झाला : यह तांगा है क्या साहब ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तांगा वला क्या है साहब ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, तांगा पहल से एक्ज़ेम्प्टेड आर्टिकल्स की लिस्ट में था। सरकार ने यह सोचा कि इसको एक्ज़ेम्प्शन में से निकाल कर इस पर टैक्स लगाया जाय और उसको टैक्स के एक्ज़ेम्प्शन में से नोटिफ़िकेशन के द्वारा विथड्रा किया। उसके बाद चारों तरफ़ से शोर मचा, डेपूटेशन मिले, तार आये और एसोसियेशन सरकार के पास आई। और उन्होंने अपनी जो दलीलें रखीं, वे मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं।

उन्होंने यह कहा कि जो हमारे यहां, आपने देखा होगा, बहुत सी सूत की मिलें चल रही हैं और कई नई लग रही हैं। उनका कहना यह था कि अगर उसको भी आप टैक्स कर देंगे, तो राजस्थान में सूत की खपत नहीं है, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिये हमको बाहर कम्पीट करना पड़ता है। बाहर की मिलें हैं उनके प्रोड्यूस पर दो पर्सेन्ट का टैक्स है। उन्होंने कहा कि यहां पर हम अगर दो पर्सेन्ट कर देंगे तो क्योंकि हमारी मिलें अभी इन्फ़ैन्सी में चल रही हैं, इसलिये हम बाहर के व्योपारियों का मुक़ाबला नहीं कर सकेंगे। यह दलील सरकार को माकूल मालूम हुई कि जितनी आपकी इस वक्त मिलें हैं उनको चले हुए अभी ज्यादा अर्सा नहीं हुआ। इसलिये जब तक वे मार्केट न बना लें, बाहर से कम्पीट न करने लगें तब तक उनके एक्सपोर्ट के ऊपर ऐसी पाबन्दी लगे एक ऐसे टैक्स से तो मुमकिन है कि इस स्टेट को नुक़सान हो। तो स्टेट ने यह मुनासिब समझा कि वह एग्ज़ेम्प्शन फिर लगा दिया जाय उतने हदतक—यह राजस्थान पर नहीं है, यह एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट पर यह सिर्फ़ छोड़ा गया है। और यह भी किया गया तो अगर माननीय सदस्यों को कोई बदबू आये तो· · · ·

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लगाया क्यों ?

श्री बालकृष्ण कौल : कब ?

श्री भैरोंसिंह : अभी।

श्री बालकृष्ण कौल : अब तो. . . .

श्री भैरोंसिंह : जो ग्राउन्ड बताये थे, जो असर आपके फ़ैसले का पड़ेगा वह अब नहीं पड़ेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें १ पर्सेन्ट लगाया है, दो पर्सेन्ट नहीं लगाया।

तो इस चीज को सदन के सामने रखा, हमारा यह सोचना था, जैसा माननीय सदस्यों से कहा कि टैक्स लगा दिया करते हैं तो बहुत से ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आपको पहले से पता था कि इन्हें बदबू आयेगी।

श्री बालकृष्ण कौल: ख़ैर, जो वस्तु-स्थिति है वह सदन के सामने रखदी। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेन मेन चीजें थीं उनके बारे में मैं ने बताने की कोशिश की, मैं ने आपके सामने रख दीं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इस सदन ने इस बजट को स्वीकार किया और न होते हुए भी कई दलीलें इसके खिलाफ़ पांच दिन तक रखीं और कुल मिला कर दिलचस्पी लेते रहे, उसी तरह आयन्दा भी जो बजट आपके सामने आ रहा है, और डिमान्ड्स आ रही हैं, उन डिमान्ड्स में भी दिलचस्पी लेकर डिमान्ड्स को पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार के प्रातः ८ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बज कर ५५ मिनट पर सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, दिनांक १४ मार्च, १६६४)

१. विधाई कार्य स्तम्भ

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मन्त्री, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६३ को वापस ले लिया।

२. सदन की कार्यवाही से कतिपय शब्दों को निकाले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव २

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया :--

> "दिनांक २ मार्च, १६६४ को श्री मानसिंह महार, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने भाषण में प्रयुक्त ये शब्द "कि डाक्टरों के तबादले आप करते हैं राजस्थान में, वह आप पैसे लेकर करते हैं" तथा इसी प्रकार के शब्द जो कार्यवाही में प्रयुक्त हुए हैं वे, तथा इसी प्रकार ६ मार्च, १६६४ को भी प्रयुक्त हुए हैं वे सब सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जावें।"

स्तम्भ

३. आय-व्ययक १६६४-६५

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद १६

आयव्ययक (बजट), १६६४-६५ पर सामान्य वाद-विवाद का आज अन्तिम दिन था।

सरकार की ओर से मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल ने बहस का उत्तर दिया।

सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १६६४
की कार्य-सूची

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २६-शिक्षा

***शुद्धि-पत्र**

(शुक्रवार, १४ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२	२	[संख्या १	[संख्या १७
१६	१७	**अप्रेतर**	**अग्रेतर**
,,	२८	शार्ट फाल	शोर्टफाल
१७	१०	है हम	है तो हम
,,	२४	नहा करते	नहीं करते
,,	अन्तिम से ४	इकनॉमी	इकोनॉमी
१८	६	सकेंगे। दो	सकेंगे; दो
२०	११	स्ट्रेजी को	स्ट्रेटेजी को
,,	अन्तिम से ३	waste" article	waste article"
२१	१	Behind	"Behind
,,	३	bread men	bread, men
,,	४	thes	these
,,	५	action.	section,
,,	६	survive..	survive,
३७	शीर्ष	(श्री मानकचन्द	(श्री मानिकचन्द
३९	,,	सुराण)	सुराणा)
४५	,,	(श्री मनिकचन्द	(श्री मानिकचन्द
४७	शीर्षक	आयक-व्यय	आय-व्ययक
५६	,,	वा विवाद	वाद-विवाद
८७	१५	श्री **सतीशचद्र**	श्री **सतीशचन्द्र**
९९	प्रथम	**आवाल**	**अग्रवाल**
१२७-१२८	शीर्षक	मार्च	मार्च
१३१-१७१	**नोट :**	इन स्कम्भों में जहां कहीं श्री मोहनलाल सुखाडिया मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया यह पढ़ें :— "श्री मोहनलाल सुखाड़िया"	

१	२	३	४
१४२	अन्तिम से २	श्री योगेन्द्रन थ	श्री योगेन्द्र नाथ
१४४	२४	श्री योगेद्रनाथ	,,
१४५	५–६	Order, Order please	Order ! Order please !!
१६४	अन्तिम से ८	श्रीमोहना्ल	श्री मोहनलाल
१७८	७, ११, २० व २३	श्री माणिकचन्द	श्री मानिकचन्द
१९५	प्रथम	श्री भेरूंसिह	श्री भेरोंसिह
१९६	१३	(तदन्तर	(तदनन्तर
१९७	शीर्षक	—	१९७
,,	३	रस्कम्भ	स्कम्भ
१९८	,,	१९७	१९८

*विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।